असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

06 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा **०६ मार्च, २०१८ ई०**

नवम् सत्र **मंगलवार, तिथि १५ फाल्गुन, १९३९(शक)**

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तरकाल।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हम प्वाइंट ऑफ आर्डर पर हैं ।

अध्यक्ष : अभी शुरू हो जाय तब न प्वाइंट ऑफ आर्डर ? कहां आर्डर बिगड़ रहा है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : प्वाइंट ऑफ आर्डर पर हैं सर । मामला है उप मुख्यमंत्री-वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया और जिस अटैची का उपयोग किया वह अटैची अभी तक वित्त विभाग को मिला नहीं है । हुजूर, सब विधायकों को मिला नहीं है और वह कैसे ले लिये ?

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तरकाल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-7(श्री संजय सरावगी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि 26 जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षकों के सामंजन के पूर्व एक शिक्षकीय विद्यालय की संख्या 4 हजार से अधिक थी एवं दिसम्बर, 2017 तक शिक्षकों के सामंजन के उपरांत एक शिक्षकीय विद्यालय की संख्या 1500 रह गयी है । पुनः विभागीय पत्रांक सं0-28, दिनांक-09.01.18 द्वारा राज्य के सभी प्रखंड, नगर, पंचायत नियोजन इकाई में अवस्थित प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में बेसिक ग्रेड के शिक्षक इकाई सहित शिक्षकों के सामंजन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए आवश्यक निदेश जारी किया गया है ताकि एक शिक्षकीय विद्यालय की संख्या शून्य हो सके ।

श्री संजय सरावगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न को अस्वीकारात्मक कहा और फिर जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि 1500 विद्यालय अभी एक शिक्षकीय विद्यालय है । अध्यक्ष महोदय, इन विद्यालयों की जो स्थिति है एक शिक्षक केवल 1500 विद्यालयों में है और उस एक शिक्षक में 15 दिन तो लग जाता है जो अन्य कार्य है- चाहे छात्रवृत्ति हो,

चाहे पोशाक की राशि हो, चाहे मध्याह्न भोजन हो और उसके बाद सरकार का अलग मतदाता सूची का पुनरीक्षण ये वो - मतलब इन 1500 विद्यालयों में कब तक माननीय मंत्री कम से कम एक शिक्षक मात्र समझ लीजिए, अगर 300 भी विद्यार्थी है एवरेज तो साढ़े 4 लाख प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक कब तक एक शिक्षक मात्र 1500 विद्यालय में हैं और एक मिनट स्थिति बता देते हैं और शहर के जो इर्दगिर्द विद्यालय हैं उसमें फिर एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें एक ही शिक्षक है । सुदूरवर्ती इलाकों में चाहे प्रखंड मुख्यालय है तो वहां भी एक शिक्षकीय विद्यालय नहीं है । सुदूरवर्ती जो इलाके हैं और यहां पोस्टेड हैं- बहुत सारे विद्यालयों में....

अध्यक्ष : पूरक एक ही है ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अरे जवाब होने दीजिए न ।

अध्यक्ष : उनका जवाब सुन लीजिए न ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, प्रश्न के उत्तर में ही हमने स्पष्ट किया है कि विभागीय पत्रांक सं0-28, दिनांक- 09.01.18 को राज्य के सभी प्रखंड, नगर पंचायत नियोजन इकाई को इस बावत निदेश जारी किया गया है विभाग के द्वारा और कहा गया है कि जिस विद्यालय में एक शिक्षक है उनको जिस विद्यालय में ज्यादा शिक्षक है उनको लेकर के वहां के कार्य को बाधित नहीं हो, उसके लिए निदेश जारी किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, अरे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं और धरफराने लगते हैं ।

अध्यक्ष : पूछिए आप ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह निदेश एक साल पहले भी जारी हुआ था और अभी तक 1500 विद्यालय मात्र एक, इसको समयबद्ध सरकार को करना चाहिए और समयबद्ध उसकी घोषणा करनी चाहिए । एक साल पहले...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य संजय जी, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इसमें अलग-अलग स्तर के विद्यालयों में नियोजन इकाइयां अलग-अलग है । नियोजन उनको करना है आप भी जानते हैं, पंचायत को करना है, प्रखंड से होना है उसके लिए तो सरकार ने निदेशित किया है । अब आपकी भावना से सरकार उसको देखेगी, एक समय कहेगी कि उसको जल्द से जल्द कर दीजिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां 15 शिक्षक हैं, 10 शिक्षक हैं, 20 शिक्षक हैं, उसमें से सरकार तत्कालिक रूप से अविलंब इसको गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इसपर कुछ करे । बहुत जगह तो बहुत शिक्षक हैं, कुछ उनमें से निकालकर इन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए । इसीलिए सरकार कब तक इसको करेगी, यह जरूर सरकार को बताना चाहिए ।

अध्यक्ष : आलोक जी, क्या पूछ रहे थे ? वही पूछ रहे थे ।

श्री आलोक कुमार मेहता : जी, सरावगी जी थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं । महोदय, 8 महीने पहले इससे सन्दर्भित निदेश दिया गया था और अभी तक उसका अनुपालन नहीं हो सका किसी भी विद्यालय में और मैं समझता हूँ कि अभी भी जो निदेश दिया गया उसपर परश्यू नहीं किया गया तो रिटायरमेंट के बाद 1500 की संख्या और बढ़ती ही जायेगी । इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सभी विद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था की जाय ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-8(श्री ललित कुमार यादव)

अध्यक्ष : डा0 रामानुज प्रसाद जी पूछेंगे ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुतः योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बैंकों की अपेक्षित भूमिका के निर्वहन नहीं करने के कारण इस योजना का लाभ आवेदकों को नहीं प्राप्त हो रहा है । अतः सरकार के द्वारा इस योजना में बैंकों की भूमिका को समाप्त करते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के गठन की स्वीकृति दी जा चुकी है । दिनांक 13.02.2018 को निगम का गठन भी किया जा चुका है ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक आवेदकों को प्राप्त हो सके तथा लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अगर बैंकों का इतना नकारात्मक रवैय्या है पूरे राज्य में न सिर्फ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मामले में बल्कि बेरोजगार युवाओं के कई हमलोगों के यहां केस आते हैं, बेरोजगार युवाओं को जो ऋण मुहैय्या कराया जाता है रोजगार ऋण, उसमें तो क्या सरकार ऐसे बैंकों को चिन्हित करके काली सूची में डालेगी या सजा देगी या जो इसके लिए जिम्मेवार हो चाहे वह हमारे सिस्टम के लोग जिम्मेवार हो या बैंक, सरकार उसको सजा देने का विचार रखती है ?

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, ये हमारे सात निश्चय के अन्तर्गत जो युवाओं के लिए पांच अवयव निर्धारित किये गये हैं उसमें एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना थी । हमलोगों का लक्ष्य यह रहा है कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है । यदि 12वीं कक्षा के बाद हायर एजुकेशन में जानेवाले छात्र-छात्राओं की कुल संख्या मात्र 13.9 प्रतिशत है । उसको राष्ट्रीय औसत से भी आगे ले जाने का और कम से कम 30 प्रतिशत का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें । हमारे ज्यादा युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें । इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना स्थापित की गयी और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो 218 सभाओं में हमने भाषण दिया होगा और सबसे ज्यादा तालियां बजती थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर, जब इसको एक्सप्लेन करते थे । हमलोगों को यह उम्मीद लगी सरकार बनी और जब हमने इस योजना को मूर्त रूप दिया तो उस समय यह अपेक्षा की जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा छात्र-छात्राएं इसके लिए प्रयास करेंगे और किसी तरह की असुविधा नहीं हो । इसलिए जिला स्तर पर डी0आर0सी0सी0 का गठन किया गया और यह तय किया गया कि अक्टूबर

महीने से यह संचालित हो जाय और जबर्दस्त बाढ़ आने के बावजूद अक्टूबर महीने से वह 2016 में चालू हो गया और छात्र–छात्राओं को प्रेरित करने के लिए पूरा केम्पेन चलाया गया । मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा उसको और स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया और बैंक के साथ जो हमलोगों ने समझौता किया, जो अन्डरस्टेंडिंग हुई उसमें बैंक की इच्छा थी कि भाई हमारे इन्ट्रेस्ट की भी गारंटी होनी चाहिए तो जो मूल धन के साथ साथ इन्ट्रेस्ट यानी 100 रूपये के स्थान पर 160 रूपये की गारंटी राज्य सरकार ने बैंकों को दिया । क्रमशः

टर्न–2/अशोक/06.03.2018

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः और उनके साथ अनेक विमर्श करने के बाद इसको निर्धारित किया गया कि डी.आर.सी.सी. एक–एक चीज को देख लेगा और उसके बाद बैंक को रेफर करेगा, इस प्रकार से किया जाता रहा है लेकिन एक तो आवेदकों की संख्या भी, जो अपेक्षित थी उतनी नहीं हुई है, नम्बर–1 और नम्बर–2 जो आवदेक थे उसमें से भी थोड़ा विलम्ब होता था इसके लिए बैंकों के साथ अनेक बार बातचीत की गई है पिछले डेढ़ वर्षो में । अंततोगतव्या हमने देखा कि भाई ये बैक अगर ऋण देने में देरी कर रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ईशू करने में देर हो रहा है, हालांकि कम लोग भी इच्छुक हैं उसमें देंख रहे हैं हम, तो फिर इसको ज्यादा प्रचारित भी किया गया हैं और लोगों को आश्वस्त किया जा रहा हैं कि आप चिंता मत करें इसके पीछे भावना भी है, हमारे बिहार में आम तौर पर लोग ऋण नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके चलते भी होगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, सरकार तो सब कुछ करा देगी लेकिन फिर भी उसके नाम पर तो एक ऋण रह जायेगा, तो कई प्रकार की उनके मन में जो एक भावनायें हैं उसको लेकर और फिर उसके गार्जियन का भी, वह चाहते थे कई तरह का प्रमाण पत्र, ये सब हमलोगों ने करने की कोशिश की लेकिन जो बैंकों का रवैया है, जितने लोग भी आवेदक थे उसमें भी जितने प्रतिशत वो तेजी से मिलना चाहिये वह हर तरह के प्रयास से ऐसा लगा कि बैंकों का काम करने का अपना तौर तरीका है, उसमें जो हमलोग एक नई चीज, यह पूरे देश में कहीं लागू नहीं है इस प्रकार से सरकार के द्वारा 100 रूपये पर 160 रूपये की गारन्टी देने के बाद भी ऐसा कहीं नहीं है पूरे देश में तो हमलोगों को उम्मीद थी कि बैंकों का रवैया थोड़ा पोजेटिव होगा, थोड़ा उदारता के साथ वह काम करेंगे, वे ऐसा नही कर सके । तो अंततोगतव्या इसकी लगातार समीक्षा करेन के बाद मुझकों यह लगा अब बैंक के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना चलने का कोई तुक नहीं हैं, हम जब 160 परसेंट की गारन्टी दे रहे हैं तो क्यों नहीं अपना वित्त निगम बनाकर हम उसके माध्यम से लोगों को दें पैसा और वह ऋण भी उस तरह से नहीं होगा, बैंक का ऋण भी नहीं होगा और बैंक

के ऋण के लिए जो नियम बने हुये हैं वह भी उन पर लागू नहीं होगा, सरकार देगी और इस बीच में, हमलोगों ने प्रारम्भ में सोचा था, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब 4 लाख रूपये तक का हमलोग प्रावधान कर रहे हैं, जिस तरह की भी पढ़ाई करें, यहां तक कि बी.ए., बी.एस.सी. भी करेगा तो उसके लिए भी ऋण मिल जायेगा । इन सब चीज को देखते हुये भी ऐसा लगा, इसमें ज्यादा लोग नही ले रहे हैं तो शुरू में हमलोगों ने सोचा था कि बाकी जितने प्रकार के स्कालरशिप्स हैं उसकी जगह पर अब यही आ गया तो ज्यादा लाभ मिलेगा इसका लाभ लें जब उसके शुरू के दौर में ही 2016-17 में ही ऐसा लगने लगा कि साहब 2016-17 में तो लागू था छात्रवृत्ति का तो फिर 2017-18 में ही हमलोगों ने यह तय कर दिया कि नहीं चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जन-जाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो यानी जितने प्रकार की छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक है, वह उसी प्रकार से बरकरार रहेगा, उसको भी चालू कर दिया कि कहीं ऐसा न हो कि जो हम छात्रवृत्ति देते थे उसमें किसी तरह का व्यवधान आ जाय तो वह भी कर दिया गया अब लोगों को जो छात्रवृत्ति की योजना पोस्ट मैट्रिक है, वह भी लागू है और जहां तक स्टूडेंट क्रेडिट लेकर पढ़ना चाहेंगे, अभिवावकों के गरीबी के कारण अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, यह तो सच है ऐसी स्थिति में अब शिक्षा वित्त निगम का गठन कर दिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष से वह चालू हो जायेगा और उसी तरह से डी.आर.सी.सी. के माध्यम से वहां जायेगा वह बैंक को नहीं देंगे, अब जितना बैंक के साथ हो गया उनके साथ जो समझौता हुआ है वह अपनी जगह पर जारी रहेगा, जितने लोगों ने ले लिया वह सब उसी तरह चलेगा लेकिन आगे से अब यह जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना है वह अब अपने राज्य सरकार के शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से इसको लागू किया जायेगा, इसमें बैंक की कोई भूमिका नहीं होगी और राज्य सरकार खुद मदद करेगी और अगर जब उसको माफ करना होगा तो माफ भी कर सकती है इसलिए वैसी स्थिति में वैसा लगता है कि इसके बाद अब ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पायेंगे और साथ-साथ इसका प्रचार भी किया जा रहा है । डी.आर.सी.सी. जो सेन्टर है जिला में आप सब लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आप देखियेगा कि इसको लेकर भी लोगों को एक्लेमेटाईज करने के लिए और लोगों को इस बारे में पूरी जानाकरी देने के लिए लोगों को बुलाया भी जाता है और अपनी तरफ से भी प्रयास होता हैं कि स्कूल में, कॉलेज में सब जगह जाकर इसकी जानकारी दी जाय कि इसका लाभ आप उठा सकते हैं तो यह किया जा रहा है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-9(श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1: स्वीकारात्मक हैं ।

खंड–2 : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। इन्टमिडियेट वार्षिक परीक्षा 2017 में सम्मलित हुये परीक्षार्थियों की संख्या 12 लाख 58 हजार 684 है । इन्टमिडियेट वार्षिक परीक्षा 2017 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 4 लाख 52 हजार 237 है । इन्टमिडियेट वार्षिक परीक्षा 2017 में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या–7 लाख 84 हजार 121 है ।

खंड–3 : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । इन्टरमिडियट कम्पार्टमेंटल–सह– विशेष परीक्षा, 2017 में सम्मलित परीक्षार्थियों की संख्या 2 लाख एक हजार 737 है । इन्टरमिडियट कम्पार्टमेंटल–सह–विशेष परीक्षा, 2017 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1 लाख 43 हजार 132 हैं । इन्टरमिडियट कम्पार्टमेंटल–सह– विशेष परीक्षा, 2017 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 51 हजार 554 है ।

खंड–4 : निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संकल्प संख्या–51 दिनांक–25.01.2018 के द्वारा इन्टरमिडियट स्तर के विद्यालयों में अंग्रजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र के विषय के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार बतलायेगी कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्लस टू विद्यालय कॉलेज में कितनी सीटें अभी हैं तथा ग्रौस इनरॉलमेंट के 30 प्रतिशत किये जाने हेतु किस–किस विद्यालय, कॉलेज के स्तर पर कितने सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव हैं और किस प्रकार से ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने विस्तार से जो प्रश्न इनका है उसका उत्तर हमने दिया है महोदय, लेकिन माननीय सदस्य....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य समीर जी, आपका मूल रूप से प्रश्न इन्टरमिडियट से रिलेटेड है, आप इसमें प्राथमिक और मध्य विद्यालय वाला कहां से जोड़ दिये ?

श्री समीर कुमार महासेठ : इसका कारण है सर, कि जब अखबार में निकल रहा हैं कि 6 लाख से एबभ कहां है? क्या सरकार कॉसलिंग करा रही हैं ? क्या सरकार के मन में यह बात आनी चाहिए कि जब इतने बच्चे, इतने परीक्षार्थी कड़ाई होने के बाद फिर परीक्षा में नहीं हैं तो क्या सरकार कौंसलिंग कराकर सरकार पता लगायेगी कि आखिर ऐसे बच्चें कहां हैं ? क्यों नहीं फिर दुबारा एगजाम दे रहा है ? तो यह प्रश्न बड़ा भयावह है, लेकिन इसको उस रूप में नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट उससे पहले वाले प्रश्न से इससे भी कोरिलेट कर दिया, एक तरफ एडुकेशन हमको बढ़ाना है दूसरा अगर परीक्षा में कड़ाई कर दिये जाने के फलस्वरूप इन्टर में 8 लाख 2 हजार विद्यार्थी फेल हो गये और हतोत्साहित होकर के 6 लाख विद्यार्थियों द्वारा जो फार्म नहीं भरा गया तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि

हतोत्साहित हो जाने वाले ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित कर के उनमें जागरूकता पैदा कर सरकार कबतक उनको शिक्षा के मुख्य धारा में लाकर परीक्षा दिलाने का विचार रखती हैं और किस तरीके से ? इसलिए हमने कॉसलिंग की बात की ।

अध्यक्ष : माने आप, आपके प्रश्न में ही है कि सरकार ने उनको दोबारा चांस दिया जिसमें दो लाख परीक्षार्थी ने फार्म भरा कम्पार्टमेंटल से,

श्री समीर कुमार महासेठः जी, जी ।

अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि जिन 6 लाख विद्यार्थियों ने फार्म नहीं भरा, उनकी कौसलिंग के लिये ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी । कैसे होगा, चूंकि हमारा बिहार का भविष्य, अगर परीक्षा नहीं दे पा रहा है कड़ाई होने पर तो कहां पर, कल तो शिक्षा पर, बजट पर इतनी चर्चा हो रही थी ।

अध्यक्ष : समीर जी, सरकार देखेंगी ही और सदन के सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने इलाके में जो संबंधित इस कैटोगरी के छात्र हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिये कि सब लोंग इसमें सम्मलित होइये और पास करिये । और अगला प्रश्न भी आप ही का है ।

टर्न-3/ज्योति/06-03-2018

अल्पसूचित प्रश्न संख्या 10(श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है । गांगेय डॉल्फिन को बिहार राज्य की पहल पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जन्तु घोषित किया गया है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । तत्कालीन योजना आयोग , भारत सरकार द्वारा नेशनल डौल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए 28.06 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी । पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तटस्थ भूखण्ड का चयन नेशनल डौल्फिन रिसर्च सेंटर के निर्माण के लिए किया गया । पटना विश्वविद्यालय से उक्त भूखण्ड के हंस्तातरण का मामला लंबित रहने के कारण रिसर्च सेंटर का निर्माण नहीं किया जा सका है ।

3- पटना विश्वविद्यालय को भूखण्ड हंस्तातरण का मामला शीघ्र निष्पादित कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, जब 2009 में ही हमको पैसा मिला और अभी चल रहा है 2018 तो निश्चित तौर पर सरकार कबतक सेंटर निर्माण में आ रही बाधा को दूर कर रिसर्च सेंटर का निर्माण करा लेगी ?

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव जो घोषित किया गया है ये मेरे प्रस्ताव पर हुआ है । जो गंगा रीवर बेसिन औथरिटी प्रधान

मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित हुई तो तत्कालीन प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसके एक सदस्य के रुप में बिहार के मुख्यमंत्री के रुप में, मैं उस बैठक में शामिल था और उसी में मैंने सुझाव दिया कि भाई जैसे जंगल के बारे में आप जानते हैं बाघ कितना है इससे पता चलता है कि जंगल का स्तर क्या है, उसी तरह से गंगा नदी का जो स्तर है, उसकी जो अविरलता है, उसकी जो निर्मलता है उसकी जानकारी मिलेगी डॉल्फिन की संख्या से और डॉल्फिन की संख्या घटती चली जा रही है तो वैसी स्थिति में इसको राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया जाय और जल जीवन घोषित कर इसकी कुछ सुरक्षा की जाय और इसके लिए पहल की जाय तो अन्ततोगत्वा केन्द्र सरकार ने उस समय स्वीकार किया और उस समय इसको घोषित किया गया राष्ट्रीय जल जीव और इसके बाद इसके लिए रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए हमलोगों ने पहल की तो रिसर्च सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति मिल गयी और उस समय हमने ये तय किया कि यह सर्वश्रेष्ठ होगा कि पटना विश्वविद्यालय में किया जाय और आप जानते हैं कि इस मामले में एक जो हमारे डा0 प्रौफेसर आर.के.सिन्हा हैं जो अभी नालन्दा ओपेन यूनिवर्सिटी के वायस चांसलर हैं, उनको लोग कहा करते थे डौल्फिन सिन्हा । वे भी एक सदस्य थे वहॉ जो मौजूद थे उस मीटिंग जिसकी मैंने चर्चा की, गंगा रिवर बेसिन औथरिटी की मीटिंग की चर्चा की । जब यह हो गया तो उसी विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय में हमलोगो की इच्छा थी पटना विश्वविद्यालय में अगर यह रिसर्च सेंटर इशटैब्लिश होगा तो ठीक ढंग से डाल्फिन के हर आस्पेक्ट पर रिसर्च किया जायेगा, काम किया जायेगा क्योंकि वहीं उसके सबसे जानकार व्यक्ति हैं लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में क्या हुआ । हर लेबल पर बहुत ही प्रयास किया । मैंने व्यक्तिगत रुप से भी कितनी बार चर्चा की, बात की होगी लेकिन पटना विश्वविद्यालय में पता नहीं क्या हुआ कि उनलोगों ने इसको कहा कि हम नहीं देंगे । वहीं जमीन देने की बात थी और यह रिसर्च सेंटर था । ऐसा कई यूनिविसिटी में इसतरह के रिसर्च सेंटर बने हैं । इसके लिए फिर अंतिम तौर पर बातचीत हुई और फिर उनसे आग्रह किया गया है पटना यूनिवर्सिटी के वायस चांसलर को कि आप अपने पहले का जो स्टैण्ड है, उसको बदलिये और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को पटना यूनिवर्सिटी में उसके लिए जो आईडेन्टिफाई कर लिया गया था जगह, वहॉ पर उसकी आप सहमति प्रदान करें और इसका इंतजार किया जा रहा है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है अगर पटना विश्वविद्यालय फिर से जो प्रयास किया जा रहा है इससे सहमत नहीं होगा तो हमने एक मीटिंग में स्पष्ट तौर पर कहा है, तब इसको पटना के वजाय हम भागलपुर में हम शिफ्ट करेंगे और वहॉ रिसर्च सेंटर को इशटैब्लिश करेंगे लेकिन अंतिम प्रयास किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे । प्रश्न संख्या 421 , श्री कुमार सर्वजीत ।

श्री जीवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक अल्प सूचित प्रश्न रह गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न था लेकिन समय ही समाप्त हो गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या 421(श्री कुमार सर्वजीत)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के बाहर अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए निर्गत कुल 6 चेक से मो0 9 लाख 63 हजार 250 रुपये की जगह क्लोन कर फर्जी तरीके से मो0 2 करोड़ 37 लाख 77 हजार की निकासी की गयी है । जिला पदाधिकारी, गया के आदेश ज्ञापॉक 9559 गो0 गया दिनॉक 22-12-2017 द्वारा उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में टीम गठित कर जॉच करायी गयी जिसका जॉच प्रतिवेदन जिला स्तर पर दिनॉक 5-3-2018 को प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : आगे की कार्रवाई भी होगी रिपोर्ट के आधार पर, वह भी बता दीजिये ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : राज्य के बाहर 6 संस्थानों के नाम पर क्लोन चेक के माध्यम से अवैध निकासी का मामला कार्यालय के संज्ञान में आते ही जिला पदाधिकारी, गया के आदेश ज्ञापॉक 9559 गो0 दिनॉक 22-12-2017 द्वारा उप विकास आयुक्त, गया की अध्यक्षता में टीम गठित कर मामले की जॉच करायी गयी । उप विकास आयुक्त, गया के पत्रांक 188 गो0 दिनॉक 05-03-2018 द्वारा गठित जॉच दल का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें कुल 6 चेक से मो0 9 लाख 63 हजार रुपये की जगह क्लोन कर फर्जी तरीके से मो0 2 करोड़ 37 लाख 77 हजार रुपये की अवैध निकासी का मामला सही पाया गया । तदोपरान्त जिला पदाधिकारी,गया के पत्रांक 1948 गो0 दिनॉक 5-3-2018 के आलोक में जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के पत्रांक 456क दिनॉक 5-2-2018 द्वारा श्री मृत्यंजय कुमार सिंह, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गया, मो0 आफताब आलम, प्रधान सहायक, श्री राकेश कुमार रंजन, लिपिक, श्री राजीव रंजन,लिपिक, श्री धीरज कुमार, लिपिक एवं प्रमोद कुमार, नाजीर सभी जिला कल्याण शाखा गया एवं प्रबंधक मुख्य शाखा, एच.डी.एफ.सी. बैंक, गया के विरुद्ध सिविल लाईन्स, थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया जिसका काण्ड संख्या 90/18 दिनॉक 5-3-2018 धारा 406, 409, 420 , 120(बी) भा.द.वि. है । उक्त काण्ड का सिविल लाईन्स थाना द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 422 (श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड में कुल 11401 पेंशनधारी में से 11038 पेंशनधारी का खाता प्राप्त हुआ है जिसमें से 10692 खाता पी.एम.एफ.एस. से वेरीफिकेशन के लिए गया है और दुबारा स्वीकृत किया गया एवं 323 खाता पी.एफ.एम. एस. द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, शेष 23 खाता सत्यापन की प्रक्रिया में है । पी.

एफ.एम.एस. द्वारा सत्यापित खाता में से प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 10476 खाता लौक्ड किया गया जिसमें से 10454 खाता में पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से जून 2017 तक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । माह जुलाई, 2017 से नवम्बर, 2017 तक कुल 10476 पेंशनधारियों के भुगतान की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है । शेष 363 पेंशनधारी का खाता संख्या प्राप्त किया जा रहा है । अस्वीकृत खाता में सुधार किया जा रहा है एवं खाता सत्यापन हेतु पी.एफ.एम.एस. को भेजा गया है तथा भेजे हुए खाता का सत्यापन हेतु पी.एफ.एम.एस. से अनुरोध किया गया है ताकि सभी पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान की कार्रवाई की जा सके ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जाननाा चाहता हूँ कि वृद्धा पेंशनधारियों के खाता को आधार कार्ड से लिंक करने की योजना के अनिवार्यता से पारदर्शिता आयी है लेकिन सिर्फ औन लाईन नाम पर आंकड़ा दिखाया जा रहा है परन्तु प्रखण्ड स्तर पर यह कोई बताने को तैयार नहीं है कि कितने खाताधारियों के खाता से वृद्धा पेंशन की राशि भेजी जा चुकी है । वृद्ध व्यक्ति बैंक खाता के पास बुक लेकर के प्रखंड एवं बैंक का चक्कर लगा रहे हैं तो शेष जो पेंशनधारी का बकाया पेंशन है वह कबतक माननीय मंत्री जी के आदेश पर वहाँ वितरित हो जायेगा मैं यह जानना चाहता हूँ ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, कुल पेंशनधारी 11401 हैं जिसमें से 10454 का खाता, उसमें से हर चीज अप-डू-डेट हो गया है और उसमें पैसा जा भी रहा है, चला भी गया है । मात्र 363 पेंशनधारी का खाता संख्या जो है अस्वीकृत हुआ है जिसका सुधार करने का काम किया जा रहा है ।

टर्न-4/06.3.2018/बिपिन

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: महोदय, जो माननीय मंत्रीजी बता रही हैं, वह गलत आंकड़ा बता रही हैं । यह अपने स्तर से उसकी जांच करा लें और जांच कराकर समय-सीमा निर्धारित कर दें कि जो शेष बकाया है उसका भुगतान कब तक करवा देंगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अच्छा, आप इसके बाद पूछिएगा । भोला जी के बाद महेश्वर जी । अभी भोला जी को पूछने दीजिए न !

श्री भोला यादव: महोदय, पूरे बिहार में किसी भी जिला में किसी भी प्रखंड में, आप आंकड़ा मंगाकर देख लीजिए । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं, आप आंकड़ा मंगाकर देख लीजिए । आप पाइएगा कहीं पर पेंशनधारी को आधा-से-अधिक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आधा-से-कम लोगों को मिल पा रहा है और रही बात जिन लोगों का बाकी है, उनलोगों को मकड़जाल में घुमाया जा रहा है

। जो खाता नंबर दे रहा है उसमें एक डिजिट इधर-से-उधर कर देता है और उसका परिणति यह हो जाता है उस खाताधारी के खाता में पैसा नहीं जा रहा है । मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां सदन में मौजूद हैं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि अविलम्ब पुराने व्यवस्था को लागू किया जाए जिससे कि जो वृद्ध आदमी हैं वह कितना बैंक दौड़ेगा ? दौड़ते-दौड़ते वह वहीं समाप्त हो जाएगा । पुराने सिस्टम को लागू किया जाए ।

अध्यक्षः महेश्वर प्रसाद यादव जी ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादवः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या पूरे बिहार की है इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इसकी कोई अंतिम तिथि निर्धारित हो कि यह पंद्रह दिन में, एक महीना में या दो महीना में राज्य के कुल पेंशनधारियों का खाता जो है वह ठीक हो जाएगा और उनको पेंशन मिलने लगेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

अब एक ही दल के दो-दो आदमी साथ खड़े हैं । कुल संख्या तीन है और . ..

श्री सत्यदेव रामः महोदय, वृद्धावस्था पेंशन में सबसे जो बड़ी समस्या आई है कि उसको अगर कोई उपभोक्ता पता लगाना चाहता है कि हमारा पेंशन किन कारणों से रूका है तो कोई बताने वाला नहीं है महोदय । मैं खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर जिला समाहर्त्ता तक, बैंक मैनेजर, मैं सभी जगहों पर गया लेकिन हमको पता नहीं चल सका कि जितने लोगों का पेंशन रूका हुआ है वह किन कारणों से रूका हुआ है । इस समस्या का समाधान माननीय मंत्रीजी अगर कराएं तो मैं समझता हूं कि उन गरीबों का कल्याण हो सकता है ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो बात सदन में उठी है, यह बिल्कुल जेनुइन है । यह फैक्ट है और हमने खुद भी जो इधर समीक्षा की है तो यह बात ध्यान में आई । कई जगह पर माननीय विधायकों ने जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर समीक्षा बैठकों में यह बात सामने आई और यही नहीं, पूर्व मंत्री और सीनियर सदस्य हैं हमारे पार्टी के, नरेन्द्र नारायण यादव जी ने एक दिन आकर मुझको बताया कि जो बैंक का खाता खुल गया है, इसके बाद कोई नीचे के स्तर पर ग्राहक बैंक का खाता खुल गया है लेकिन गांव में कई जगह पर ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बैंक का आदान-प्रदान होता है । तो वहां पर भी लोगों के साथ धांधली हो रही है । यदि वह अनपढ़ है, उसको मालूम नहीं है, एकाउन्ट में पैसा आ गया पूरा और उसको बताता है कि आपका पूरा पैसा नहीं आया है और दस्तखत करा लिया और रख लिया तो उसमें भी यह घपलेबाजी का काम शुरू है। यह बात जब मेरे ध्यान में लाई गई तो तत्काल हमने इसके बारे में कार्रवाई

करने का निर्देश दिया और कहा कि इसको पूरा मोनिटर कीजिए और जब हम इस समीक्षा यात्रा के दौरान माननीय विधायकों की बात सुनते थे अलग-अलग जिलों में, तो यह बात लगी कि इसमें कुछ मामला है । तो हमने फिर इसकी बड़ी गहन समीक्षा की कि मामला क्या है ? आखिरकार बैंक एकाउन्ट है और शुरू में ऐसा लगा कि जितने लोगों का बैंक एकाउन्ट नहीं खुल सका या जो व्यक्ति एक्जिस्ट नहीं करता है तो उसका बैंक एकाउन्ट नहीं खुला । तो वैसी स्थिति में तो उतने ही लोगों को नहीं मिलना चाहिए था । यह क्या मामला है जो चारों तरफ से शिकायत आ रही है कि बहुत लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है । जब इसकी गहन समीक्षा की तो एक बात सामने आई कि केंद्र सरकार की स्कीम है और वहां से लिमिट लगा दिया गया है कि 29 लाख लोगों को ही दिया जाएगा। अब राज्य के सामने यह प्रस्ताव लाना चाहिए था कि हमारे यहां कुल संख्या 55-56-57 लाख के करीब है तो उनको मिलना चाहिए तो जितना पैसा है वही खंड-खंड में उसको मिल रहा है। तो यह बात जब सामने आई तो मेरे सामने स्थिति स्पष्ट हो गई तो मैंने तत्काल निर्देश दिया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहब, बजट का एप्रूवल कैबिनेट से हो चुका था । हमने कहा कि अभी उसको रोकिए और आकर के फिर हमने समीक्षा करके यह कहा कि बाकी के लिए जो राशि है, राज्य सरकार अपने कोष से आबंटित करेगी और वही किया गया और आप अभी थर्ड सप्लीमेंट्री पर चर्चा करेंगे तो उसमें देख लेंगे । आकस्मिकता निधि से निकाल करके पैसे का आबंटन किया गया है और थर्ड सप्लीमेंट्री में वर्ष 2017-18 के लिए जो और जरूरी राशि है उसका प्रावधान कर दिया गया है और अगले साल के बजट को देख लें, उसमें भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर दिया गया है तो अब मुझको ऐसा लगता है कि इस समस्या का हल हो जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 423 (श्री ललन पासवान)

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री: महोदय, राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अनुसार राज्य सभी 38 जिलों में सरकारी क्षेत्र में एक-एक पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जानी है । उक्त कार्यक्रम के तहत रोहतास जिला के डिहरी-ऑन-सोन में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जा चुकी है । इसलिए महोदय, अभी वहां कोई सरकार का ध्यान नहीं है ।

श्री ललन पासवान : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि हमारा डिहरी से जगन्नाथपुर और नौहट्टा दो प्रखंड जो है, सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन दो प्रखंड है, उग्रवाद प्रभावित है, 120 कि0मी0 की दूरी पर और वहां एक भी कोई कॉलेज नहीं है, इसी सदन में मैंने कहा था । 21पंचायत है । 21 पंचायत में मात्र 11 पंचायतों में हाई स्कूल है । उसमें भी 10+2 नहीं है और शिक्षा

के सवाल पर एकदम सुदूर इलाका है, कहीं से कुछ नहीं है । मैंने मंत्रीजी से आग्रह किया है कि सरकार के नियम के बावजूद भी सरकार अगर थोड़ी-सी नियम को कृपा करके और उग्रवाद प्रभावित है, अनुसूचित जाति का इलाका है, सबसे बड़ी आबादी दलितों-शोषितों की है, उग्रवाद इलाकों में सबसे बड़ा सेंटर रहा है, जब बंदूकों की खेती हुआ करती थी, तो माननीय मंत्रीजी, आप डिहरी में खोले हैं, वहां से 120 कि.मी. की दूरी पर है, कृपा करके एक और खोल दीजिए तो बहुत कृपा होती । इसलिए आग्रह करते हैं कि आप इसमें कोई संशोधन करके एक और अतिरिक्त देने की कृपा करें । 120 कि.मी. की दूरी पर है माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्री ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री: महोदय, वित्त काल में हमलोग जिला को मानक बनाए हुए हैं और प्रत्येक जिला में इंजिनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज हमलोग खोल रहे हैं, इसलिए यह टेक्निकल कॉलेज है और आपका डिहरी से नजदीक है और जिला में बहुत ही करीब वह खुला हुआ है, इसलिए अभी कोई वर्त्तमान में औचित्य नहीं है । हमलोगों की, न कोई सरकार की योजना है कि एक जिला में दूसरा पॉलिटेक्निक खुले ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 424 (श्री जीवेश कुमार)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. निगम के बेड़े में बस उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त मार्ग पर सम्प्रति बस परिचालन विचाराधीन नहीं है ।

श्री जीवेश कुमार : महोदय, दरभंगा जिला में अभी 158 बसें नई खरीदी गई है और दरभंगा जिला के अंतर्गत 10 विधान सभा है । 158 बस अगर खरीदी गई है तो 10 विधान सभा है, सोलह बस तो हमारा ऐसे ही हिस्सा बनता है । हम तो माननीय मंत्री जी से कह रहे हैं कि केवल चार बस दे दीजिए, दो रूट है, एक सबेरे, एक शाम को । चार बस चलवा दीजिए, लोगों को राहत हो जाएगी । दरभंगा जो है वहां मेडिकल कॉलेज है, दरभंगा के अंदर हॉस्पिटल है । देहात क्षेत्र के लोग बीमार पड़ते हैं, दिखाने आने-जाने के लिए भी उनके पास साधन नहीं रहता है । क्रमश:

टर्न : 05 / कृष्ण/ 06.03.2018

श्री जिवेश कुमार (क्रमश:) तो कम-से-कम जनहित में चार बसें - दो सुबह, दो शाम, दोनों रूटों पर फिलहाल काम चल जायेगा । इतना आश्वासन तो देना पड़ेगा ।

सर कोई आश्वासन इसपर नहीं आया ।

अध्यक्ष : कोई आश्वासन नहीं आया तो इसका भी अर्थ होता है न ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 425 (श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में अपीलीय प्राधिकार विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के द्वारा पारित ज्ञापांक 108 दिनांक 27.07.2013 द्वारा श्रीमती आशा प्रसाद, सहायक शिक्षक को प्रधानाध्यपक के पद के योग्यय माना गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी नंबर 604/2014 में पारित न्यायादेश एवं अपीलीय प्राधिकार दिनांक 16.09.2014 को पारित आदेश के अनुपालन में नियुक्ति की प्रक्रिया की गयी है ।

खंड-2 बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नंबर 18391/2010 में पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा ज्ञापांक 2399 दिनांक 14.03.2015 को आदेश निर्गत किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती आशा प्रसाद द्वारा अपीलीय प्राधिकाकर के समक्ष अपील दायर किया गया । दायर अपील में अपीलीय प्राधिकार द्वारा संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पटना द्वारा ज्ञापांक 282 दिनांक 11.02. 2016 को पारित आदेश में श्रीमती आशा प्रसाद को विधिवत प्रधानाध्यपक माना गया है।। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पत्रांक 2548 दिनांक 27.03.2015 द्वारा पत्र दिया है जो अध्यक्षीय निर्णय ज्ञापांक 2399 दिनांक 14.03.2015 पर आधारित था, को अपीलीय प्राधिकार सह संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 281 दिनांक 11.02.2016 द्वारा सर्वथा अनुचित मानते हुये कृष्णनन्दन प्रसाद व अन्य के दावे को निरस्त कर दिया गया है ।

खंड-3 इस खंड का उत्तर उपरोक्त खंड 1 एवं 2 में सन्निहित है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 426 (श्री श्याम रजक)

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 उत्तर अस्वीकारात्मक है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना की स्वीकृति हुई है ।

खंड -2 अमेरिका के सेंट डियागो चिड़ियांघर में गेंडों की वर्तमान संख्या की आधिकारिक सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है । वर्तमान में संजय गांधी जैविक उद्यान में 12 गेंडा उपलब्ध है जो चिड़ियाघर के दृष्टिकोण से यथेष्ट है ।

खंड-3 गेंडा प्रजनन केन्द्र की निविदा प्रक्रियाधीन है जो आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि अभी गेंडा प्रजनन की निविदा प्रक्रियाधीन है । माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री ने 4-5 महीना पहले शिलान्यास किया था और काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है । माननीय मंत्री कह रहे हैं कि इसकी भी जानकारी नहीं है कि सेंट डियागो में गेंडा की वर्तमान संख्या क्या है । तो हम यह बताना चाहते है कि जब 2008 में दिल्ली के इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्डिया कंजर्वेशन ब्रीडिंग इनिशिएटीव की बैठक हुई थी और वहीं इस बात की जिक्र हुई थी कि अमेरिका के सेंट डियागो के बाद सबसे ज्यादा गेंडा बिहार के पटना के संयज गांधी जैविक उद्यान में है और उसी समय यहां प्रजनन केन्द्र स्थापित करने की बात हुई थी । चूंकि दर्शक वहां जाते हैं और गेंडे असहज हो जाते हैं । इसलिये प्रजनन क्रिया नहीं हो पाती है । तो यह तय हुआ था कि यहां प्रजनन क्रिया केन्द्र बनाया जाय । तो जब माननीय मंत्री शिलान्यास कर चुके हैं, उसके बावजूद काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है और कहते हैं कि अभी प्रक्रिया में है तो यह कब तक कराया जायेगा ?

अध्यक्ष : वित्तीय वर्ष 2018-19 में । माननीय मंत्री ने बताया न ।

श्री श्याम रजक : लेकिन शिलान्यास हो गया 6 महीना पहले । तो शिलान्यास का क्या मतलब?

अध्यक्ष : दस दिनों के बाद वित्तीय 2018-19 शुरू होने जा रहा है । माननीय मंत्री जी एक बात से आसन को खुशी है कि माननीय सदस्यों को प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक जीवों के संरक्षण में जो विशेष रूचि जगी है कि डॉल्फिन संरक्षण, गेंडा संरक्षण पर माननीय सदस्यों के प्रश्न आ रहे हैं । इससे आसन को भी खुशी है कि हम प्रकृति में होनेवाले क्षरण एवं अन्य जो उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके प्रति यह सदन सजग है, यह काबिल-ए-तारीफ है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 427 (श्री श्याम रजक)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 अस्वीकारात्मक है । इस संबंध में जिलाधिकारी, पटना तथा पुलिस अधीक्षक, यातायात से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । पटना के न्यू बाईपास में अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाना, नो-इन्ट्री की समयावधि का अनुपालन कराने एवं विभिन्न मार्गों पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिये 2 पुलिस निरीक्षक, 2 रेगुलर मोबाईल, 9 पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक एवं 32 यातायात सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गयी है । जिला परिवहन के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर वाहनों पर अवैध रूप से पार्किंग के लिये मोटर व्हेकिल ऐक्ट की धारा-179 के तहत कार्रवाई की जाती है ।

खंड–2 अस्वीकारात्मक है । न्यू बाईपास अनिसाबाद गोलम्बर से जीरो माईल तक के मार्ग में अवैध रूप से पार्क किये गये भारी वाहनों– ट्रक, ट्रैक्टर आदि हटाने हेतु 3 क्रेन प्रतिनियुक्ति किये गये हैं ।

खंड–3 कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। जिलाधिकारी, पटना तथा पुलिस अधीक्षक, यातायात को इस संबंध में लगातार निगरानी का निर्देश दिया गया है ।

श्री श्याम रजक : महोदय, माननीय मंत्री ने प्रश्न के खंड – 1 के उत्तर में कहा है कि अस्वीकारात्मक है । माननीय मंत्री उसी रास्ते से जाते होंगे । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पूरे सड़क पर अनिसाबाद से लेकर जीरो माईल तक जो ट्रकों का कतार सड़क के साईड में लगा रहता है, गंगा ब्रिज के तरफ से जाने में ट्रकों का कतार लगा रहता है और यह आज से नहीं बल्कि कई महीनों से, कई वर्षों से लगा रहता आ रहा है और माननीय मंत्री कह रहे हैं कि यह अस्वीकारात्मक है । महोदय, उस के कारण सड़कों के साईड में ट्रकों एवं ट्रैक्टरों के कतार में लगे रहने के कारण सड़कें कम चौड़ी हो गयी है ।

अध्यक्ष : मा0सदस्य श्याम जी । हमको लगता है कि आपने जो प्रश्न में पूछा है कि जाम से दुर्घटना बढ़ गयी है । इसे अस्वीकारात्मक बताया है । जाम से तो असुविधा बढ़ती है, दुर्घटना थोड़े बढ़ती है ।

श्री श्याम रजक : प्रश्न का खंड–1 देखा जाय । इसमें लिखा है कि – क्या यह बात सही है कि पटना के न्यू बाईपास पर अनिसाबाद गोलम्बर से जीरा माईल के बीच ट्रकों के अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण से जाम की स्थिति बनी रहती है ।

अध्यक्ष : जिससे दुर्घटनाबढ़ गई है । आपका प्रश्न है ।

श्री श्याम रजक : दुर्घटना तो सेकेंड है । पहला है कि जाम की स्थिति बनी रहती है ।

अध्यक्ष : हमारे यहां है कि खंड –1 में क्या यह बात सही है कि पटना के न्यू बाईपास पर अनिसाबाद गोलम्बर से जीरा माईल के बीच ट्रकों के अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाबढ़ गई है ।

श्री श्याम रजक : दुर्घटना तो हो रही है न सर । प्रतिदिन 9–10 लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन ट्रकों को हटाने के लिये, जो इन्होंने कहा कि पुलिस की पोस्टिंग है, प्रतिनियुक्ति है । सभी माननीय सदस्य उस रास्ते से जाते होंगे, आप भी उस रास्ते से जाते होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि वह जगह क्या क्लीअर रहता है ? जाम रहता है कि नहीं ? प्रतिदिन आपको और माननीय सदस्यों को भी वहां सड़क पर रूकना पड़ता है और जो दुर्घटना होती है तो सड़क जाम होता है और सड़क जाम करके लोग बैठे रहते हैं । तो हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि वहां पर अवैध पार्किक को और अवैध रूप से दुकान खुल गये हैं, वहीं गाड़ियों का मरम्मत

होता है, उन अवैध ट्रकों के पार्किंग को सरकार हटाना चाहती है या नहीं ? दूसरा पूरक प्रश्न यह कि माननीय मंत्री ने कहा कि तीन क्रेन की प्रतिनियुक्ति की गयी है । मात्र एक क्रेन है । हम चुनौती देना चाहते हैं सिर्फ एक ही क्रेन है और वह भी काम नहीं कर रहा है । तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह के जाम को हटाने के लिये और वहां पर पुलिस अगर एकाध रहता है तो वह सिर्फ वहां खड़ा रहता है तो क्या सरकार लोगों पर कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है । महोदय, मैं विस्तार से माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब भी दिया है । माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो सुझाव दिया है, उसकी समीक्षा विभाग में करेंगे ।

क्रमशः

टर्न-6/सत्येन्द्र/6-3-18

श्री श्रवण कुमार,मंत्री(क्रमशः): और समीक्षा के उपरांत इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे लेकिन माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ जनवरी, 2018 में डी0टी0ओ0 के द्वारा कुल 115 वाहनों पर अवैध पार्किंग के लिए कार्रवाई की गयी है और दंडस्वरूप 94,200/- रू0 वसूल किया गया है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यातायात पुलिस द्वारा जनवरी, 2017 से जनवरी, 2018 तक कुल 4,031 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 37 लाख 40 हजार रू0 की वसूली की गयी है महोदय, तो सरकार तो कार्रवाई कर रही है और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसको भी विभाग दिखवायेगा और उस पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा माननीय अध्यक्ष महोदय कि इतने रू0 का फाईन किया गया, ये किया गया । माननीय विधायक जी का प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि उस रास्ते में इतनी गाड़ियां खड़ी रहती है कि अगर एक दिन इनके पदाधिकारी सिर्फ जांच कर देंगे तो जितना ये पूरे साल का खर्चा निकाले हैं, वह एक दिन में अध्यक्ष महोदय वहां पर वसूल किया जा सकता है, वह नहीं कर के, लीपापोती का प्रश्न नहीं है, इस रास्ते में माननीय अध्यक्ष जी मुझे स्मरण है कि आप भी एक बार जहानाबाद के कार्यक्रम में जा रहे थे और आपकी क्या स्थिति थी, आप स्वयं सदन में हैं और इस सदन के मालिक हैं तो माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास जो परिवहन विभाग का वक्तव्य दे रहे हैं, इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इनको भी उसी रास्ते से आना है और माननीय सदस्यों को, हमलोगों को भी उसी रास्ते से आना जाना है, पूरे रास्ते में, सरकार कहती है कि बिहार के किसी कोने से पटना पहुंचने में 6 घंटा लगता है और अब हम 5 घंटा में पहुंचायेगे और हमलोग को माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना से गया जाने में और माननीय संसदीय मंत्री को पटना से नालंदा जाने में 4 घंटा लगता है

।आज ये स्थिति हो गयी है, प्रश्न उससे निजात दिलावाने की है, यह प्रश्न पक्ष और विपक्ष का नहीं है । श्याम जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका मोनेटरिंग कर के इस पर कार्रवाई करवायें ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि इसमें पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है और उसकी मोनेटरिंग कर रहे हैं ट्राफिक विभाग के एस0पी0, जिला प्रशासन कर रही है । कृपया करके यह बतलायें मंत्री जी कि जब लंबी कतार में जो पार्किंग बनी है, माननीय सदस्य श्याम रजक जी ने जो पूछा यह सत्य है और महोदय,यहीं तक नहीं है वह सिटी तक है, वहां तक जाम लगा रहता है टॉल तक और स्थिति से हमलोग समझते हैं, इससे रू ब रू शनिवार रविवार को माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री जी भी होते हैं, चूंकि उसी रास्ते से वे आते जाते हैं और हम भी उसी रास्ते से जाते हैं तो जो पदाधिकारी वहां प्रतिनियुक्त हैं, इसकी जांच करा लें। क्या सरकार उस पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

अध्यक्षः मंत्री जी, आपने जो बतलाया है और जो मूल प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य की भावना है, औरों की भी जो भावना है कि वहां अतिक्रमण रहता है या अवैध पार्किंग के कारण वहां आवागमन में बाधा होती है । वहां आप खाली भी कराते होईयेगा तो फिर लगा लेता होगा इसलिए इसके लगातार अनुश्रवण के हिदायत के साथ निर्देश दीजिये कि उसको देख लेंगे ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या-428(श्री आबिदुर रहमान)

अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या- 429(श्री मुजाहिद आलम)

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः (1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कट ऑफ मार्क्स कम कर के टी0ई0टी0 परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को नियोजन किये जाने के संबंध में अधिकारिक सूचना अप्राप्त है । ग्रेस मार्क्स दिये जाने या कट ऑफ नीचे करने से शिक्षकों की गुणवत्ता यानि शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होगी । साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-21199/2013 एवं संलग्न वादों में दिनांक 31-10-2017 को पारित आदेश के तहत नियोजन नियमावली, 2006 के नियोजन से संबंधित प्रक्रिया नियम-6 को Readdown कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0संख्या-20/2018 दायर किया गया है एवं सर्वोच्च न्यायालय से जैसा निर्देश प्राप्त होगा तदनुरूप कार्रवाई की जायेगी । तत्काल इन कारणों से शिक्षक नियोजन की अग्रेत्तर कार्रवाई करने में विधिक गठिनाई है ।

(3)इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है ।

श्री मुजाहिद आलमः अध्यक्ष महोदय, 2013 में पूरे बिहार में 27 हजार उर्दू बंगला शिक्षकों की रिक्ति के विरूद्ध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्पेशल उर्दू बंगला टी0ई0टी0परीक्षा ली गयी थी जिसमें फर्स्ट पेपर में 13 प्रश्न गलत थे और सकेंड में 10 प्रश्न, पहले रिजल्ट दिया गया उसके बाद जब छात्रों द्वारा आन्दोलन किया गया और पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण श्री मिहिर कुमार झा जो जज थे उन्होंने कहा कि जितने मार्क्स का प्रश्न गलत है उसका 1-1 मार्क्स जोड़कर के फिर रिजल्ट दिया जाय तब 12 हजार छात्रों का जो रिजल्ट निकाला गया 27 हजार के विरूद्ध, उसमें अबतक जो है लगभग 12 हजार शिक्षकों की बहाली हुई है इस कारण शिक्षा के अधिकार के कारण उर्दू बंगला पढ़ने वाले छात्र प्रभावित हो रहे हैं । पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी जी उनसे डिलिगेशन मिला था इस मामले में, उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा जो शिक्षकों की बहाली में कट ऑफ मार्क्स कम कर के बहाली किया गया उस तर्ज पर महाधिवक्ता से. ....

अध्यक्षः पूरक पूछिये न?

श्री मुजाहिद आलमः पूरक पूछ रहा हूँ जिस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा टीचरों की बहाली में ...

अध्यक्षः इसमें तो सरकार ने बताया है कि विधिक कठिनाई है ।

श्री मुजाहिद आलमः विधिक कठिनाई महोदय, इसके लिए महाधिवक्ता से लीगल ओपिनियन भी लिया गया है और उन्होंने कहा है कि इसमें जो है सरकार शिक्षकों की उपलब्धता कम रहने के कारण उसमें कट ऑफ मार्क्स कम कर के बहाली किया जा सकता है । 27 हजार रिक्ति के विरूद्ध अबतक मात्र 12 हजार शिक्षकों की बहाली हुई है और दो कैम्प में, जबकि 4 हजार अभी फ्रेस है और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनमें से चार हजार तीसरे कैम्प की बहाली के है ।

अध्यक्षः हो गया। माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना साफ है, आपने कहा है कि विधिक कठिनाई है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरकार या विभाग द्वारा महाधिवक्ता से एडवोकेट जेनरल से राय ली गयी है तो उस राय को देख लीजिये और उस अनुरूप दिखवा लीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः ठीक है ।

श्री अब्दुल गफूरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री और सरकार का निर्णय है कि प्रत्येक विद्यालय में एक उर्दू शिक्षक की नियुक्ति होगी और उसके विरूद्ध 27 हजार की नियुक्ति होनी थी लेकिन गलत तरीके से प्रश्न पूछने के कारण मात्र 16 हजार विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए और उस 16 हजार में 12 हजार की नियुक्ति हो चुकी है और 4 हजार कुछ की

नियुक्ति होनी बाकी है जो घूम रहे हैं । राजस्थान सरकार में इसी तरह का मामला था तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार अगर उसमें छूट देती है तो नियुक्ति हो सकती है इसके लिए हमलोगों ने...

अध्यक्ष: आप वही प्रश्न दुहरा रहे हैं । अब, इलियास जी ।

श्री मो0 इलियास हुसैन: महोदय, सरकार से इस संबंध में मैं एक खुलासा चाहता हूँ । गंगा यमुनी तहजीब का आधुनिक सृजन साहित्य में उर्दू का आता है । हालात इस देश में, इस राज्य में ये है कि 600-650 स्कूलों में उर्दू बच्चों, उर्दू शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हिन्दी टीचर से करायी जा रही है । अफसोस है जिसको अलीफ तक की जानकारी नहीं है, क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: विभाग से जानकारी प्राप्त कर के माननीय सदस्य को संसूचित कर दिया जायेगा महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी लोग इसी चीज को चाहते होंगे कि बहाली हो और माननीय सदस्य मुजाहिद जी ने कहा है और सरकार ने कहा है कि जो भी महाधिवक्ता की राय आयी होगी उसको देख कर के आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

टर्न-7/मधुप/06.03.2018

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-430 (श्री विजय प्रकाश)</u>

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । जमुई जिला के बरहट प्रखंड के उच्च विद्यालय मलयपुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 112 दिनांक-30.06.2017 द्वारा दी जा चुकी है । जमुई जिले के जमुई प्रखंड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 8 दिनांक-22.04.2010 द्वारा दी जा चुकी है । अत: एक प्रखंड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है । जहाँ तक नूमर प्रखंड में चाँदनी मैदान में स्टेडियम निर्माण का प्रश्न है, के संबंध में स्पष्ट करना है कि नूमर बरहट प्रखंड अन्तर्गत ही आता है जो भवदीय के पत्रांक 74 दिनांक 14.01.2016 से स्पष्ट है ।

महोदय, यहाँ एक स्टेडियम पास कर दिया गया है और इसपर 49 लाख 46 हजार रू0 में 32 लाख राशि आवंटित की जा चुकी है, अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, 22. 04.2010 को ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब तो हो ही रहा है ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं । कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय.....

अध्यक्ष : आपका तो प्रस्ताव कहॉ आया है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : सर, एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । यह मामला है सर कि गैंडा.....

अध्यक्ष : आप तो उस समय कुछ बोले नहीं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, गैंडा, डॉल्फिन का मामला था और चेयर ने काफी सराहा कि माननीय विधायकों की चिन्ता है । लेकिन पता नहीं सरकार को विधायकों की चिन्ता नहीं है, हुजूर । विधायकों की चिन्ता भी होनी चाहिये । जो विधायक सभी मामले को उठाते हैं..

अध्यक्ष : माननीय विधायक भाई वीरेन्द्र जी, जाहिर तौर पर माननीय विधायक गैंडा और डॉल्फिन भी तो नहीं हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं हैं लेकिन मामला तो उठा रहे हैं न ! चेयर के संरक्षण की आवश्यकता है, हुजूर। माननीय विधायकों को जो 1952 से परम्परा रही है, मिलता रहा है उसको लागू करवाइये और जबर्दस्ती लागू करवाइये ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 06 मार्च, 2018 को माननीय सदस्य श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव, श्री अमित कुमार एवं श्री समीर कुमार महासेठ से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मॉग (स्वास्थ्य विभाग) पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर तथा विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 176(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने बड़े ही गम्भीर सवाल को लेकर आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना सरकार को दी थी कि इस राज्य के अन्दर जितना इमरजेंसी में नहीं बंदी थे, उससे ज्यादा अभी बंदी हैं, जो टाईम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया है, रपट आई है, 1 लाख 15 हजार से अधिक शराब के मामले में बंद हैं, वे कमजोर तबके के लोग, दलित-महादलित वर्ग के लोग हैं । (व्यवधान) यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है । सरकार कोई अच्छा पहल की थी कि शराबबंदी कानून लाई थी लेकिन सवाल यह है कि जो कानून में कुछ जटिलता आ जाय जिससे

आम-आवाम और गरीब-गुरबा लोग जिसके घर में कमाने लोग जेल चल जायेंगे तो उनका भरण-पोषण कौन करेगा ? एक छोटा-सा मिसाल है कि देश का उच्च सदन ने तीन तलाक के मामले में भरण-पोषण के सवाल पर बिल रोक दिया । मेरा आसन से आग्रह है.....

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री महबूब आलम ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुये हैं... एक मिनट सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : आप कोई सूचना तो दिये नहीं किसी आग्रह का ? क्या कहना है ? जल्दी बोलिये ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, हमारे विक्रमगंज में हमारे कार्यालय के बगल में एक मिष्टान भंडार है जहाँ गोली चली, उसके बाद मैंने.....

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजियेगा । श्री महबूब आलम ।

शून्यकाल

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, 14 फरवरी, 2018 को बारसोई के अंतर्गत कचना ओ0पी0 प्रभारी द्वारा शराब तस्करी के झूठे इल्जाम में मुन्ना नोनियां की गोली मारकर हत्या कर दी तथा हत्या के खिलाफ थानेदार की बर्खास्तगी तथा 10 लाख मुआवजे की माँग पर 9 घंटे का प्रदर्शन किया गया । सरकार न्यायिक जाँच व मुआवजे की घोषणा करे ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च को भोजपुर के पीरो के रसौली गाँव में महादलित टोले पर संगठित हमला जिसमें रश्मि देवी व परीक्षण देवी बुरी तरह घायल हैं । हमला करने वाले अपराधी रणधीर सिंह समेत तमाम नामजद अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा चीनी मिल में इस वर्ष अभी तक 35 लाख क्विंटल गन्ना का पेराई हो चुका है जिसका भुगतान किसानों को दिनांक 06.03.2018 तक नहीं हो सका है, किसानों को शीघ्र भुगतान करावें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, राज्यकर्मियों हेतु सातवाँ आयोग लागू है परंतु महत्वपूर्ण विधि कार्य करनेवाले ग्राम कचहरी के न्यायमित्रों को न तो मानदेय में बढ़ोत्तरी की गयी और न ही उनके स्थायीकरण की कोई कार्रवाई हुई है ।

अतः न्यायमित्रों के मानदेय में बढ़ोत्तरी एवं उनके स्थायीकरण की माँग करता हूँ।

श्री अत्रि मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिला अन्तर्गत हिलसा नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कानून को ताक पर रखकर योजनाओं को लूटा जा रहा है जिसके कारण हिलसा नगर परिषद नरक परिषद में तब्दील हो चुका है ।

अतः हिलसा नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जॉच निगरानी से कराने की मॉग करता हूँ ।

श्री अमरनाथ गामी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट विधान सभा के बसहा मिर्जापुर पंचायत में होली की रात्रि में गिरधरपुर गॉव में कुछ दबंगों द्वारा मिथलेश सहनी के घर में घुसकर पीट-पीटकर हत्या कर दी और महिलाओं के साथ मारपीट की गयी ।

मैं हत्यारों की गिरफ्तारी एवं परिजनों को 10 लाख मुआवजा की मॉग करता हूँ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत अंचल+थाना-आमस के संतोष कुमार यादव, पिता-सूर्यदेव यादव, ग्राम-मंझौलिया की मृत्यु बिजली की तार गिर जाने से दिनांक-17.11.2017 को हो गई थी, जिसका प्राथमिकी आमस थाना में दर्ज है ।

मृतक के आश्रितों को विद्युत विभाग के आपदा राहत कोष से 4 लाख रूपये मुआवजा की मॉग करता हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण राज्य में बालू के कालाबाजारी के कारण सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यों में भारी परेशानी हो रही है, मजदूरों को काम नहीं मिलने से वे भूखमरी के कगार पर हैं ।

उचित दर पर बालू की उपलब्धता तथा मजदूरों को मजदूरी सुनिश्चित कराने हेतु सरकार से मॉग करता हूँ ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के देवापुर ग्राम में गंडकी नदी के सोता पर पुलिया नहीं रहने के कारण हजारो ग्रामीणों को परेशानी होती है ।

अतः सरकार उक्त पुलिया का निर्माण शीघ्र कराये ।

अध्यक्ष : आप एक मिनट में क्या संज्ञान में लाना चाहते हैं ?

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा-सा ध्यान देते इस मुद्दे पर । हर माननीय सदस्य 243 बिहार विधान सभा सदस्य हैं....

अध्यक्ष : आप अपनी बात न कहिये ! नहीं तो बाउंड्री में ही समय चला जायेगा ।

श्री संजय कुमार सिंह : मैं कहना चाहता हूँ कि हर विधान सभा क्षेत्र में जो भी शहरी कसबा है, सी0सी0टी0वी0 कैमरा यदि विधायक निधि से भी लग जाय तो कम से कम हम अपराध पर कंट्रोल कर सकते हैं । इस मुद्दा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका प्रस्ताव विचारणीय है और इन्होंने मिलकर भी यह बात मुझको बताई तो हमने गृह विभाग के प्रधान सचिव को भी इस संबंध में निर्देश दिया है, योजना एवं विकास मंत्री से भी बात हो गई है ताकि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत इसको शामिल कर लिया जाय ।

टर्न-8/आजाद/06.03.2018

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री श्याम रजक, विनोद प्रसाद यादव एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण सूचना । श्री श्याम रजक एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना । श्री श्याम रजक ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, ''बिहार के अन्य विश्वविद्यालय सहित पटना विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम0एड0) कोर्स के सत्र 2016-17 के पचास सीटों के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा में मात्र दो अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन हुआ क्योंकि अनुसूचित जाति के छात्र न्यूनतम निर्धारित अंक 50 प्रतिशत नहीं प्राप्त कर सके । अनुसूचित जाति के खाली छः सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन कर लिया गया ।

इस परीक्षा में सभी वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए 50 प्रतिशत क्वालिफाईंग मार्क्स लाना अनिवार्य था । आरक्षित वर्गों के छात्रों को क्वालिफाईंग मार्क्स में रियायत नहीं दी गई । क्वालिफाईंग मार्क्स एक समान रखना और खाली आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन कर लिया जाना आरक्षण का घोर उल्लंघन है ।

अतएव बिहार के अन्य विश्वविद्यालय सहित पटना विश्वविद्यालय के एम0एड0 कोर्स की नियमावली में संशोधन कर अनुसूचित जाति सहित सभी आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए क्वालिफाईंग मार्क्स कम करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । ''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में कहना है कि पटना विश्वविद्यालय,पटना द्वारा एम0एड0 में नामांकन हेतु लिये गये प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित

जाति के लिए आरक्षित 8 सीटों में सत्र 2017-18 में 7 सीटों पर नामांकन तथा 2016-17 में दो सीटों पर ही नामांकन हो सका क्योंकि इस कोटि के विद्यार्थियों द्वारा नामांकन हेतु वर्तमान में प्रख्यापित अध्यादेश में निहित निर्धारित क्वालिफिकेशन मार्क्स 50 प्रतिशत प्राप्त नहीं किया जा सका । आरक्षित कोटे के उक्त सीटों के नहीं भरने के कारण नियमानुसार उस पर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन लिया गया । विश्वविद्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार एम0एड0 में नामांकन हेतु क्वालिफिकेशन मार्क्स कम कर 45 प्रतिशत करने तथा आरक्षित कोटे के सीटों के नहीं भरने की स्थिति में कुलपति को क्वालिफाईंग मार्क्स कम करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यादेश में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । शीघ्र ही इस प्रस्ताव को शैक्षणिक परिषद् एवं अन्य प्राधिकारों से पास कराकर अध्यादेश में संशोधन के लिए कुलाधिपति को भेजा जायेगा । महामहिम कुलाधिपति से अनुमोदन के पश्चात् अध्यादेश संशोधित होते ही यह समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव,भोला यादव एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य में बालू की किल्लत से जहाँ विकास कार्य ठप है, वहीं मजदूर व कामगारों के मूल रोजगार खत्म हो जाने से उनके परिवारों पर भूखमरी छा गया है । विगत् वर्ष के अनुपात में खनन एवं भूतत्व विभाग के राजस्व में लगभग 30 प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है । कई जिलों में बालू उठाव के लिए मिलने वाले सरकारी चालान भी सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है । आम जनता को ऊँचे कीमत पर कठिनाई से बालू उपलब्ध हो रहा है ।

अतः मजदूरों के बेरोजगारी, आम जनता को ऊँचे दर पर बालू उपलब्ध होने एवं सरकारी राजस्व में कमी होने की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । ''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, खनन एवं भूतत्व विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए)(2) के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ए)(2) के तहत् सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

टर्न-9/अंजनी/दि0 06.03.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य लिए जायेंगे ।

<u>वित्तीय कार्य</u>

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय अनुपूरक के व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों के मांगों की कुल संख्या-34 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अत: किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटिन यानी मुखबंद द्वारा किया जायेगा । अब मैं मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग को लेता हूँ, जिसपर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
जनता दल(युनाइटेड)	-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	02 मिनट
निर्दलीय	-	03 मिनट

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"स्वास्थ्य विभाग के संबंध में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2017, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2017 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम,2017 के उपबंध के अतिरिक्त 2,23,21,59,000/-(दो अरब तेइस करोड़ एक्कीस लाख उनसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री भोला यादव, श्री चन्द्रशेखर, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं और जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(अनुपस्थित)

श्री भोला यादव, अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

अध्यक्ष : आपको कुछ कहना है इसपर ? कुछ बोल दीजिए ।

श्री भोला यादव : महोदय, अभी जिस वित्तीय वर्ष में हमलोग चल रहे हैं, यह वर्ष 2017-18 है । वैसे तो 39 विभाग का कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है हम विपक्ष के द्वारा लेकिन आपलोगों के द्वारा एक विभाग स्वास्थ्य विभाग को लिया गया है । स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि 120 करोड़ रूपये की लागत से कैंसर अस्पताल का इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बनने की बात पिछले वित्तीय वर्ष में हुई थी, उसकी राशि भी आ गयी थी केन्द्र से लेकिन सरकार पता नहीं, अभी तक शिलान्यास नहीं की है । इस वित्तीय वर्ष में भी जो बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ा है, उसमें फिर उसी बात को दुहराया गया है । यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैसे को लेकर सरकार क्या सिर्फ ब्याज कमाने के लिए पैसा केन्द्र ने भेजा है या इसका उपयोग करने के लिए भेजा है । पूरे राज्य में कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है लेकिन कैंसर का समुचित इलाज यहां अभी उपलब्ध नहीं है । पूरे राज्य के अंतर्गत जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय हैं, उन चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षक का घोर अभाव है । शिक्षक के अभाव में हमारे जो छात्र हैं, वे उचित टेकनिकल शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उस दिशा में शिक्षकों की बहाली नहीं करके केवल उनका उम्र बढ़ाया जा रहा है । आप सोच सकते हैं कि 65 वर्ष की अवस्था वाले शिक्षक क्या पढ़ाते होंगे ? जो खुद

चलने में लाचार हैं, जो खुद बीमार हैं, वे शिक्षा क्या देंगे ? ऐसे लोगों को इसमें लगाया गया है । इतना ही नहीं और भी कई बात हम बताना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जितने भी अस्पताल हैं, उसमें कहीं पर भी जो प्रोपर दवा-दारू होना चाहिए, वह नहीं है । इस संबंध में हम अपने क्षेत्र का एक मिसाल देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

- दारू भी एक दवा है, महोदय । पता नहीं आप लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को पीने वाला दारू ही नजर आता है, दारू भी एक दवा है । महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक करेला में है और उस स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर है लेकिन कई बार इस संबंध में सदन में प्रश्न किया गया लेकिन वह भवन अभी तक बनने के लिए कोई योजना की स्वीकृति सरकार के द्वारा नहीं हुआ है । कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की स्थिति जर्जर है और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी इसमें अपार संभावनायें हैं आपको अपना चेहरा निखारने का लेकिन इसके लिए आपको तत्पर होकर सभी अस्पतालों में डाक्टरों की बहाली करना होगा, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली करना होगा और साथ-ही-साथ ग्रामीण स्तर के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं, एडीशनल पी0एच0सी0 हैं, उसमें डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है । डाक्टरों की बहाली न के बराबर हो रही है और जो हो भी रही है, वह अनुबंध के आधार पर हो रही है । वे बेमन से काम करते हैं डाक्टर लोग और डाक्टर लोगों को बेमन काम करने से हमारे राज्य में रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि कटौती प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया गया है, उसे स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद । आपके 20 मिनट में से 8 मिनट भोला बाबू ले लिए ।

श्री भोला राय : महोदय, आपके आदेश से बोले हैं, पार्टी का समय मैंने बर्बाद नहीं किया है ।

अध्यक्ष : मेरा जो समय है, वही न पार्टियों को दिया जाता है ।

टर्न-10/शंभु/06.03.18

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट 2017-18 पर वाद-विवाद में भाग लेने का जो आपने अवसर दिया- इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद । महोदय, एक कहावत है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली । अध्यक्ष महोदय, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब यह 20-25 दिनों की अवधि बची है, सरकार जब पूर्ण

बजट लाती रही है । जब सरकार लाती है फुल बजट और फुल बजट जब आप लाते हैं इसका मतलब है कि आपका एकाउंटिंग ठीक नहीं है, लेखाजोखा आपका ठीक नहीं है । आपने जनता के सामने जो लेखाजोखा लेकर बजट रखा और फिर आप मांग ला रहे हैं द्वितीय, तृतीय इसका मतलब यह है कि वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है । अभी कल ही माननीय वित्तमंत्री जी अपने बजट भाषण में बोल रहे थे । हमने एक सवाल उठाया था और आज भी उठा रहा हूँ कि पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं । ठीक है स्वास्थ्य विभाग पर आज है, लेकिन इन्कलुडिंग ऑल्स अगर देखा जाय तो पैसा जो हमारा है- मैं बार-बार कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेन्स । मैं कहता हूँ ठीक है मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेन्स कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पूरे राज्य की चौकीदारी नहीं कर सकता, जिस तरह देश की चौकीदारी नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, जो चौकीदार हैं देश के, क्या हुआ चौकीदार भागीदार हो गया, सो गया कि लेकर के बाहर चला जा रहा है । एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जीरो टॉलरेन्स का हमारा कॉन्सेप्ट है तो सिस्टम में जो लूप हॉल्स है, सिस्टम में जो अकर्मण्यता है, अगर उसको ठीक नहीं करते हैं, रेक्टीफाई नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति तो दूर हम इस गरीब राज्य की जनता का सेवा चाहे स्वास्थ्य का महकमा हो या शिक्षा का महकमा हो, किसी का भी महकमा हो सबका हम सामने रखेंगे, रख रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आज यह सरकार जो लेकर आई है- आज 6 तारीख को हम बहस कर रहे हैं और सप्लीमेंटरी पास भी होगा, चूंकि सरकार बहुमत में है तभी सरकार में है । पास होने के बाद महामहिम राज्यपाल जी के यहां अनुमोदन के लिए जायेगा, पांच छः दिनों का समय उसमें लग जायेगा । बाकी के दिनों में आप कैसे इस लगभग 6 हजार करोड़ रूपये सरकार लेकर आयी है सप्लीमेंटरी बजट तो ये जो 5 हजार 6 सौ 3 करोड़ 30 लाख 24 हजार इस राशि का कैसे सामंजन करेंगे आप ? क्या यह पार्क नहीं होगा ? आप पार्क करते रहे हैं जब से आये हैं सत्ता में तो राशियों को पार्क करने का सिलसिला शुरू हुआ और लैप्स नहीं कर जाय तो आप उसको पार्क कर दे रहे हैं । पार्क करके जब उससे भी नहीं मन भरा तो आप उसको एन0जी0ओ0 के खाते में डालकर उसको सृजन और शौचालय घोटाला कराते रहे । सभी विभागों में है पूरे बिहार में है । यह सप्लीमेंटरी बजट जो सरकार लायी है, हम समझते हैं कि सरकार को यह सप्लीमेंटरी बजट नहीं पास करना चाहिए, नहीं इनको पैसा देना चाहिए । सरकार या तो अकर्मण्य है या वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है । अगर है वित्तीय प्रबंधन सही तो 12 महीने का लेखा जोखा सरकार को देना चाहिए तब पैसा मांगना चाहिए कि आपने किस मद में कितनी राशि खर्च की, आपके कितने-कितने परसेंट किसमें खर्च हुए और नहीं खर्च हुए तो क्यों नहीं खर्च हुए । कल महत्वपूर्ण यह जवाब वित्तमंत्री जी दे रहे थे यह रेकार्ड का पार्ट है। 19 हजार करोड़ रूपया बैंकों में पड़े रह गये, विभागों में पड़े रह गये वह लौट नहीं सका और बार-बार सरकार के दिशा निदेश के बाद सरकार के आदेश के बाद भी पैसा नहीं लौटता है तो यह हमारा

सिस्टम कितना फेल्योर है । पहले सरकार 30 दिसम्बर की बात कही थी, अब उसको कहा जा रहा है कि मार्च तक हम लौटवा लेंगे । पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं छात्रवृत्ति का मामला हो, कृषि अनुदान जैसा मामला हो, स्वास्थ्य महकमे का मामला हो तो काहे के लिए सरकार पैसा मांग रही है । क्यों सरकार को पैसा चाहिए? क्यों सप्लीमेंटरी बजट पास किया जाय, यह हम जानना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, सदन यह जानना चाहता है आपके माध्यम से । हम यह कहना चाहते हैं कि जो इस राज्य में हो रहा है, जो हुआ है उसको देखते हुए कहीं से यह सप्लीमेंटरी बजट हमलोगों को पास नहीं करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने यह जो किताब दी है विनियोग का हो या सप्लीमेंटरी का, आप जो कमिटेड एक्सपेंडीचर है- कमिटेड एक्सपेंडीचर पर भी आपका अनुमान सही नहीं है, आपका एकाउंटिंग सही नहीं है, कमिटेड जो आपका एक्सपेंडीचर है उसपर भी आप पैसा मांग रहे हैं सप्लीमेंटरी के माध्यम से । क्या है बजट फोरमेशन हमारा ? वह तो निर्धारित है कि हमारे इस्टेब्लीशमेंट पर इतने खर्च आयेंगे । ठीक है आकस्मिक खर्च बढ़ सकते हैं । कोई आपके राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं उसमें आप शिफ्ट करते रहते हैं इशू को- इशू चेंजर मैनेजर है और इशू चेंज करने में कुछ इशू आपने ला दिया तो उसमें हो सकता है कि खर्च का लेखा जोखा गड़बड़ा सकता है । लेकिन आप इस्टेब्लीशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडीचर पर भी पैसा मांग रहे हैं, यह बड़ा खेदपूर्ण लगता है । यह सरकार का क्या रवैय्या है, सरकार का क्या कामकाज है ? सरकार का अपने सिस्टम पर पकड़ नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इसमें स्वास्थ्य पर सही में हमलोग जब आपने किताब पर लिखवा दिया है तो ये होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी है उसपर भी पैसे मांगे गये हैं और माननीय मुख्यमंत्री के पास वह विभाग है । माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो भिजलेंस है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो होम है । हम इसपर जानना चाहते हैं कि रोज अखबार खोलिये, टी0वी0 वॉच कीजिए और जो हत्या, लूट, फिरौती- फिरौती के लिए पहले होता था अपहरण, लेकिन अब अपहरण करके बच्चे मारे जा रहे हैं- रौशन मारा जा रहा है, शुभम मारा जा रहा है ।

(इस अवसर पर डा0 अशोक कुमार ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

(व्यवधान)

मैं स्वास्थ्य पर भी आऊंगा । आप सप्लीमेंटरी मांग रहे हो और खाली स्वास्थ्य पर सप्लीमेंटरी मांगते तो मैं केवल स्वास्थ्य पर बोलता । स्वास्थ्य पर बोलूंगा उसपर स्ट्रेस करूँगा लेकिन सप्लीमेंटरी सब हमलोग पास करने जा रहे हैं । सभी विषय का पास करने जा रहे हैं । हम यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय, एक और विषय हम रखना चाहते हैं जो इस राज्य के परिस्थिति के अनुकूल जो हमारा है, भौगोलिक जो हमारी स्थिति है और हम इंडस्ट्री में फेल्योर हैं । गये थे अभी गुणगान हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टमंडल लेकर जापान लेकर क्या आये ? क्या मिला, क्या पकौड़ा बनाने वाला औजार लेकर आये, लेकिन नहीं-नहीं मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि जो जवाब मिले हैं वह सदन को बताना चाहिए था

माननीय मुख्यमंत्री जी को, पथ निर्माण मंत्री जी को । सभापति महोदय, मैंने जवाब पढ़ा है । हमलोगों ने भी जिज्ञासावश उसको देखा तो उसमें जवाब मिला है कि अरे भाई हम जो बुद्धा सर्किट में आपके यहां काम करते हैं, जो हम राशि देते हैं । बुद्धा सर्किट में जो सड़कें हम बनाते हैं आप उसको अक्षुण्ण नहीं रख पाते । हमारे लोग जाते हैं गया में मारे जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं गया में उनके साथ छिनतई होता है, हमारे लोग जाते हैं प्रताड़ित होते हैं । हम जो सड़कें बनाते हैं चाहे बुद्धा सर्किट में हो या वैशाली तक डेवलप करें या राजगीर तक डेवलप करें - चलते हैं अपनी बनायी सड़कों पर तो वहां सड़क के किनारे लोग शौच कर रहे होते हैं । आप कागज में ओ0डी0एफ0 कर रहे हो स्वच्छ भारत बना रहे हो तो आखिर सारे विभाग पर मांग रहे हैं तो यह सदन जानना चाहता है कि सरकार की कार्य प्रणाली क्या है ? सरकार के फेल्योर ये हैं तो उपलब्धि के लिए भी सरकार पीठ खुद थपथपा रही है । जापान जाकर भी क्या मिला, जापान गये । ठीक है हमलोग सुने थे एक गाना था कि जाना था जापान हम चीन चले गये तो ठीक है आप जापान ही गये, लेकिन जापान से लेकर के क्या आए । आप जापान से लेकर क्या आये, आप गुणगान कर रहे हैं यह बताना चाहिए ।

(व्यवधान)

अरे बैठिए न मंत्री हैं, थोड़ा इसका ख्याल कीजिए । सभापति महोदय, एक और जो महत्वपूर्ण विभाग है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मंत्री जी लोग भी बैठे हुए हैं, सब मंत्री हैं । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्थिति है इस राज्य में कहीं कोई विधायक, कहीं कोई सांसद अगर पत्र लिख दे, फोन कर दे । एक हमारे विधायक मित्र कह रहे थे कि डी0एम0 को फोन करते हैं तो कहता है कि हां बोलिये विधायक जी क्या हाल है ? सरावगी जी से दूसरा कहता है क्या ? जो भ्रष्टाचार है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार इतना ये है आप उसको रेक्टीफाई नहीं ।

(व्यवधान)

अरे हाल ही तो मैं पूछ रहा हूँ न । माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है यह हम कहना चाहते हैं कि हम इसको नहीं सुधार पाते हैं तो आखिर किस चीज का सुशासन बाबू ? क्यों पैसा मांग रहे हैं ? हर डिपार्टमेंट है उसमें जो वैकेन्सी है वह फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आप नियोजन पर भी जो कर्मचारी ले रहे हो उसको भी समय पर वेतन नहीं दे रहे हो ।

क्रमशः

टर्न-11/06.03.2018/अशोक

डा. रामानुज प्रसाद : क्रमशः तो यह पैसा कहां जायेगा ? हम स्वास्थ्य पर आ रहे हैं, मैं कंक्लूड करूंगा स्वास्थ्य से ही, घबड़ाइये नहीं । आपके डी.एम.सी.एच. पर भी चर्चा होगी । आप रूक जाइये तो । मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक और विभाग का सभापति महोदय, मैं एक और रेज करना चाहता हूँ, इम्पौर्टेन्ट ईशु है जो हम अपने स्टेट के

कंटेस्ट में, बहुत वाईटल ईशु है, एग्रीक्लचर । एग्रीक्लचर के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, मैं इसलिये चर्चा करना चाहता हूँ कि मैं उसके जब खर्च ब्योरा देख रहा था तो मुझे लगा कि 29.7 प्रतिशत हमलोग अभी तक खर्च हमारी सरकार कर पाई है, ढिंढोरा पीटी जा रही है कृषि रोड मैप का, देश के तमाम लोगों के थालियों में बिहार का एक व्यंजन हो, कैसे होगा बिहार का व्यंजन ? आधा बिहार सूख गया और आधा बिहार दह गया, आप कैसे प्रबन्धन कर रहे हैं, आप खर्च नहीं कर रहे हैं, किसानों को अनुदान नहीं मिल रहा है, बीज नकली मिल रहा है, जीरों टेलर का जो नई कंसेप्ट और नई टेकनोलॉजी आई है उस पर कहीं सबसिडी नहीं दे रही हैं सरकार । सरकार का जो महकमा है, सकरार अगर प्रोवाईड भी कर रही है तो बैंकों में पड़े हैं या लूट हो रहे हैं माननीय मंत्री जी । तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसलिये हम ने कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सराकर में भी कृषि मंत्री रहे हैं, भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं, अच्छा अनुभव है उनको मैं उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कम से कम कृषि विभाग को आप कम से कम देखिये । जहां तक सवाल है, हम हेल्थ आयें उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ । सभापति महोदय, मेरा यह है कि कोई भी पार्टी जो सरकार में होती है, चूंकि पार्टियों का ही वर्ग चरित्र हुआ करता है, पार्टियों का ही वर्ग चरित्र होता है । जब वह सरकार में बैठ जाती उसी वर्ग चरित्र की प्राथमिकता होती हैं तो यह सरकार जो वर्ग चरित्र प्रस्तुत कर रही हैं, कहने के लिए कह रही है, कर्पूरी ठाकुर की जयन्ती, अम्बेदकर साहब की जयन्ती, मनाने के लिए तो मना रही है लेकिन हमारे लोगों को कहां भटका रही है, हमारे स्कूल को सुधारने की बात नहीं हो रही है, लेकिन मंदिर की मांग उठ रही है । (व्यवधान)अरे रविन्द्र भाई चरवाहा विद्यालय अगर यह हो जाय तो कल्याण हो जायेगा, आपकी पूछ इसीलिये है अगर चरवाहा विद्यालय पर स्ट्रेस नहीं होती तो आपकी पूछ नहीं होती । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि एस.सी./एस.टी. वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ऐसे-ऐसे विभाग हैं जिसके कारामात, आज ही माननीय मुख्यमंत्री खुद ही जवाब देने लगे कि साहब छात्रवृत्ति, एक तारांकित प्रश्न भी मेरा लगा हुआ था, हमारे लोग उड़ीसा मे, हमारे लोक तमिलनाडू में, हमारे लोग जो हैं वे केरल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारे गरीब के बच्चे, अति पिछड़े के बच्चे, दलित के बच्चे इस भरोसा से पढ़ने गये कि साहब उनको छात्रवृत्ति सरकार देने की घोषणा की है, और सरकार ने जो किया है, अब सरकार कह रही है बैंकों की अकर्मण्यता है, अरे भाई बैंकों की अकर्मण्यता जग जाहिर है, चौकीदार पूरा जो है सो, मोदी, ललित मोदी, निरव मोदी से विदेश पैसा भेजने में बैंक और बैंक के कर्मचारी लगे हैं और गरीब को कहां पैसा दे रहे है, चाहे छात्रवृत्ति लोन हो, चाहे

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एक्सपिडिशन का मामला हो, यह नहीं होने वाला है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि सरकार का वर्ग चरित्र ही गड़बड़ है । मैं आता हूँ अब स्वास्थ्य विभाग पर । स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी बैठे हैं और मामला स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा हो रहा हैं तो स्वास्थ्य विभाग से कहना चाहता हूँ कि साहब कि स्वास्थ्य की जो हालत है, स्वास्थ्य विभाग की जो हालत हैं, एन.आर.एच.एम. स्कीम .....(व्यवधान)

डा0 रवीन्द्र यादव : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एक चीज बतलाइये रामानुज बाबू, आप सिनियर मेम्बर हैं.....

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : आप व्यवस्था का प्रश्न उठाये हैं, आप सवाल आसन से न उठाइयेगा ।

डा0 रवीन्द्र यादव : अस्पताल में गॉज मिलता था आज से दस साल पहले ?

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है डा0 साहब ।

डा0 रामानुज प्रसाद : बैठिये डा0 रवीन्द्र जी, आप डाक्टर भी हैं, रवीन्द्र जी बैठिये । बैठ जाइये नहीं तो और जग हसांइ होगी । मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये बाबू राम कुशवाहा वाले लोग हैं, बाबू राम कुशवाहा को गहबलिया करने वाले लोग है । ये एन.आर. एच.एम. स्कीम और आज के हमारे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं सभापति महोदय, ये जब स्वास्थ्य मंत्री जी और जब स्वास्थ्य मंत्री के लोग जब इधर बैठते थे तो एन.आर.एच.एम. स्कीम को यहां भी लोगों ने रेज किया था और पी.एम.सी.एच. में जो दवा घोटाले हुये थे, उस घोटाला को माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने न सिर्फ उस पर हाय तौबा किया था बल्कि कोर्ट के शरण में भी पहुंच गये थे । अब जब कोर्ट का डायरेक्शन पास हुआ, कोर्ट जब भरडिक्ट आया तो कार्रवाई करने के समय उधर चले गये अब हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वे हमारे अच्छे मित्र भी हैं ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब आप कंक्लूड कीजिये । अब आपका समय हो रहा हैं ।

डा0 रामानुज प्रसाद : मैं इनका भी पढ़ा करता था, वे हंस रहे हैं । तो इनका भी रोज बयान सुनता था, पढ़ता था। मैं चाहूंगा कि कोर्ट ने भी डायरेक्शन पास किया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कि क्यों नही सरकार इसको सी.बी.आई. से जांच कराती हैं ? आप इस केस को सी.बी.आई को दे दो । आपसे आग्रह करता हूँ, आपका जो है, वह जारी रहेगा कि हां साहब आपलोगों ने जो लड़ाई लड़ने का काम किया था तो उस लड़ाई को सरकार में आये तो अमलीजामा पहनाने का काम किया । आपको यह करना चाहिये ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, थोड़ा सा और बोल लेने दीजिये । स्वास्थ्य विभाग पर तो बोल लूं । यह जो स्वास्थ्य विभाग का यह हालत हैं, माननीय मंत्री जी मैं आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां कही कोई न पारा मेडिकल स्टाफ न कहीं कोई डाक्टर नहीं हैं, आप हंसिये नहीं डा0 रवीन्द्र जी, सच्चाई है । अगर उनके पोस्टिंग और डिप्लायमेंट है तो वे काम नहीं करते । अरे आप अपने क्षेत्र में भी देंख लेना, अपने क्षेत्र में भी कहीं भी सभापति महोदय, किसी भी उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई नहीं जाते, हमलोग बार बार चिल्लाते हैं, सिविल सर्जन को कहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है । हां डिप्लायमेंट है, वहां उनका पोस्टिंग है लेकिन काम को मैं नहीं कहता हूँ कि मंत्री जी इसके लिए जिम्मेवार हैं, इसको सुधारने की जरूरत है । ये नौजवान हैं, मेरे मित्र हैं, मैं कहता हूँ कि आप इसको सुधारिये । जो मेडिकेल कॉलेज का जो सवाल है तो मुजफफरपुर मेडिकल कॉलेज एस.के.एम.सी.एच., उनका डी.एम. सी.एच. में भी घोटाला है, लेकिन एस.के.एम.सी.एच., के बारे में कह रहा हूँ कि उसकी स्थिति जर्जर है, वहां ही एस.के.एम.सी.एच., के एडजेसेंट एरिया में चिकेनगुनिया, इन्सेफलाईटिस से हर साल हमारे बच्चे काफी संख्या में मरते हैं, सरकार को एण्टी एलर्जी रिसर्च सेन्टर खोलने का प्रस्ताव आया था, केन्द्र से आया था, मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर सकी है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपने राज्य में ...

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : थोड़ा सा और । हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक स्वास्थ्य उप केन्द्र है परमानन्दपुर, भाई लोग हल्ला कर रहे हैं वह बना हुआ है, हमने आपसे पहले भी आग्रह किया था, हमारे नया गांव है, नयागांव है बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है और वहां स्वास्थ्य उप केन्द्र हुआ करता है, लेकिन कोई डाक्टर नहीं जाता हैं, डिप्लायमेंट है लेकिन वे पटना में और हाजीपुर में प्रैक्टीस करते हैं ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें, समय हो गया ।

डा0 रामानुज प्रसाद : जितने डाक्टर्स रहते हैं वहां करा लेते है कि पटना में बैठकर प्रैक्टीस करेंगे, हम आपसे कहना चाहते हैं कि सदन का आश्वासन भी है, स्वास्थ्य मंत्री जी हम ऐसे विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बिधान सभा क्षेत्र के जिला के अंतिम, आप हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं और उस जिला का अंतिम छोर है और अंतिम छोर है, जब दुर्घटनायें होती हैं, लोग मरते हैं, लोग डूबते हैं और जब पोस्टमार्टम का मामला आता है, तो लोगों को छपरा 70 कि.मी. है जिला मुख्यालय तो हाजीपुर लोग चले जाते हैं, हाजीपुर में तो हाजीपुर में वह कहता है कि हम

इन्टरडिस्ट्रीक्ट नहीं करेंगे । हमारा बार बार मांग रहा है कि सोनपुर में एक आप पोस्टमार्टम सेन्टर, वहां रेफरल हॉस्पीटल भी हैं, वहां देने की कृपा करेंगे । माननीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग को सुधारेंगे, महोदय मांग नहीं रहे है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, एक और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य समिति में जो मैनेजर बहाल किये हुये हैं सभापति महोदय, सभी अस्पताल में मैनेजर बहाल हैं, उन मैनेजरों का हाल यह है कि वह अस्पताल को मैनेज नहीं, वह मनी मैनेज में लगा रहता है । वह मनी मैनेज में लगा रहता है, उसको देंखने की जरूरत है । सभापति महोदय, मैं राज्य हित में उठा रहा हूँ । मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ पी.एम.सी.एच. का जो ब्लड बैंक है, मैं खुद गया था साढ़े बारह बजे रात में, हमारे क्षेत्र के लोग, गरीब व्यक्ति रो रहे थे और वहां की कारगुजारी, सभापति महोदय ....

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब आपका समय समाप्त हुआ ।

टर्न-12/ज्योति/06-03-2018

श्री रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, थोड़ा सा आपसे आग्रह कर रहे हैं । वहां होता क्या है वह बच्चा जो बीमार था पेडियाट्रिक्स में तो उस बच्चे के लिए एडवाईस होता है ब्लड ट्रांसफ्युज्न के लिए जब वो जाता है ब्लड बैंक में भेजा जाता है तो उसका बाप कहता है, मेरा खून ले लीजिये , बाप का खून जांचता है, कहता है, नहीं नहीं आपका ये नहीं, इसके लायक नहीं है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): समाप्त कीजिये ।

श्री रामानुज प्रसाद : फिर मां जाती है उसको भी कर देता है फिर तीसरे जाते हैं उनको भी वही कर देता है, थोड़ी देर बाद रोते हुए निकलता है, जब दलाल लग जाता है, तो मैं बताता हूँ । ब्लड बैंक पर ध्यान दिया जाय ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : आपका समाप्त हुआ । श्री लक्ष्मेश्वर राय ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदय, तृतीय अनुपूरक बजट पर हमको बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद । महोदय, राज्य सरकार न्याय के साथ विकास मंत्र के अनुरुप सभी क्षेत्रों और वर्गों के साथ ले कर चलने के लिए कृतसंकल्पित है । राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत होने के साथ साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है । सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं पेयजल सुविधा, बिजली , स्वास्थ्य सेवा उपलबध हो बल्कि आधारभूत संरचना सड़क गली, पुल इत्यादि का भी विस्तार हो । राज्य सरकार युवाओं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उच्च व्यावसियक तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की व्यवस्था कर रही है । साथ ही बिहार की जनता को गुणवता चिकित्सीय सुविधा सुगमता से

उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है । राज्य की बुनियादी सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की भी स्थापना की जा रही है । स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट चिकित्सा हेतु आधारभूत संरचना का विकास एवं कुशल मानव संससाधन के उपलब्धता पर भी काम किया जा रहा है ताकि लोगों को आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो । बिहार में विकास दर में भी लंबी छलांग लगायी है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य की आर्थिक विकास दर 7.5 थी । वित्तीय वर्ष 2016-17 में वृद्धि दर 10.3 प्रतिशत हो गयी । इसी अवधि में देश का विकास दर 7 प्रतिशत रहा है । देश की तुलना में राज्य का विकास दर 3 प्रतिशत अधिक है जो सराहनीय है । पिछले दशक 2004-05 से 2014-15 के बीच में स्थिर मूल्य पर राजकीय आय 10 प्रतिशत बढ़ी है । सड़क, कृषि, उर्जा, डेयरी, सब्जी उत्पादन आदि में भी तरक्की हुई है । खास कर राज्य सभी क्षेत्र और वर्ग को साथ ले कर चलने के साथ साथ सामाजिक कुरीति दूर कर राज्य की चहुंमुखी विकास के लिए भी कृतसंकल्पित है । सामाजिक समरसता का माहौल आगे बढ़ रहा है । महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास हो रहा है उसके लिए उच्च शिक्षा व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास की व्यवस्था भी की जा रही है । 2 अक्तूबर से बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरु किया गया है । 21 जनवरी को इसके विरुद्ध बिहारवासियों ने 14 हजार किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर इस अभियान के संकल्प का इजहार किया है । साथ ही महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनके सपनों को बिहार से उस सपना को एक देश में एक नयी दृष्टि देने के लिए, सामाजिक परिवर्तन का रुप देने के लिए शराबबंदी हमको लगता है इस देश के लिए वरदान साबित होगा । महोदय, यह पहली होली है जहॉ लोगों में हुड़दंग और दंगा नहीं हुआ , जहॉ लोगों की हत्या नहीं हुई , जहॉ लोगों में प्रतिशोध भावना नहीं जगी । आज शराबबंदी से ..

श्री विजय प्रकाश : महोदय, पहले पता कर लीजिये सभी जिले के हौस्पिटल से कि कितना लोग होस्पिटलाईज हुए हैं । गलत बात बोल रहे हैं । पता कर लीजिये ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदय, केवल मधुवनी जिला में एक घटना हुई जो महादलित परिवार को वहॉ के स्थानीय ललमनिया के मुखिया रुप नारायण यादव ने होलिका दहन के दिन उसका घर उजाड़ दिया, उनकी पत्नी की पिटाई की और उसके परिवार और घर को उजाड़ दिया । केवल एक घटना हुई मधुवनी में, यही है होली और होलिका दहन । यही है शराबबंदी का दौर । हम सभापति महोदय, शराबबंदी से जरुर महात्मा गांधी के सपनो, महात्मा गांधी के विचार का रुप बदला है लेकिन 15 वर्षो से राज किये है उनकी मानसिकता नहीं बदली है । शराब की बात कौन करता । शराब में कौन डूबा है, इसकी जॉच होनी चाहिए जो शराब की बात करता कभी कृतसंकल्पित थे , शपथ लिए थे

आज जब शराब की बात होती है तो बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी, होम डिलीवरी के मैनेजर कौन है, इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि होम डिलीवरी में कौन लगे हुए हैं । यही बड़े लोग लगे हुए हैं । कोई अतिपिछड़ा महादलित नहीं लगता । सुनिये । सामाजिक न्याय की धारा के लोग हैं महादलित और अति पिछड़ा, ये लोग डोर डिलीवरी नहीं कर सकते । वही लोग कर सकते जो होम डिलीवरी की बात करते हैं । बालू का आज किल्लत हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, कौन है माफिया बहुत लोग बैठे हुए हैं । माफिया करके बालू को आज कौन कब्जा में रखे हुए थे । आज कौन शराब के लिए कौन जिम्मेदार है ? नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है । नीतीश कुमार जैसे गांधी जी के जो चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह वर्ष है, याद करिये नील्हें खेती के लिए यदि आन्दोलन में चम्पारण आए तो दुनिया को तकदीर बदल दिए, तस्वीर बदल दिए जो क्रांति का रास्ता था, चम्पारण आ कर दुनिया का संघर्ष का तरीका बदल गया और बोला हिंसा से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती और वही बात आज बिहार में हो रही है । नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई शराब के बिना बंद किए हुए नयी दिशा नहीं दे सकते । कौन कहते हैं होम डिलीवरी कौन कहते हैं अनुशासन और विकास की बात । पिछले दिन विपक्षी दल के नेता अपने आसन से उठकर आ गए थे टेबुल पर । ये चलेगा बिहार ? इससे होगा बिहार का विकास ? नहीं होगा , आप भी अनुशासन में रहिये, हम भी रहें । जब आपका विपक्षी दल के नेता बोलते हैं तो हमलोग चुप रहते हैं । बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, एक लोग भी नहीं बोलते लेकिन जब इधर से लोग बोलते हैं तो आप लोग दबाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, इससे नहीं चलेगा ? बिहार के लोग जान लिए हैं कि यह विकास से बात बदलेगी । सामाजिक न्याय की जो धारा है वह ताकत पर नहीं चलेगी । आपको बदलना होगा नहीं तो आपको जनता बदल देगी आने वाले समय में और मजबूती से मुंहतोड़ आपको जवाब देगी । आपको नजरिया बदलना चाहिए । आज स्वास्थ्य विभाग पर डौक्टर साहेब बढ़िया बोल रहे थे । कहां गया था स्वास्थ्य विभाग ? हमलोग एप्लीकेशन नहीं दे पाते थे । हम एक हौस्पिटल के सुधार के लिए चिन्तित रहा करता था कि कहॉ जांऊ , कहॉ एप्लीकेशन लगाऊं इसिलए चुप रहता था, यह स्थिति थी स्वास्थ्य विभाग की लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग लगता है बदलाव का प्रतीक है और बिहार के लोगों का नजरिया बदला है । स्वास्थ्य विभाग निश्चित रुप से गरीबों के लिए और खास कर जो हमारे डौक्टर और चीज की जो कमी है प्रत्येक अनुमंडल में ए.एन.एम. कॉलेज खोला जा रहा है । प्रत्येक जिला में और मधुवनी जिला जैसे जगह पर आज मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, यह बड़ी बात है । बड़े सौभाग्य की बात है कि लोगों की मेंटलिटी बदलेगी और लोगों का नजरिया बदलेगा । नीतीश कुमार जी हमको तो लगता है कि इस देश का नजरिया बदलेंगे । देश का तस्वीर बदलेंगे । ये सीखना चाहिए । आज कह रहे थे पिछले

दिन हमारे नेता विरोधी दल के कि बीस हजार की बात कर रहे थे । कोई रेखा मोदी जी यहाँ नहीं थी उनकी भी चर्चा की थी एक शब्द आपके खिलाफ में कोई नहीं बोला लेकिन दिल्ली में किसका होता है फार्म हाउस का सीज किनका होता है, किनका होता है ? बोलना चाहिए । अरे घोटाला में कौन फंसा है, यह बोलना चाहिए । आज बहस का विषय है कि छोटी छोटी बात ले कर हंगामा करते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं , हम अति पिछड़े हैं, ये लोग जो हमलोग शांतिप्रिय हैं इसलिए बोल रहे हैं । निश्चित रुप से अपको सबक लेना चाहिए कि हम आपकी बातों में वैचारिक रुप से जवाब देते हैं तो आपको भी देना चाहिए । आज जो इस सदन के मेम्बर भी नहीं थे, उनकी बात करते हैं कि घोटालाबाज है, सृजनवाज है । दिल्ली में किनका फार्म हाउस सीज हुआ है । अब कोई गठबंधन के लोग नहीं बोले कि रांची में कौन बंद है ? गठबंधन के लोग नहीं बोले लेकिन आपको इस बात को रखना चाहिए कि यदि ये लोग हमको सम्मान देते हैं, हमारे नेता को तो हमको वैसे लोगों पर कीचड नहीं उछालना चाहिए । नीतीश कुमार वैसे लोग हैं ।

क्रमशः

टर्न–13/06.3.2018/बिपिन

श्री लक्ष्मेश्वर राय : क्रमशः नीतीश कुमार वैसे लोग हैं, नीतीश कुमार की वैसी दृष्टि है जो महात्मा गांधी जी से तुलना किया जा सकता है, इस देश की आजादी से तुलना किया जा सकता है । आज 15 साल की भरपाई, हम तो कहेंगे सरकार से कि यदि यह 15 साल का जो बचा–खुचा चीज है उसको जब तक ध्वस्त नहीं करिएगा तो आपके मन में जो है कि सामाजिक न्याय और जो विकास, तो मजबूती से ध्वस्त करना होगा । वैसे लोगों जिनकी आदत खराब है, जो ये केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से शिकस्त करना चाहिए कानून के दायरे में । इन्हीं चंद बातों के साथ हम चाहेंगे कि बिहार का तकदीर, बिहार का तस्वीर बदल रहा है और गांधीजी का जो सपना था, गांधी जी चम्पारण शताब्दी वर्ष के याद में जो किए थे कि दुनिया का तस्वीर बदल दिए थे तो क्रांति से नहीं, शांति से बदलाव होगा । नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे विचार दिए, चाहे वह सात निश्चय हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जल संसाधन के क्षेत्र में हो, नजरिया बदल रहा है । निश्चित रूप से कानून के राज्य की बात वह नहीं है, सामाजिक न्याय की धारा की बात वह नहीं है लेकिन नीतीश कुमार जी कभी जातिवाद नहीं करते, कभी धर्म की बात नहीं करते, वह तो कहते हैं हिन्दू–मुस्लिम–सिख–इसाई, आपस में हैं भाई–भाई । ऐसा बात कहते हैं । तो जातीय कट्टरता की बात नहीं करते और इसीलिए हम चाहेंगे कि बिहार की तकदीर बदलने के लिए सारे लोगों को एकताबद्ध होनी चाहिए और नए दृष्टि, नए आयाम के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक नया दिशा बिहार को देना चाहिए जो देश बिहार से सीखे

और बिहार के रास्ते पर चले तो उनकी चम्पारण शताब्दी वर्ष है, हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को मजबूती से हमलोग साथ हैं, हम आगे आने वाले समय में भी चाहेंगे कि जो आपका भ्रष्टाचार का जो टॉलरेंस की नीति है, आपकी नीति ठीक है, कार्यक्रम ठीक है लेकिन ऐसे लोगों पर, ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं, उसको और शिकस्त करने की जरूरत है और मजबूती से कानून लगाने की जरूरत है । इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह जो कटौती प्रस्ताव आया है उनके खिलाफ में बोल रहे हैं और सरकार के पक्ष में अपनी बात रखते हैं ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य श्री राघव शरण पाण्डेय ।

(व्यवधान)

बैठिये । नाम पुकार लिया गया है अगले वक्ता का । आप बैठिये । आपकी बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जाएगी । बैठिये । राघव शरण पाण्डेय जी ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के विरोध में और सरकार द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधोयक के पक्ष में बोलने का आपने अवसर दिया, आभारी हूं । (व्यवधान)

ऐप्रोप्रिएशन बिल देख लीजिए । पांच करोड़ छः सौ तीन करोड़ का है । उसी के विषय में चर्चा है । स्वास्थ्य विभाग पर विशेष चर्चा है । सरकार के पक्ष में, आपके कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोल रहा हूं । मंशा स्पष्ट कर दे रहा हूं क्योंकि अभी जो वक्ता थे, उनकी मंशा पर आपलोग सवाल उठाए थे ।

स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो रही है और तकलीफ होती है कि वो लोग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिस्टम की अकर्मन्यता की बात कर रहे हैं जिनके नेता ने डेढ़ साल यह विभाग चलाया । प्रश्नों का उत्तर देने से बचते रहे । यह तीसरा बजट हमलोग देख रहे हैं । इस विधान सभा के गठन के बाद तीसरा बजट हमलोग देख रहे हैं । कभी स्वास्थ्य विभाग की चर्चा नहीं की गई और आज जब स्वास्थ्य विभाग पर विशेष चर्चा का समय है तो कहा जा रहा है कि सभी विभागों का अनुदान इसमें सम्मिलित है तो सभी विभागों के बारे में चर्चा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है । वैद्यता के तौर पर सभी विभाग के बारे में चर्चा हो सकती है और सरकार के बारे में चर्चा हो सकती है ।

तकलीफ होती है कि विपक्ष, इस नई सरकार के आए आठ महीने हुए, एक नए तरह का बजट पेश हुआ है पुरानी एन.डी.ए. सरकार के जो कार्यकलाप हैं, विकास के दर में जो तेजी आई थी, बिहार को जो उम्मीद जगी है कि नई सरकार के आने के बाद ये नए गठबंधन के आने के बाद बिहार विकास के मार्ग पर पुनः अग्रसर होगा तो

कहा जा रहा है कि मैंडेट का निगेशन हुआ, कहा जा रहा है कि चोर दरवाजे से आए हैं ।

(व्यवधान)

सच्चाई मुझसे सुनिए । आपका समय आएगा तो आप भी बोलिएगा । ये चोर दरवाजा क्या होता है ?....

(व्यवधान)

सभापति : बैठे बैठे मत बोलिए ।

श्री राघव शरण पाण्डेय: सांवैधानिक दरवाजा से सरकार आई है । सरकार ने विश्वास मत प्राप्त किया है । आपने सरकार के विश्वास मत नहीं होने पर सवाल उठाए । सांवैधानिक तौर से यह चोर दरवाजा क्या होता है ? पहले हम उस दरवाजे से आते थे, अब इस दरवाजे से आ रहे हैं । वह भी दरवाजा सांवैधानिक है, यह भी दरवाजा सांवैधानिक है । जैसे अभी सदस्यों का जिसको समर्थन प्राप्त है, वह सरकार चलाएगा और क्या था आपका चुनावी नारा ? आप महागठबंधन बनाए हुए थे तीन दलों को मिला कर लेकिन ..

(व्यवधान)

शक्ति सिंह यादव : मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है सभापति महोदय ।

सभापति : बोलिए, आपका क्या ऑर्डर है ?

शक्ति सिंह यादव: महोदय, आपने कहा कि क्या आपका था चुनावी नारा महोदय ? आपके पूरे बजट में सात निश्चय हो....

(व्यवधान)

सुन लीजिए, आप सुन लीजिए । चाहे नल का जल हो, हर घर बिजली हो..

(व्यवधान)

आप सुन लीजिए । लेट मी कम्प्लीट ऑनरेबुल मेम्बर । आप सुन लीजिए...

(व्यवधान)

सभापति : शक्ति सिंह जी, जब आपके दल के लोग बोलेंगे, तो बोलिएगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, यही व्यवस्था है ?

(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, सुन लीजिए । शक्ति सिंह जी, आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर उठे थे तो आपको आसन से मुखातिब होना चाहिए न ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, यह जो मैंडेट मिला था –

आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार ।

और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को असहज स्थिति लगने लगी, जब लगा कि महागठबंधन में नेता का दम घुटने की स्थिति आ गई तो वह नेता पुनर्विचार नहीं करेगा कि हमको जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है बिहार को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का, वह हम नहीं ले जा रहे हैं तो हम नई संभावनाओं का तलाश करें और नई संभावनाएं आज आई हैं तो कहा जाता है कि यह चोर दरवाजा है, यह मैंडेट का निगेशन है ।

पहली बार तीन वर्ष में, मैं अपनी बात कहता हूं, तीनों बजट प्रपोजल को मैंने पढ़ा है, बखूबी बारिकी से पढ़ा है । तीनों जो इकॉनॉमिक सर्वे पेश हुए हैं मैंने उनको भी पढ़ा है और मैंने देखा है कि इस बार माननीय उप मुख्यमंत्रीजी ने जो बजट बनाया, जो पेश किया, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं, स्वास्थ्य पर विशेष चर्चा का दिन है । स्वास्थ्य में सुधार कुछ कम दिनों में जो कल्पनाएं की गई हैं जिनको मूर्त्त रूप देना अभी बाकी है । जिसमें जो कमियां हैं, उसका उल्लेख आप भी करते हैं, हमलोग भी करते हैं । हम चाहते हैं कि उन कमियों का सुधार हो लेकिन सरकार की मंशा एक बजट से साफ होती है और यह वह बजट है, अभी तक का सबसे ज्यादा पैसे वाला बजट । एक लाख छिहत्तर करोड़ का बजट । हमें जानना चाहिए कि हमारा जी.डी.पी. कितना है ? हमारा जी.डी.पी. 5 लाख 15 हजार करोड़ वर्ष 2018-19 में अनुमानित जी.डी.पी. है । यदि प्रपोर्शन निकालें और इन्हें निकालना चाहिए । मैंने निकाला है, आपसे शेयर करना चाहता हूं- यह 33 परसेंट है । हम अविकसित हैं इसीलिए इतना है और इसमें ..... क्रमशः

टर्न : 14 / कृष्ण/ 06.03.2018

श्री राघव शरण पाण्डेय (क्रमशः) हमारे वित्त मंत्री जी ने कहीं-कहीं से रिसोर्सेज ले करके, जिसमें केन्द्र का योगदान बहुत है, 70 परसेंट केन्द्र का योगदान है और जब हम सत्ता में आये तो हम कहते थे कि डबल इंजन की बात है तो डबल इंजन लग गया है । 1 लाख 76 हजार करोड़ में 1 लाख 22 हजार करोड़ केन्द्र से आयेगा । कुछ हमारा अधिकार है, कुछ केन्द्र का डिसक्रिशन है और यदि हम इन सारे पैसों का हम सदुपयोग कर सकें, जिसमें आपका भी सहयोग चाहिए, हम सब का सहयोग सरकार को चाहिए तो बिहार फिर 13 परसेंट का जो ग्रोथ रेट था, उससे हम आगे भी पार कर जायेंगे । यह मेरा मानना है । इस बजट के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है । यह प्राथमिकता सही पहचाननेवाला बजट है । सबसे ज्यादा पैसा किस विभाग को मिला है ? शिक्षा विभाग को मिला है, 32 हजार करोड़, जो 18 परसेंट से भी अधिक है टोटल खर्चे का । भारत में एक भी राज्य ऐसा बता दीजिये । कई राज्यों के बजट पेश हो रहे हैं, मैंने कई राज्यों के बजट का अध्ययन करने की कोशिश की । कोई ऐसा राज्य नहीं है

भारत में जहां 18 परसेंट शिक्षा पर खर्च हो और क्यों खर्चा हो रहा है बिहार में क्योंकि यहां शिक्षा की स्थिति दयनीय है । शिक्षा की स्थिति दयनीय इस सरकार ने नहीं बनायी है । यह जो एन0डी0ए0 की सरकार है जिसको अभी आये हुये 8 महीने हुये हैं आप भी इस सरकार में शामिल थे पहले हमने भी सरकार चलाई है, आपने भी चलाई है बहुत लोग आये, बहुत लोग गये लेकिन शिक्षा की स्थिति दयनीय है । शिक्षा का सुधार आवश्यक है । इस वित्त मंत्री ने पहचाना कि शिक्षा में सबसे अधिक आवंटन होना चाहिए तो 18 परसेंट शिक्षा में उन्होंने आवंटन किया । इन्फ्रास्ट्रक्चर, आप अभी पूछ रहे थे जापान से क्या लेकर आये ? आप गये और जापान ने दे दिया और आप ले कर चले आये, ऐसे ही सरकार चलती है क्या ? इन्वेस्टमेंट कैसे होता है ? आपको मालूम होगा, अभी आपने कहा कि 33 परसेंट हमारा बजट का टोटल जी0डी0पी0 में । एक डेवलप स्टेट की बात मैं बताता हूं । गुजरात । गुजरात का बजट हमारे राज्य के बजट के करीब-करीब बराबर हळ । हमारा अगर 1 लाख 76 हाजर करोड़ है तो गुजरात का 1 लाख 81 हजार करोड़ बजट है । किन्तु गजरात का जी0डी0पी0 हमारे जी0डी0पी0 से तीगुणा है । तो इसका मतलब हुआ कि उसका बजट और जी0डी0पी0 का रेसियो केवल 12 परसेंट है । गुजरात में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और हमारे यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां है ? भारत में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 60-61 बिलियन को पार कर गया है । लेकिन चिन्ता होती है अपने प्रदेश के लिये । हमारा शेयर उसमें कितना है ? बिहार और झारखंड को मिलाकर प्वाइंट वन परसेंट है । हमारी जनसंख्या 8 परसेंट है । हमारा एफ0डी0आई0 प्वाइंट वन परसेंट है । इसके लिये क्या करना होगा ? इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा और हमारी इस सरकार ने एन0डी0ए0 की सरकार 8 महीने पुरानी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मानकर बिजली, सडक, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है और यदि इस तरह से प्राथमिकता चलती रही तो तो एफ0डी0आई0 भी हमारे यहां आयेगा, हमारा शेयर भी और हमारा जो बजट है, जी0डी0पी0 का रेसियो हैं, कम होगा प्राईवेट सेक्टर का शेयर ज्यादा होगा और हम विकास के पथ पर अग्रसर होंगे ।

स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है । हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी थोड़े दिन पहले आये हैं । पी0एम0सी0एच0 की जो कल्पना की गयी है, उसको पांच हजार बेड का बनाया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बनाया जायेगा । इन्दिरा गांधी मेडिकल इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो यहां है, उसमें किडनी प्रत्यारोण, लीवर प्रत्यारोपण की सुविधा दी जायेगी । आई0 टी0 के क्षेत्र जो विकास हो रहा है, जो हर चीज ऑन लाईन हो जायेगा, जिसमें स्वास्थ्य सुविधायें भी शमिल हैं, मैं गिनाना नहीं चाहता, बहुत उपलब्धियां हैं इस सरकार में ।

कृषि की चर्चा आप कर रहे थे । हां, यह बात सही है कि कृषि में खर्चा 29 परसेंट कम हुआ है । पिछला दस साल का हिसाब लेकर देख लीजिये । किस विभाग में किस वर्ष में 100 परसेंट खर्च होता है । यह हमारी सरकार की उपकरण की कमी है, यह सरकार उसको सुधारेगी । यह सरकार सुधारावाली सरकार है । यह सरकार नरेन्द्र मोदी की सरकार से गाईड होती है । यह सरकार एनडीए की सरकार है और एनडीए का क्या है मामला ? जब एनडीए इस देश में आयी थी ।

(व्यवधान)

बताता हूं । मुख्यमंत्री एनडीए के नेता हैं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) – नेमतुल्लाह जी । आप अभी भाषण देनेवाले हैं । जब आप अपना भाषण दीजियेगा तब आप बोलियेगा ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : एनडीए सात राज्यों में थी । 2014 के चुनाव हुये थे । आज एनडीए 21 राज्यों में है । 70 परसेंट जनता पर भारत में एनडीए का शासन है और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद बिहार में भी जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनलोगों ने समझा कि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चलना है तभी बिहार का विकास होगा और बिहार में भी एनडीए की सरकार बन गयी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सात निश्चय का काम उठाया है, घर–घर नली और गली और पेयजल की व्यवस्था का जो बीड़ा उठाया है, जो महिलाओं के आरक्षण की बात कही है और जो छात्रवृत्ति की बात कही है, जिसके लिये नई योजनायें बन रही हैं जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री आज सुबह सत्र में करक रहे थे, ये सब सराहहनीय बातें हैं । यह दम घुटनेवाली महागठबंधन में संभव नहीं था । अब संभव हो रहा है । कुल लोग कह रहे थे कल सुन रहा था, जेनरल बजट पर चर्चा हो रही थी, आपने माईनॉरिटी का बजट घटा दिया । कहां माईनॉरिटी का बजट घटा दिया ? पिछले वर्ष मैंने इसी सदन में कहा था माईनॉरिटी के बजट में पिछली बार तुष्टिकरण की नीति के अंदर 84 परसेंट का इजाफा किया गया । माईनॉरिटी की सारी इच्छायें पूरी हो, इसमें किसी को मतभेद नहीं है । लेनि एक विभाग का बजट 84 परसेंट आप बढ़ा दीजिये और बाकियों का काट दीजिये तो यह बात माननेवाली नहीं है । इस वर्ष क्या हुआ है वित्तीय वर्ष 2016–17 की तुलना में माईनॉरिटी के बजट में 42 परसेंट का इजाफा किया गया है । हां, इस बार मंदिरों ी घेराबंदी के लिये 30 करोड़ दिया गया है ।

(व्यवधान)

विभाग को खत्म करने की बात नहीं है । मैंने कहा कि माईनॉरिटी के विभाग को 42 परसेंट ।

(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : आप लोग आपस में क्यों बात कर रहे हैं ? आप का समय आयेगा तब आप बोलियेगा न !

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, मैं यह कहना चहाता हूं कि हमारा बिहार बहुत पीछे है । प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम झारखंड के भी आधे हैं । देश की तुलना में एक तिहाई हैं । विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि कंधे से कंधा मिलाकर चलिये । सरकार ने अच्छा बजट बनाया है सरकार स्वास्थ्य सुधारों में सुधार करने की मंशा रखती है । सरकार के बजट डॉकुमेंट आप समझते हैं, ये पहले से अच्छे हैं । सरकार की इकोनॉमिक सर्वे पहले से अच्छी है । तो सरकार की जय कीजिये, इसी में बिहार का जय होगा ।

महोदय, आपदा की बात मैं थोड़ा कहना चाहता हूं । इस सरकार के बनते-बनते बिहार को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा और जिस दक्षता से बाढ़ का सामना सरकार ने किया और केन्द्र की मदद से किया, डबल इंजन लगाकर किया, वैसा बिहार में मिसाल नहीं है । एक बात अपने सरकार के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में मेरे जिला में एक मसान नदी है, मसान नदी ने इतनी तबाही की यदि रात में बाढ़ आई होती तो कई लोग जान गवां चुके होते, मसान नदी का तट 35 किलोमीटर चौड़ा है पश्चिम चम्पारण जिले में, नेपाल के बोर्डर से शुरू होकर तीन प्रखंडों में - बगहा-2, बगहा-1 और रामनगर, लौरिया प्रखंडों से होकर सिकरहना नदी में मिलता है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : बांध टूट गया उसको बनाने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है । मैंने बजट में नहीं देखा । मेरा अनुरोध होगा कि उसपर पुनर्विचार करके उसकोा उसमें शामिल किया जाय । यह सरकार एस0टी0,एस0सी0 के लिये समर्पित सरकार हळ । उसका भी बजट बढ़ाया गया है । वे वंचित लोग हैं समाज के । लेकिन एक बात कहूंगा कि जब झारखंड बंटा तो एस0टी0 का आरक्षण 10 परसेंट था ।

सभापति (डा0अशोक कुमार) : समाप्त किया जाय ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : एक मिनट । एस0टी0 का आरक्षण 10 परसेसंट था, वह काट कर 1 परसेंट सकर दिया गया । क्योंकि उन दिनों एस0टी0 की संख्या बिहार में कम हो गयी थी । उसके बाद कई जातियां जनजाति की श्रेणी में शामिल की गयी । लेकिन वह आरक्षण केवल 1 परसेंट का 1 परसेंट बना हुआ है । यह अनुचित है । सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि जिस नीयत से यह एनडीए सरकार बनी है , बिहार को आगे ले जाना चाहती है बजट में जिसका स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है, वह जरूर संभालेगी और इस पर विचार करेगी ।

एक अंतिम बात महोदय इस सरकार के बजट में बहुत-सी जैसी चीजें हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर सुधार लाने की आवश्यकता है । विपक्ष ने भी कहा, हम

भी कहते हैक । और इम्प्लीमेंटेशन के लिये डिसेन्ट्रलाईजेशन बहुत जरूरी है । कुछ जगह जिला बनना चहिए, बगहा को जिला बनना चाहिए, उसकी मांग मैं फिर इस सदन में दोहराता हूं । सरकार से अनुरोध करता हूं, सरकार की नीतियों को लागू कर ने के लिये यह जिला बनना बहुत जरूरी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह ।

टर्न-15/सत्येन्द्र/6-3-18

मो0 नेमतुल्लाह: महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और अनुदान मांग के विपक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग का जो अनुदान मांग है, इस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनका स्वास्थ्य अब लगता है कि ठीक हो गया है इसीलिए वह स्वास्थ्य पर इतना रूचि नहीं ले रहे हैं । सिर्फ मंत्री यहां मौजूद हैं, पूरा मंत्रिमंडल गायब है, लगता है कि उनका अब स्वास्थ्य ठीक हो गया है इसलिए वे रूचि नहीं ले रहे हैं स्वास्थ्य के बहस पर । महोदय, पिछली सरकार जो हमलोगों की थी, 18-19 महीना की सरकार जो महागठबंधन की थी उसके पहले भी तो आप ही लोग की सरकार थी लेकिन आप गुणगान कर रहे हैं सिर्फ आज की सरकार का और आप अठारह महीना के सरकार के बारे में शिकायत कर रहे हैं, ये पिछले सात साल से जो आपकी सरकार थी वह चली आ रही थी उसके बारे में भी तो कहिये कि क्या उपलब्धि हुई थी । सिर्फ आप 6 महीना पर, आप विराजमान हो गये हैं बैक डोर से तो उसके बारे में आप चर्चा कर रहे है । पिछली सरकार में आपने फैसला किया था स्वास्थ्य मंत्री जी, आपलोगों ने कि 250 हम हॉस्पीटल बनायेंगे लेकिन आज यह कहां बना है, जमीन पर कितना उतरा है, इस पर भी बोलना चाहिए, बताना चाहिए । महोदय, आज जो सरकारी हॉस्पीटल है उसकी क्या दूर्दशा है, आज क्यों प्राईवेट नर्सिंग होम कुकुरमुत्ता के तरह खुल रहे हैं, हर जिले में, हर प्रमंडल में, हर ब्लौक में नर्सिंग होम को देखिये खुलते जा रहा है और दिन पर दिन उसमें गैदरिंग बढ़ती जा रही है । वहां दोहन हो रहा है, मरीजों का शोषण हो रहा है । आज पटना में किस तरह से लोग आते हैं बाहर से इलाज कराने सरकारी अस्पताल में इस उम्मीद में कि यह पी0एम0सी0एच0 है, यह नेशनल और इंटरनेशनल पैमाना का हॉस्पीटल है, यहां एम्स है लेकिन क्या सुविधा है यहां ? आप जाईए और देखिये । पिछली दफा जब यूवा स्वास्थ्य मंत्री थे जो हमेशा भिजिट करते थे, उन्हीं की पहल से किडनी ट्रांसप्लांट जो है वह खुला था राजाबाजार में, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पहले लोग बाहर जाते थे लेकिन आज किडनी ट्रांसप्लांट कराने की यह सुविधा आई0जी0एम0एस0 में मिल रहा है और यह उन्हीं का

पहल है । महोदय, स्वास्थ्य का जो हाल है, आज सभी प्राईवेट हॉस्पीटल में दोहन हो रहा है, वहां दलाल खड़ा है सरकारी हॉस्पीटल से खींच कर ले जाते है कि प्राइवेट हॉस्पीटल में चलो, वहां हर आदमी के पीछे और पेसेंट के पीछे दलाल लग जाता है, एक पेसेंट आता है जब बाहर से पटना में तो जब पी0एम0सी0एच0 के पास जाता है तो उसे पांच दलाल पकड़ लेता है, कहता है चलो हार्ट की बीमारी है चलो फलां नर्सिंग होम में, दूसरा कहता है कि किडनी की बीमारी है चलो फलां नर्सिंग होम में, वो सब इतना खींचातानी करता है तब मरीज कहता है कि अब हमको ऑर्थोपेडिक वाला में ले चलिये चूंकि आपलोग तो खींचतान के हमारी हड्डी ही तोड़ दिये तो ये तो हाल है आज पी0एम0सी0एच0 का और आई0जी0आई0एम0एस0 का महोदय, वहां जाईए तो लोगों की भीड़ लगी रहती है, कोई व्यवस्था नहीं है, इमरजेंसी में जाईए, वहां बाहर लोग रहते हैं, हाईजेनिक नहीं इनहाईजेनिक होता जा रहा है होस्पीटल का माहौल, वहां सफाई नहीं है महोदय, इस तरह की व्यवस्था है इसीलिए प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ लोग रूख करते हैं जहां अपना ईलाज कराते हैं और प्राईवेट नर्सिंग में क्या स्थिति है महोदय, मरीज अगर आई0सी0यू0 में मर जाता है तो दो दिन तीन दिन के लिए और उसमें रख लिया जाता है कि बिल बनता रहे, बिल बनता रहता है, कई नर्सिंग होम को कई मर्तबा तो फोन कर हमलोग कहते हैं कि अरे भाई पेसेंट मर गया है उसके बाद से भी बिल तुम क्यों चार्ज कर रहे हो । आपने देखा कि रेलवे स्टेशन से एक शव को, एक डेड बॉडी को दारू पिलाकर के ठेला पर लाद दिया गया, दारू तो यहां बंद है और कहा– ले जाओ श्मशान घाट, श्मशान घाट ले जाया गया ,ये स्थिति है यहां और आप लॉ एंड आर्डर की बात करते हैं, कल ही आप देखें कि पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर एसिड छिड़क दिया गया एक लड़की पर और उसके मामा पर भी, यही यहां लॉ एंड आर्डर है, कहां मूर्खों के जन्नत में आप तैर रहे हैं । आप हकीकत को देखिये, आप आईए देखिये, आपको सुधार करना है, माननीय मंत्री जी आप स्वास्थ्य मंत्री है और हमारे यहां के प्रभारी मंत्री भी है आपकी सरकार ने 2007 में कहा था कि गोपालगंज में बरौली को मॉडल हॉस्पीटल बनाना है, आपको छपरा में मढ़ौरा को, सीवान को दिघवारा को मॉडल हॉस्पीटल बनाना है लेकिन अभी तक कहां हुआ ? कहां हो गया और आज एडीशनल पी0एच0सी0 का क्या हाल है, डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है भी तो वह तुरंत रेफर कर देता है कि गोरखपुर चले जाओ । आपका वही हाल है एडीशनल पी0एच0सी0 का महोदय, पिछले दफा डेंगू का प्रकोप हो गया था छिड़काव नहीं हो रहा है मलेरिया का, आप देखिये जिस तरह से मच्छर का प्रकोप है, आज कहां फॉगिंग हो रहा है, कहां छिड़काव हो रहा है, मलेरिया का मच्छर ऐसे ही काट रहा है, डेंगू से लोग मर रहे है । यह तो ठंढा आ गया कि लोगों का जान बचा डेंगू से और मच्छर अपने आप मर गया लेकिन ठंढा होने के पहले बरसात के बाद जिस तरह से डेंगू हर घर में

फैला, जहां जाईए पांच आदमी बीमार मिलेंगे, क्या भाई तो डेंगू हो गया है, बकरी का दूध खोजो, पपीता खाओ, का भाई तो हॉस्पीटल में जगह नहीं है हॉस्पीटल में सब बेड बुक है तो घर में क्या करो, देहाती ईलाज कराओ, बकरी का दूध ले आओ, पुदीना का रस पीजिये, इस तरह से पी पी कर के आपका ये सब व्यवस्था लोग करते थे । महोदय, आज जो हॉस्पीटल में महिलाएं आती है, गर्भवती महिलाएं आती है, आशा को पांच सौ रू0 उनको देना होता है लेकिन आज मिल रहा है क्या? लाईफ सेविंग ड्रग्स का अभाव है, कल ही हमारे एक साथी ने कहा कि कुत्ता काट दिया, मधुबनी से पटना आकर कुत्ता का सूई लेना पड़ा, वहां कहीं नहीं मिला बीच में मधुबनी से पटना तक में, कहीं पी0एच0सी0 में कुत्ता और सांप काटने की दवा नहीं है महोदय, अगर कहीं कहीं जिला में मिल भी जाता है वह तब जब हमलोग पैरवी करके किसी को कुत्ता काट लिया है तो दिलवाते है महोदय, यह आम आदमी को सूलभ होना चाहिए उनको आसानी से मुहैय्या होना चाहिए महोदय । आज स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बिहार का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, देश का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम अपने नागरिकों से, हम अपने बिहारवासियों के स्वास्थ्य के लिए हम चिंतित रहें ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा महोदय तो देश विकास करेगा, राज्य विकास करेगा, समाज विकास करेगा । अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा महोदय, जो हमारे यहां मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज खोलने का है, आज बेतिया के मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, वहां टीचर की कमी है, एम0सी0आई0 रोज धमकाता है कि आप टीचर हमारे मानक के अनुसार नहीं रखते हैं हम मान्यता रद्द कर देंगे, तब आपाधापी में जैसे तैसे हमलोग बहाल करते हैं । आप बहाल कीजिये यह आपके हाथ में है, यहां डॉक्टर की कमी है कहीं भी डॉक्टर नहीं है, न पी0एच0सी0 में डॉक्टर है, न एडीशनल पी0एच0सी0 में डॉक्टर है और नर्सों की कमी है, पारा मेडिकल स्टाफ की कमी है यह सब आपके हाथ में है आप बहाल कीजिये, वहां ले जाईए और उससे गरीब जनता को उसके लिए सुविधा मुहैय्या कीजिये, ये आपको करना चाहिए इसमें विपक्ष कहां आड़े आ रहा है आपको करना चाहिए आप कीजिये । आप ये दुहाई देकर बच कर के नहीं निकल सकते हैं कि अठारह महीने की आपकी सरकार थी, अठारह महीना में हमलोगों ने जो कर दिया वह आप सात साल में भी नहीं कीजियेगा । हमलोगों ने बहुत किया जबकि आपने करने नहीं दिया चूंकि आपके खिलाफ मैंडेट मिला था और आपने पिछले दरवाजा से नापाक गठबंधन बना लिया, आपने गलत ढंग से गठबंधन बना लिया और आप ढ़िढोरा पीटते हैं शराबबंदी का । (क्रमशः)

टर्न-16/मधुप/06.03.2018

...क्रमशः ....

श्री मो0 नेमतुल्लाह : बिहार में शराबबंदी लागू है क्या ? कहीं है, देखने को मिलता है ? हर जगह होम डिलेवरी है । अभी हमने कहा कि दारू पिलाकर उस लाश को श्मशान घाट ले गया । अगर मरीज बीमार है, उसको ले जाना है एम्बुलेंस से तो डीजल नहीं है । कल ही एक अखबार में था कि डीजल की कमी की वजह से एक हार्ट पेसेंट को हॉस्पीटल नहीं पहुंचाया गया चूंकि एम्बुलेंस में डीजल नहीं था । इसलिये डीजल की व्यवस्था कीजिये । श्याम बहादुर भाई को बड़ी तकलीफ है क्योंकि व्यवस्था उनके लिये शराबबंदी करके बंद कर दिये ।

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : बैठिये । क्यों उठ जाते हैं ? बैठिये । कोई व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, पी0एम0सी0एच0 से हम लौट रहे थे, पी0एम0सी0एच0 के गेट पर एक लाश पड़ी हुई थी, चादर से ढकी हुई थी । दवा के अभाव में उसकी मौत हुई थी, चादर उठाकर मैंने देखा, उसके पेट पर लिखा था – सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा।

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : एक मिनट नेमतुल्लाह साहब । अब आप बोलिये, क्या प्वायंट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री श्याम बहादुर सिंह : लाईन दिया जाय । बहुत अच्छा बात कहे । बधाई है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सुनिये माननीय सदस्य, आपको प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर मैंने पुकारा है, कौन-सी धारा पर आप बोल रहे हैं, किस प्वायंट पर कहॉ पर वॉयोलेशन हुआ है ?

श्री श्याम बहादुर सिंह : नेमतुल्लाह जी जो बोले हैं....

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : बैठिये, गलत बात नहीं । आप बैठिये, स्थान ग्रहण करिये ।

माननीय सदस्य नेमतुल्लाह जी, बोलिये ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति हमलोगों के थे और मिसाइलमैन के नाम पर, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के नाम पर ठगी हो रहा है । मिसाइल सिटी कहॉ खोला गया ? मिसाइल सिटी खोलना था 397 करोड़ की लागत पर, मिसाइल सिटी कहॉ खुला ? कहॉ खर्च हुआ ? महोदय, सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि कहॉ खुला है मिसाइल सिटी । राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हमलोगों के मिसाइलमैन थे, देश-दुनिया में हमलोगों को एक लेशन दिया और कहा कि सपना वह नहीं है जो सोते हुये देखा जाय, सपना वह देखिये जो सपना आपको सोने नहीं दे । तो हमलोगों को यह सपना देखना चाहिये कि हमलोगों को काम करना है, हमलोगों को सोने नहीं दे । इस तरह का सपना देखना चाहिये । लेकिन आपको सत्ता मिल गया, आप सो गये, आप हैं कहॉ ? आपको इत्मीनान हो गया । आप सोचे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया तो बिहार की जनता का स्वास्थ्य ठीक हो गया । आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया, आपके अच्छे

दिन आ गये लेकिन बिहारियों के, बिहारवासियों के जो बुरे दिन आ रहे हैं, उसका भगवान ही मालिक है । इसलिये अभी से सचेत हो जाइये और होशियार हो जाइये क्योंकि आपके भी बुरे दिन आने वाले हैं । महोदय, 2007 में, जो दरौली में हमने कहा, स्मार्ट सिटी बनाना था, मेरे यहाँ एक दियारा का इलाका है, मांझा प्रखंड गोपालगंज में वहाँ नमुइया पंचायत में एक बाजार है मंगला बाजार, वहाँ एक उप स्वास्थ्य केन्द्र ...

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ एक खोल दें ताकि वहाँ दियारा के लोगों को गोपालगंज में आना पड़ता है, वहाँ महिलाएँ हैं, वहाँ प्रसव के लिये भी दिक्कत होती है। महोदय, मांझा प्रखंड में एक बथुआ जगह है, वहाँ भी एक प्रसव सेन्टर खोल दिया जाता तो वहाँ की महिलाओं को सुविधा होती । महोदय, जर्जर हालत में एक स्वास्थ्य उप केन्द्र है, बरौली में बेलसंड में, उसकी भी मरम्मति माननीय मंत्री से करवा देने के लिये आग्रह करता हूँ ।

महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द, जय बिहार ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : सभापति महोदय, (व्यवधान) सच तो बोलना ही है चूंकि तिवारी जी का आदेश है कि आप सच बोलिये । झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है । हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, 1997 से हमने अपने आपको सामाजिक-राजनीतिक जीवन में सौ प्रतिशत ढालने का एक सार्थक प्रयास किया है और 2005 में जनता की अदालत के आशीर्वाद से इस पवित्र मंदिर में मुझे आने का मौका मिला । इस पवित्र मंदिर के मंच पर हमारे माननीय विधायकों के द्वारा जो डिबेट किया जाता है और बाहर के मंदिर में जो डिबेट किया जाता है, डिबेट में काफी विरोधाभास मुझे महसूस होता है । स्वास्थ्य महकमा की हालत, हमारे जो विपक्ष में अभी साथी बैठे हुये हैं, वे अपने दिल पर हाथ रखकर यदि ईमान से विचार करेंगे तो बिहार की धरती पर स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं थी । (व्यवधान) भईया, हम तो पीठ पर हाथ कभी रखते ही नहीं, मैं तो दिल की आवाज से बोलता हूँ और किताब की बात नहीं बोलता हूँ । बिहार की धरती के जन-मानस की आवाज, बिहार की जो दुर्दशा को देखा है उसपर मैं बोलने का प्रयास करता हूँ । मैंने देखा बिहार को, सम्पूर्ण बिहार त्राहिमाम-त्राहिमाम की स्थिति में खड़ी थी और दुनिया के लोग बिहार को अपने नक्शे से हटाने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार में अब कोई सरकार नहीं है, बिहार में नैतिकता नहीं, बिहार में संस्कृति नहीं, उस हालात में बिहार को पहुंचाने वाले साथी आज विपक्ष में बैठे हुये हैं और लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे हैं । हॉस्पीटल के हालात यह थे सभापति महोदय, हॉस्पीटल में कुत्ते बैठते थे, न डॉक्टर, न नर्स, न हॉस्पीटल, न

टेबल, न कुर्सी, जीरो पर आऊट था । आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने बड़े ईमानदारी से एन0डी0ए0 की सरकार को आशीर्वाद दिया और 2005 में बिहार की धरती पर एन0डी0ए0 की सरकार बनी, सभापति महोदय । एन0डी0ए0 की सरकार ने बड़े ही ईमानदारी से बिहार को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने का एक सार्थक प्रयास किया है । हमने तो आज तक किसी अखबार में या किसी टेलिवीजन पर ऐसा न देखा, न पढ़ा, न सुना कि एन0डी0ए0 के हमारे नेता ने कहा कि बिहार को हमने विकसित राज्य बना दिया, विकसित बिहार बना दिया । हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि बिहार में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, यह तो अभी बिहार में शुरूआत है चूंकि जो हमारे विपक्ष में साथी बैठे हुये हैं, बिहार को जीरो पर आऊट करने का कार्य किये थे । मैं धन्यवाद देता हूँ एन0डी0ए0 में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चन्द्रमोहन राय जी आये थे और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में आमूल परिवर्त्तन करने का कार्य किया था और बिहार के आमजन स्वास्थ्य विभाग पर विश्वास करने को मजबूर हो गये थे और हॉस्पीटल में मरीजों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती चली जा रही थी ।

... क्रमशः ...

टर्न–17/आजाद/06.03.2018

..... क्रमशः .....

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : चूँकि मैं अपने जीवन से कुछ सिखता हूँ । मैंने देखा, जब हम फिल्ड जाते थे, आम लोगों से मिलते थे, उनके पॉकेट में दर्द की 5 रू0 की दवा की व्यवस्था नहीं होती थी, हमलोग सामाजिक स्तर से उनकी सेवा करने का प्रयास करते थे और जब एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो चन्दा मांगने की नौबत खतम हो गई और बिहारवासियों का इलाज बेहतर होना शुरू हो गया । महागठबंधन की सरकार बनी और गांव–घर में एक कहावत है, हमारे यहां ''Boss is always right." हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का निर्णय सर ऑखों पर था, लेकिन बन्दर के हाथ में नारियल मिल गये थे । स्वास्थ्य विभाग पर 18 महीना कोई चर्चा नहीं हुई, माननीय सदस्यों के द्वारा स्वास्थ्य पर सवाल उठाये जाते थे तो उसका जवाब नहीं मिलता था । हम माननीय सदस्य पीड़ा सहते थे और नेता के निर्णय का सम्मान करते थे और समय बदला, परिस्थिति ने हमारे नेता को फिर एन0डी0ए0 के साथ भाईचारा करके बिहार के इतिहास को आगे बढ़ाने का मौका मिला, इसके लिए मैं आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी को साधुवाद देता हूँ सभापति महोदय । आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पाण्डेय जी हैं, दिल की गहराई से इनको धन्यवाद देता हूँ, चूँकि इनके व्यक्तित्व को मैंने काफी नजदीक से परखा है, इनको समझा है, इनको जाना है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो स्वास्थ्य विभाग में कुछ कमियां हैं, मानते हैं, धरती की सच्चाई को मानना पड़ेगा माननीय सदस्य और धरती की सच्चाई को नहीं मानेंगे तो इस लोकतंत्र

के मंदिर में आना बड़ा ही मुश्किल हो जायेगा, न जाति के नाम पर आ पायेंगे, न धर्म के नाम पर आ पायेंगे, न पार्टी के नाम पर आ पायेंगे और न क्षेत्रवाद के नाम पर आ पायेंगे, मतदाता की सेवा करेंगे, मतदाता इस लोकतंत्र के मंदिर में आपको भेजने का सार्थक प्रयास करेगी, यह मुझे विश्वास है माननीय सदस्य ।

मैं दो-तीन बातों की चर्चा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने करना चाहता हूँ । पहली चर्चा चूँकि बिना स्वास्थ्य का सृष्टि नहीं हुआ । हम जितने हैं, सभी स्वार्थी हैं, नि:स्वार्थ नहीं । मटिहानी विधान सभा की जनता ने मुझे एक सेवक के रूप में चुना है और मैंने मटिहानी प्रखंड में जमीन परचेज करके अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के लिए दान दिया है । बलहपुर नया गांव में होस्पीटल तैयार हो गये हैं, दो-तीन फीट मिट्टी फिलिंग और चहारदिवारी के अभाव में उस होस्पीटल में मरीजों की सेवा नहीं हो रही है और दूसरा मैंने बरौली प्रखंड के अपने गांव केसाबे में जमीन परचेज करके दान दिया, वह भी होस्पीटल अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र तैयार हो गये, सिर्फ चहारदिवारी और दो-तीन फीट मिट्टी के अभाव में उस होस्पीटल में भी मरीजों की सेवा नहीं हो रही है और तीसरा मेरा क्षेत्र एक साम्हो अकबरपुर अकहा प्रखंड है, टापूनुमा प्रखंड है , 60हजार की आबादी है । वहां भी मैंने मतदाताओं से आग्रह करके भूमि दान में दिलवाया, होस्पीटल तैयार हो गया है । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि सेशन के बाद तीनों होस्पीटल में आप वहां यूनिट भी सैंक्शन है, संसाधन की व्यवस्था करते हुए आप उस होस्पीटल का उद्घाटन कर दें जिससे आमजन को स्वास्थ्य लाभ हो सके । साथ ही डॉक्टर की कमी है, हमारे विपक्ष के साथी ने इस सवाल को उठाया, मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सच्चाई से सरकार को रू-ब-रू कराने का एक सार्थक प्रयास किया, यह आवाज बिहार की जनता के बीच में अवश्य जायेंगे और शायद आप पोजेटिव रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होगा और सिर्फ निगेटिव इस मंच पर ड्रामाबाजी करेंगे तो बिहार की जनता किसी भी कीमत पर आपको बखसने का कार्य नहीं करेगी । यह लोकतंत्र है, किसी का खतियान नहीं, किसी के परिवार की खतियान नहीं, यह खतियान न किसी पार्टी को देखता है, न चेहरा को देखता है, न जाति को देखता है, न धर्म को देखता है, न क्षेत्र को देखता है, न पैसे को देखता है । यह खतियान सिर्फ सेवा को देखता है, जो जनता की अदालत में सेवा करने के लिए हम माननीय खड़े रहेंगे, जनता की अदालत में हम माननीय को सदा आशीर्वाद मिलता रहेगा, यह मुझे विश्वास है माननीय सदस्य भाई । डॉक्टर की कमी है, साम्हो प्रखंड 60हजार की आबादी है और हेडक्वार्टर से 70 कि0मी0 लखीसराय होकर हमलोगों को जाना पड़ता है । बेगूसराय शहर वेलमेन्टेंड शहर है । सैंकड़ों की संख्या में अच्छे होस्पीटल हैं, डॉक्टर हैं लेकिन साम्हो में एक भी प्राइवेट होस्पीटल एवं डॉक्टर नहीं हैं । वहां पेसेंट बीमार हो जाय, अगर रोगी बीमार हो जाय तो रोगी को बेगूसराय लाने में कम से कम 3

घंटे लगते हैं । वहां पर मात्र एक डॉक्टर हैं, माननीय मंत्री जी मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने आपके सिविल सर्जन को कहा, बेगूसराय के कलक्टर को कहा कि साम्हो होस्पीटल में ताला लगवा दो, राम भरोसे जनता रहे, हम गाली सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं राजनीति में, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,साम्हो में आप अतिशीघ्र डॉक्टर की व्यवस्था करा दें, जिससे कि वहां आम-अवाम एन0डी0ए0 को आशीर्वाद देता रहे, प्यार देता रहे और हम जैसा बच्चा इस लोकतंत्र के अदालत में, मंदिर में जनता की आवाज को बुलंद करते रहें । साथ ही एक कठिनाई और है, कठिनाई यह है कि वहां पर दोहन होता है, इसपर आपकी पैनी नजर रहनी चाहिए । सिस्टम में दोष है, आपके जो पदाधिकारी हैं, वे आपके सिस्टम को दूषित करते हैं और बदनामी सरकार की होती है, मंत्री जी की होती है, विधायक की होती है, पार्टी की होती है । मटिहानी प्रखंड के रहने वाले ए0एन0एम0 को साम्हो कर दिया जाता है और साम्हो के जो रहने वाले हैं, उनको बखरी कर दिया जाता है, बखरी वाले को बलिया कर दिया जाता है । डिसटेंस अधिक होने के कारण महिला ए0एन0एम0 ड्यूटी और सेवा देने में सक्षम नहीं हो पाती है । लेट पहुँचती है, उनका दोहन होता है और फिर उस दोहन के आर में डिपुटेशन करके उस ए0एन0एम0 को प्रताड़ित किया जाता है । इसलिए मेरा सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी से आग्रह है .....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त किया जाय ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : सभापति महोदय, दो मिनट । आपने समय तो बताया नहीं..

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : आपको 15 मिनट एलोटेड है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : महोदय, 15 मिनट हुआ कहां ?

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : 15 मिनट हो गया । अब आप कनक्लूड कीजिए न ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी बेहतर कार्य कर रहे हैं । चूँकि मुझे आई0जी0आई0एम0एस0, पी0एम0सी0एच0 प्रतिदिन आने-जाने का मौका मिलता है। मैं एक आदमी को स्पेशल बेगूसराय से आये हुए लोगों की सेवा करने के लिए रखा, किडनी प्रत्यारोपण का कार्य चल रहा है, पी0एम0सी0एच0 में भी प्लानिंग है लेकिन और थोड़े व्यवस्था की आवश्यकता है ..... क्रमशः .....

टर्न-18/अंजनी/दिनांक 06.03.2018

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह :....क्रमशः... मरीज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से मरीज आते हैं, उनको बेड नहीं मिल पाता है, वे नीचे किसी तरह जीवन काटते हैं, बहुत पेसेंट ऐसे होते हैं, जिनको बैरंग वापस कर दिया जाता है, जिसकी शिकायत आपको भी मैंने मोबाइल से

दिया और आपके आदेश से उस पेसेंट का इलाज हुआ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लेकिन बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाके के हर मरीज के पास हर विधायक का फोन नम्बर उपलब्ध हो, ऐसा मुझे संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए आपके समय में हॉस्पीटल में सम्पूर्ण रूप से पारदर्शिता रहे, यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : चूंकि सभापति महोदय, मैं तो उस क्लास का छात्र हूँ, जिस क्लास का नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार को दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया और मैं आपके आदेश को सर आंखों पर रखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय बिहार, जय स्वास्थ्य मंत्री ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी, आपका 12 मिनट समय है ।

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पेश तृतीय अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के लिए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

महोदय, सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है । इस बजट से जनता के हित में समाज के सभी तबके का ध्यान रखा गया है, जिससे राज्य में चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा । महोदय, बिहार का नया बजट मुख्य रूप से मानव संसाधन के विकास और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मजबूत करने पर केन्द्रित है, इस बजट में गांवों की शहरों से दूरी कम करने के लिए प्रावधान पर भी जोर दिया गया है, साथ ही साथ इस बजट में सरकार ने बिहार के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है । महोदय, बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान करके गांवों के किसानों और खेती की तकदीर बदली जा सकती है । वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में गांवों और कृषि के समग्र विकास पर जोर दिया गया है । खेतों की सेहत लेकर सिंचाई, कृषि शिक्षा और बाजार से आगे किसानों की सुरक्षा के जरिये राज्य के दूसरी हरित क्रांति का अगुवा बनाने हेतु सरकार प्रयासरत है ।

महोदय, कृषि रोड मैप में कृषि के अलावे 11 अन्य विभागों यथा- जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, वन एवं पर्यावरण, उद्योग एवं गन्ना उद्योग को सम्मिलित कर तकनीकी सहयोग के जरिए समृद्धि लाने की कोशिश की गयी है । इस बजट में खेतिहर मजदूरों के पोषण, आय बढ़ाने एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर फोकस किया गया है ।

महोदय, बिहार की 70 प्रतिशत आबादी कृषि व्यवसाय से जुड़ी है लेकिन राज्य के अधिकतर किसान प्रशिक्षित नहीं है । किसानों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने

हेतु कृषि शिक्षा जरूरी है । इसके लिए गया में कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज एवं आरा में जैव प्रौद्यिगिकी कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। महोदय, इस बजट द्वारा 54 बाजार समितियों में आधारभूत व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया जायेगा । समितियों के विकास हेतु सड़क, चहारदिवारी, रोशनी, पेयजल, नाला निर्माण कर विकास का कार्य किया गया है । महोदय, खाद्यान्न में पोषण, उपभोक्ता की सेहत और किसानों की आमदनी के लिए सरकार ने सब्जी की खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी अपना कदम बढ़ाया है । पटना से भागलपुर तक गंगा के किनारे तथा दनियावां से बिहारशरीफ तक एन0एच0 तथा एस0एच0 मार्गों के आस-पास के गांवों में जैविक कॉरीडोर विकसित किया जा रहा है । महोदय, पूर्वी चम्पारण एवं मुजफफरपुर जिलों में तीन नये कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है । महोदय, महिलाओं के लिए भी कई तरह की छूट का प्रावधान इस बजट में किया गया है । ड्राइविंग लाईसेंस प्राप्त महिलाओं के नाम पर व्यवसायिक वाहनों का निबंधन कराने पर वाहन कर में शत्-प्रतिशत कर की छूट एवं महिलाओं के पक्ष में सम्पत्ति की खरीद-बिक्री पर दस्तावेज और निबंधन पर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में पांच प्रतिशत की छूट का प्रावधान बजट में किया गया है । महोदय, सरकार की सोच है कि युवा पढ़ेगा तो गांव से शहर तक बदलेगा, जिसके तहत युवा शिक्षा पर बड़ी राशि खर्च की गयी है । सरकार विश्वविद्यालयों के खाली 1354 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति, प्लस-टू हाई स्कूल में गणित, विज्ञान और अग्रेजी पढ़ाने के लिए साढ़े चार हजार अतिथि शिक्षक रखे जायेंगे । 16 जिलों में चल रहे इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलावे पांच अन्य जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जायेंगे । इन कॉलेजों के खुल जाने से संबंधित क्षेत्र से छात्रों का पलायन रूकेगा । महोदय, गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने हेतु अधिकतर पंचायतों में ऑप्टिकल फाइवर केबुल बिछा दिया गया है । पंचायतों में चार सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई सेवा प्रदान करने हेतु मॉडम लगाने का प्रावधान है। महोदय, सरकार आई0टी0 क्षेत्र में भी अग्रिम भूमिका निभाने के लिए तत्पर है । इसके लिए पटना में डॉ0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण, गया में नेशनल काउन्सिल ऑफ साइंस म्यूजियम का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ-ही साथ भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेकनॉलोजी पार्क्स ऑफ इंडिया की शाखा खोलने की सहमति भी दी जा चुकी है । महोदय, सरकार ने कला,संस्कृति एवं युवा विभाग के बजट में फिल्मों के विकास के लिए राजगीर में फिल्मसिटी का निर्माण कराने जा रही है । साथ-ही साथ सरकार ने बिहार राज्य फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति, 2018 बनाने, पांच जिलों में प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी, मधुबनी के रहिका प्रखंड में मिथिला चित्रकला संस्थान निर्माण की भी घोषणा की गयी है । महोदय, सरकार ने इस बजट में खेलों के विकास की ढांचागत मजबूती पर भी जोर दिया है, जिसके तहत

राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम का निर्माण, मोइनुल हक पटना में स्टेडियम का जीर्णोद्धार, प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण प्रमुख है । साथ ही साथ 2018 की खेल नीति तैयार करने के लिए टॉस्क फोर्स का गठन राज्य के आठ जिलों में व्यायामशाला सह खेल भवन के निर्माण की घोषणा भी की है । महोदय, सरकार द्वारा राज्य के चार शहरों यथा पटना, मुजफ्फरपर, भागलपुर और बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु बजट में 200-200 करोड़ राशि की भी व्यवस्था की गयी है । महोदय, सरकार गंगा नदी तट विकास योजना के तहत बजट में पटना सिटी के नौजरघाट से मालसलामी के नूरपुर घाट के बीच 26 घाटों को आपस में जोड़ने का ऐलान भी किया गया है ।

...क्रमशः...

टर्न-19/शंभु/06.03.18

श्रीमती गायत्री देवी : क्रमशः.....महोदय, बहुत लोग बोल रहे थे चिकित्सा में बहुत कमी है । यह पहले था अब कुछ कमी नहीं है । पहले जाते थे हमलोग हास्पीटल में तो कुत्ता को बैठा देखते थे, अब वैसा कुछ नहीं है । अब इतनी अच्छी सुविधा हो गयी है- एक फोन घुमाने पर डाक्टर उपलब्ध हो जाते हैं । जनता को कोई परेशानी नहीं है । चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार ने अधिक ध्यान दिया है । पहले स्वास्थ्य मंत्री कमजोर थे बच्चा थे, बांसुरी बजाते थे, अब तो स्वास्थ्य मंत्री भी मजबूत हैं । महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार ने अधिक ध्यान दिया है । वित्तीय वर्ष 2018-19 बजट के स्वास्थ्य मद में 7793 करोड़ रूपये के प्रावधान से सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधा एवं चिकित्सा मुहैय्या कराने के लिए राज्य में दो स्टेट कैंसर संस्थान, सात मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आइ0 बैंक, पी0एम0सी0एच0 में बेड बढ़ाने और किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा, आइ0जी0आइ0एम0एस0 में लीवर प्रत्यारोपण शुरू किया गया है । 244 प्रकार की निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने की योजना है । महोदय, सरकार ने उपभोक्ता को निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु समेकित ऊर्जा विकास योजना के तहत राज्य के 133 शहरों में 2100 करोड़ रूपये की लागत से 62 नये पावर सब स्टेशन का निर्माण कराने जा रही है । महोदय, सरकार राज्य में कानून का राज स्थापित कर रही है । इसके तहत संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और विधि व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। पुलिस तंत्र को ठीक किया जा रहा है ताकि अपने दायित्व का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सके । महोदय, सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु कृत संकल्पित है । आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को सभी घरों को उपलब्ध करायी जा रही है। विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत गांव या शहर के सभी घरों के नल का जल, शौचालय, गली, नाली एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । महोदय, हर घर नल का जल निश्चय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 10 हजार 544 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है । 1195 वार्डों में कार्य पूर्ण हुआ है तथा 2 लाख 25 हजार घर आच्छादित हुआ है । शहरी क्षेत्रों में अब तक 1250 वार्डों में अब तक कार्य प्रारंभ किया गया

है । कुल 4 लाख 72 हजार घरों को नल के जल की सुविधा दी गयी है । महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार ने बजट में खास ध्यान दिया है । इसके लिए बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म से जुड़े स्थलों के विकास पर भी जोर दिया गया है ताकि राज्य में अधिक से अधिक पर्यटकों का आगमन हो सके । महोदय, सरकार ने सामाजिक बदलाव हेतु जन अभियान चलाया है जिसके तहत दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत 21 जनवरी 2018 को 14 हजार 600 कि0मी0 लंबी मानव श्रृंखला में राज्य के 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाग लिया । यह अभियान समाज के कई त्रुटियों को दूर करेगा । महोदय, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में सभी क्षेत्रों के विकास पर बल दिया है ताकि राज्य में चहुमुखी विकास हो ।

एन0डी0ए0 की सरकार राज्य में विकास के लिए प्रतिबद्ध है । जिसके कारण राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है । महोदय, स्वास्थ्य विभाग पर आज बोलना है ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए, समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, महिला हैं महिला के नाते थोड़ा तो मौका दिया जाय। आज स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा है सभी चीज पूरक है, इसलिए सभी चीज पर चर्चा किये हैं । आज स्वास्थ्य विभाग में जो यह बदलाव हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ था । जब एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो आज व्यवस्था सुधरी है । हम भी सीतामढ़ी में थे और सीतामढ़ी मेरा जिला है । वहां भी हास्पीटल अस्त-व्यस्त हो गया था । आज जाते हैं तो सिर उठाकर देखते हैं और मन में गर्व होता है कि हम सरकार में हैं । हमारे स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं । हर विभाग में दवा उपलब्ध, सुई उपलब्ध सब चीज उपलब्ध है, किसी चीज की कमी नहीं है सिर्फ आपलोगों के मन की कमी है । जिस दिन मन बना लीजिए आपका बिहार विकास करेगा । अब मन की कमी है अपने मन को मजबूत कीजिए । बिहार में देखिए जो महिला घर में बैठी थी आज गौरव से चलती है । आज किसी चीज की परेशानी नहीं हो रही है । मेरा घर सीतामढ़ी में हास्पीटल के बगल में है और किसी चीज की कमी नहीं है । वहीं पहले सुई नहीं मिलता था, रूई नहीं मिलता था, बार-बार लोग चिल्लाते थे, लेकिन आज सभी चीज की सुविधा है ।

(व्यवधान)

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : आपस में बात मत कीजिए । अब समाप्त किया जाय। स्वीटी जी, आप आपस में क्यों बात करती हैं ?

श्रीमती गायत्री देवी : आज एम्बुलेंस की कमी नहीं है, घर से हास्पीटल ले जाता है । आज एम्बुलेंस की सुविधा हो गयी है, इसमें कोई कमी नहीं है । पहले एम्बुलेंस नहीं मिलता था, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पी0एम0सी0एच0 के बगल में जो मर गया था वह बाहर रखा था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : हो गया अब समाप्त किया जाय, पांच मिनट अधिक बोल चुकी आप ।

श्रीमती गायत्री देवी : अब ऐसा नहीं है बिहार में बहार है । हमारे स्वास्थ्य मंत्री अच्छे हैं । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं । यही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, आज तृतीय अनुपूरक बजट और स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जो तृतीय अनुपूरक बजट है और जो मुख्य बजट जो पेश किया गया इस बजट की कुछ खामियां और इस बजट में आम जनता को कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है जिससे लगे कि बिहार का बजट आम साधारण गरीब का बजट हो । इस बजट का जो एक बिन्दु हम बताना चाहते हैं वह बिन्दु है कि रजिस्ट्री में इन्होंने जो पब्लिक से रीलेटेड केस है निबंधन विभाग के द्वारा रेट बढ़ा दिया गया, आम किसान मजदूर अगर जमीन खरीदने जायेंगे या जमीन बेचने जायेंगे। जमीन खरीदना और जमीन बेचना दोनों मजबूरी की स्थिति होती है । जमीन जो बेचता है अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वह जब जमीन बेचने के लिए जाता है ।

क्रमशः

टर्न–20/अशोक/06.03.2018

श्री अवधेश कुमार सिंह : क्रमशः तो वहां पर टैक्स बढ़ा दिया जाता हैं, उसका रेभन्यू बढ़ाया है निबंधन में, इस बजट में हमको देखने का मौका मिला है । शिक्षा विभाग, जो आज आर.एस. पाण्डेय जी भारत सरकार के भी सचिव स्तर के पदाधिकारी रहे हैं, बिहार में तो तीन बजट देखें हैं, भारत सरकार में अनेक बजट देंखे होंगे, अनेक विभागों के अच्छे पदाधिकारी रहे थे । इस बजट में यू.पी.ए. गर्वनमेंट ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश के सभी राज्यों को सर्वशिक्षा के माध्यम से शिक्षा विस्तार करने का मौका दिया मगर आज भी इस बिहार में 15 साल हमारे नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया रहे हैं, कमो बेस, आज भी गांव में, दलित के गांव में, पिछड़ों के गांव में, प्राथमिक विद्यालय नहीं है । हम लिखकर भी दिया है और आज सदन को बतलाना चाहत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान देना होगा । देश एक मोदी में फंसा हैं और बिहार दो मोदी में फंसा है । देश में नोटबंदी आया, नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ? देश में नोटबंदी से कहां से काला धन आया, आज तक देश के आवाम जानना चाहता है मगर आज भी आवाम को नहीं मालूम है और बिहार में छोटे मोदी जी, इस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वह मोदी जी काल धन को रोकना नहीं चाहते थे, किसी पार्टी पर प्रहार करना चाहते थे । आज नोटबंदी में अगर इस देश में किसी एक व्यक्ति को फायदा हुआ है तो एक संस्था है भारतीय जनता पार्टी । उस नोटबंदी में, अखबारों में आप देंखे होंगे आज बिहार की स्थिति क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, महागठबन्धन के

भी मुख्यमंत्री थे, हम मुख्यमंत्री का सराहना करते हैं, मगर मुख्यमंत्री के जो सात निश्चय है, वह सात निश्चय का मटियामेट कहां हो रहा हैं, चाहे पक्ष के विधायक हो चाह विपक्ष के विधायक हो, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा के सदस्य हैं आज बिहार में बालू की स्थिति क्या है ? गिट्टी की स्थिति क्या है ? बिहार से मजदूर पलायन कर रहे हैं, आर.एस. पाण्डये साहब, आप तो बुद्धिजीवी आदमी थे, बालू की कमी आपके जिले में हैं या नहीं ? बिहार के सभी जिले के सदस्य इस सदन में बैठे हैं, सात निश्चय कार्यक्रम, एक अच्छा कार्यक्रम है, सात निश्चय का नाली किस चीज से बनेगा ? सड़क का पक्कीकरण का क्या होगा ? हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री बैठे हैं हजारों कि.मी. सड़क की घोषणा ये करते हैं, अगर पत्थर नहीं मिलेगा तो सड़क का निर्माण कहां से होगा ? बालू और गिट्टी नहीं मिलेगा, चन्द्रसेन इस्लामपुर के हो, बगल में फल्गु नदी है, जहानाबाद से तुमको मिल रहा होगा मेरे भाई, आप उस जिले के विधायक हो जो जिला हिन्दुस्तान में जाना जाता हैं, नालन्दा । बिहार में अगर कोई एक मिट्टी भी जायेगा तो वह नालन्दा जायेगा, वह गया नहीं जायेगा, भगवान बुद्ध की धरती है गया, जहां बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त किये थे, उस गया में नहीं जायेगा। कहां जायेगा ? जरासंध की नगरी नालन्दा। जो बने नालन्दा, हम कहना चाहते हैं कि सात निश्चय से आज सभी विधायक है सभी लोग चाहेगा कि हर वार्ड में हर पंचायत में गल, नली पक्की सड़क बने, जिस दिन सरकार ने यह संकल्प ले लिया कि गली, नली, सड़क हम सरकार अपने खजाने से बनायेगी तो विधायक कोष की क्या आवश्यकता है ? विधायक फंड, जो विधायकों को दिया जाता है सभी विधायक को मिलता है, यह विधायक फंड, विधायक करते क्या हैं ? उसी गली, उसी नली का निर्माण कराने का काम करते हैं और आज विधायकों का वह गली नली रूका हुआ था, आज गली नली का आपने परमिशन दिया है, चापाकल विधायक कोटा में नहीं है, चापाकल कोई विधायक अपने घर में लगाता था ? कि विधायक क्षेत्र में देता था, पंचायत में देता था, सात निश्चय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय है, पर सात निश्चय कार्यक्रम का इम्पलीमेंटेशन, उसकी सफलता, उसकी गुणवत्ता को जांच कराने का काम मुख्यमंत्री जी करें वो काम आपको करना होगा, सरकार में आप हैं सरकार के जो सदस्य हैं नहीं बोल पाते हैं । मगर हम विपक्ष के लोग आपको आइयना दिखलाने का काम कर रहे हैं कि आप सात निश्चय का रेण्डम, आप अपने किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री को, किसी भी क्षेत्र में भेज कर एक इमानदारी से अपने विधायक से, अपने सदस्य से जानकारी ले लें कि सात निश्चय का क्या स्थिति है, कौन नहीं चाहेगा चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के हों सभी लोगा चाहेगा कि सात निश्चय का कार्यक्रम हो, तो सात निश्चय जनहित से जुड़ा हुआ

मामला है, तो सात निश्चय के बारे में सच्चाई बतलाने का भी काम जनहित से जुड़ा हुआ है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या चाहे विपक्ष के विधायक हों बतलाना चाहिये मगर आप नहीं बता पा रहे हैं, हम बताने का आपका जिम्मा लिया है, अभी आप सुने रवीन्द्र भाई आप अध्यक्ष महोदय इस राज्य में, इस राज्य में लघु सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग का निर्माण किया गया था, उसका उद्येश्य था कि लघु सिंचाई मतलब लघु, छोटा सिंचाई का साधन मुहैया कराया जाय, उस छोटा में सभी हमलोग गांव से आते हैं कुछ लोग शहर से आते होंगे हर गांव में हर पंचायत में पोखर, आहर है । देश का प्रधान मंत्री बोलता है कि देश का जलवायु बोलता है कि पानी का संरक्षण करो, पानी संरक्षण करो संरक्षण तो किसी तशला या बटलोही में होगा नहीं, वह उसी गांव के पोखर में होगा, लघु सिंचाई विभाग बैठा है, हर जिले में आंकड़ा उठाकर देंख लें, किस जिले में लघु सिंचाई विभाग ने कितने आहर, कितने पोखर का पुनर्जीवित किया है ? यह सच्चाई यही है , सच्चाई है, विपक्ष का काम है आइना दिखलाने का, हम आइना दिखला रहे हैं, आप को जो अच्छा लगे ग्रहण कीजिये और जो न अच्छा लगे, मेरे माथे पर पटक दीजिये । मगर सच्चाई यह है कि राज्य में आज जो आप बालू और ईंटा और गिट्टी की मारामारी हो गई है । हम गया से आते हैं, गया में 3500, 100 सी.एफ.टी का 3500 रूपया लग रहा है, जो बालू 500, 700, 800 में हुआ करता था । हमारा इन्दिरा आवास, वह आवास ऊपर से जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, आपने कार्यक्रम किया है, उन दलित को आप मकान बनाने लिये पैसा दे रहे हैं, राज्य सरकार देर ही है और जब तक उसको बालू और ईटा नहीं मिलेगा तो उसके घर का निर्माण कहां से होगा ? यह बालू सिर्फ एक व्यक्ति, एक दल को रोकने के लिए आपने, सुशील मोदी ने यह जो कार्रवाई किया, वह बिहार की जानता आपको माफ नहीं करेगी । हम कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि यह जो लघु सिंचाई विभाग है, इसको सुदृढ़ करना होगा और इसकी फंडिंग करनी होगी । अगर पानी, जल स्तर हमलोगों के जिला खासकर के मगध में जल स्तर नीचे जा रहा है । क्रमशः

टर्न-21/ज्योति/06-03-2016

क्रमशः

श्री अवधेश कुमार सिंह : अगर पानी का जल स्तर हमलोगों के जिला में खास करके मगध में नीचे जा रहा है । अभी गर्मी आयी नहीं है, चापाकल सूख रहा है और कल के दिन जिसतरह से गर्मी का प्रकोप होगा, हमारे गरीब, मजदूर, किसान पानी के लिए तरसेंगे । अगर लघु सिंचाई विभाग हर पंचायत में, हर गांव में वह जो सरकारी तालाब है उसको पुनर्जीवित कर दिया होता तो निश्चित तौर पर बिहार में जलवायु भी ठीक

होता और बिहार के किसान और मजदूर और आने वाली जो भयावह स्थिति है – नर नारी तो कहीं पानी पियेंगे, मगर पशु पक्षी को पानी का अभाव होने जा रहा है । माननीय सभापति महोदय, यह हम बताना चाहते हैं । हमारे जितनी भी योजनायें जो बजट में दी गयी हैं सब में कटौती का प्रस्ताव दिया गया है । यह कटौती , जो काटे हैं आप, ये काटना और एक तरफ आप 1 लाख 76 हजार करोड़ की घोषणा करना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर लगता है । एक तरफ 1 लाख 76 हजार करोड़ का बजट दे रहे हैं और दूसरी तरफ सभी विभागों के फंडिंग में कटोती कर रहे हैं । वह कटौती क्या है, आप कटौती को जोड़कर आप बजट पेश किए रहते हैं । यह जरुरी नहीं है कि आप गुजरात से तुलना कीजिये । आपका राजस्व जो बिहार का है, बिहार की पृष्ठभूमि है, इसपर आप विचार करें । बिहार में पिछली बार आप कहते थे जंगल राज, जंगल राज । मंगल राज में बिहार में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री आपने बैठा दी ? एक इंडस्ट्री की बात करें । आप बिहार में सिवाय जुमलेवाजी करके आप शासन कर रहे हैं । मैन्डेट मिला था महागठबंधन को, मैन्डेट है महागठबंधन का और आज बैठे हैं एन.डी.ए. ? यही सामने हमारे संजय सरावगी साहेब मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे थे । हम भाई सरावगी जी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और आज सरावगी साहेब उसी सरकार को महामंडित कर रहे हैं और हम जो शपथ लिए थे, हमने जो शपथ लिया था कि आर.एस.एस. मुक्त भारत बनायेंगे, आज कह रहे हैं कि आर.एस.एस. युक्त भारत रहेगा, यह आपका नारा है । हम थोड़े ही बोल रहे हैं । हमने कहा, अरे थोड़ा बैठिये न ।

(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार): दूसरे प्रसंग में बोला है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, हम बता रहे हैं कि 18 महीने में भी और संजय सरावगी साहेब 1980 में एम.एल.ए. होकर आया हूँ इस सदन में और मेरा सौभाग्य है कि एक लम्बा काल इस सदन में रहे हैं । मैं छोटे भाई, बड़े भाई, बड़े लोग हैं यहाँ और कुछ अनुभव है, उसकी जानकारी दे दें । गोगा बाबू हमारे अच्छे छोटे भाई हैं । बनाने में गोगा बाबू भी साक्षात गवाह है कि हमने जो योगदान दिया है, वह बतायेंगे गोगा बाबू कभी अकेले में, सरावगी साहेब आप उस दिन को नहीं देखें हैं । उस दिन कहाँ थे, उस दिन तो दूध का दांत था आपका, आज बता रहे हैं कि आज सभापति महोदय, ये सारे विभाग में जो कटौती आप कर रहे हैं जो आप बजट एलोकेशन कम कर दिए और खास करके क्या संदेश देना चाहते हैं ? ठहरो यार । आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि रवींद्र यादव जी भा.ज.पा. के नेता हैं । ये पैदा लिए है कौंग्रेस के गोदी में तो आज भाजपईया हो गए ? ये पैदा लिए हैं आर.जे.डी. के गोदी में, आज नया नया मियाँ प्याज खाने चले हैं । मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, कि

आज स्थिति निश्चित विजय बाबू आपका शपथ है और जो आपका कारनामा है, आपने कौंग्रेस मुक्त मणिपुर किया, कौंग्रेस मुक्त गोवा किया, आपने कौंग्रेस मुक्त मेघालय किया । ये आपकी बढ़ोत्तरी है, यही नोटबंदी है, यही नोटबंदी है । मेरे भाईयों यह नोटबंदी का कमाल है, और बिहार में बहार है भा.ज.पा. की सरकार है । यही बिहार है मेरे भाईयो । मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो अच्छा काम हुआ है । बिहार के गांव में बिजली पहुंची है उसके लिए विजेन्द्र यादव जी को बधाई देंगे, मंत्री हैं बिजली विभाग के । आज बिहार में जो काम हुआ है । जरा ठहरो भाई ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): जरा समय का ध्यान रखा जाय ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अभी तो 20 मिनट मेरा समय था । मेरा जो पार्टी का समय है उसके अंदर ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): बस दो मिनट बचा है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : हमारा पॉच मिनट है अभी । आज हेल्थ की चर्चा हो रही है । हेल्थ में सारे लोग पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बांसूरी बजता था लेकिन हेल्थ में जो बजट प्रोविजन था 16 और 17 में वह 5.69 था और 2018-19 में घटकर 4.4 हो गया है । यह स्वास्थ्य विभाग का आपका एलोकेशन है । हमारा नहीं है । यह आपका है । मेरा कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के हमारे मंगल पाण्डे जी अच्छे मेरे मित्र भी हैं । अच्छे मंत्री भी हैं मगर जो बिहार में मेडिकल कॉलेज मगध मेडिकल कॉलेज, गया में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अपने शासनकाल में बनाया था, हमने ....

(व्यवधान)

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : क्या व्यवस्था है ?

श्री मो0 नेमतुल्लाह : माननीय सदस्य ने कहा कि नया नया मिया प्याज खाता है इसको हटा दीजिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : हम आपको थोड़े ही बोले हैं हम रवींद्र यादव को बोले हैं । हमने कहा कि गया के मगध मेडिकल कॉलेज जो टेक ओवर के टाईम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आज उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । आज मगध मेडिकल कॉलेज में शिक्षक की कमी है । डौक्टर की कमी है और आप एक अच्छे मंत्री हैं । आपके नॉलेज में देना चाहते हैं इस सरकार में बैठे हुए लोगों को । मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कोटा में गरीब दलितों के जो मस्तिष्क रोग से जो व्यक्ति की मृत्यु होगी, उसको 50 हजार अनुदान देने का प्रोविजन किया गया है, पत्र संख्या 45419, दिनॉक 25-06-2012 में यह संकल्प लिया गया है । हमारे जिला में यह जो बना है जन शिकायत केन्द्र इसमें भी वह दलित कपिल मांझी जो रसना गोंव का रहने वाला है जिला- गया, मानपुर- प्रखंड का है, इसकी बेटी मांझी जाति की है

। वह मस्तिष्क ज्वर से मर गयी और कमीशनर की चिट्ठी और सिविल सर्जन की चिट्ठी के बावजूद आज तक स्वास्थ्य विभाग उसका पेमेंट नहीं करा पाया है । माननीय मंत्री जी ये आपके स्वास्थ्य विभाग का निकम्मापन है । आपसे अनुरोध करेंगे कि सरस्वती कुमारी जिसका पिता कपिल मांझी है जिसके लिए कमीशनर मगध सिविल सर्जन, गया आपको लिखे हुए है और उसके बाद भी विभाग की अकर्मण्यता के चलते उस गरीब दलित का चूँकि दलित गरीब इस सचिवालय के गेट के अंदर आपके बाबू को सलाम नहीं कर सकता है, बाबू को पान नहीं खिला सकता है इसलिए उसका भुगतान नहीं हुआ है । माननीय मुख्यमंत्री का स्पेशल और्डर है पूरे बिहार के मस्तिष्क रोग के बीमारियों के लिए । सभापति महोदय, आपने कहा समय खतम हो गया । दो तीन बिन्दुओं को बताना चाहते हैं कि आज एक बात की चर्चा सदन में बड़े गर्मजोशी से हमारे सत्ता पक्ष के लोग करते हैं और हम विपक्ष के लोग खास करके हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप रहते हैं । चरवाहा विद्यालय की चर्चा हो जाती है । अरे भाई चरवाहा विद्यालय का वीजन जो लालू प्रसाद ने दिया था, इस राज्य के सामन्तवादी लोग, उस वीजन को पूरा नहीं होने दिया । अगर चरवाहा विद्यालय में एक गरीब चरवाहा अपना गाय, बैल, भैंस ले कर अगर उस मैदान में चरवाहा करेगा , वहाँ पढ़ाई करेगा, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत में वह वीजन था ।

क्रमशः

टर्न–22/06.3.2018/बिपिन

श्री अवधेश कुमार सिंहः क्रमशः उस चरवाहा विद्यालय के संस्थापक हमारे माननीय विधायक श्याम रजक भी थे और उस विजन को चूंकि श्याम रजक बुद्धिजीवी आदमी हैं, बुद्धिजीवी आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा । चरवाहा विद्यालय विजन था । उस विजन को, हम सरकार से कहेंगे कि उस विजन को लें और आज जो बिहार में चरवाहा विद्यालय के लिए जगह जो बनाया गया है वहां आप कौन विद्यालय खोंलेंगे, आप निर्णय लें । इन्हीं शब्दों के साथ आपको सभापति जी बहुत–बहुत बधाई । आपने मुझे मौका दिया, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं । जय हिन्द । जय भारत ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठः सभापति महोदय, सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तृतीय अनुपूरक के माध्यम से जो मांग रखी गई है, उसपर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं सरकार द्वारा मांगी गई दुगुनी राशि का भी समर्थन करता हूं, ठीक से सुनिए, महोदय, मैं सरकार द्वारा मांगी गई दुगुनी राशि का भी समर्थन करता हूं यदि सरकार की नीयत सही होती और सदन द्वारा पारित राशि का सदुपयोग होता लेकिन ऐसा

नहीं हुआ । सरकार प्रत्येक वर्ष सदन से बजट सत्र में मांगों को पारित कराती है और प्रायः दो-तीन अनुपूरक लाए जाते हैं । इन राशियों का सदुपयोग किया जाता है तो इस राज्य की गरीब जनता निजी चिकित्सकों में, निजी अस्पतालों और राज्य के बाहर के अस्पतालों में शोषित होने के लिए विवश नहीं होती । चलिए पी.जी.आई., लखनऊ, चलिए पी.जी.आई., चंडीगढ़, एम्स, चेन्नई, मुंबई आदि जगहों पर, वहां आप पाएंगे कि बिहारियों की सबसे ज्यादा भीड़ यहां के अस्पतालों और चिकित्सकों के यहां है । आखिर यह स्थिति क्यों है ? हम क्यों कर्ज लेकर जमीन-घर बेचकर बाहर इलाज कराने के लिए विवश हैं? इस पर सदन को चिंतन करने की आवश्यकता भी है । महोदय, हमारे यहां सुविधाएं लगभग शून्य की स्थिति में पहुँचने जा रही है । राज्य में स्वीकृत बल के विरूद्ध 30-35 प्रतिशत् चिकित्सक कार्य कर रहे हैं । क्षेत्रीय स्तर के अस्पतालों में बहुत बुरी स्थिति है । वहां के ए.पी.एच.सी. और पी. एच.सी. आयुष चिकित्सकों के ही भरोसे चल रहा है, दरभंगा छोड़कर, चूंकि दरभंगा डी.एम.सी.एच. पर बहुत ध्यान आपका रहा है, इसीलिए दरभंगा छोड़कर । क्षेत्रीय स्तर पर अस्पतालों की बुरी स्थिति है। कल ही हमने चर्चा किया था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी मधुबनी में और उसे एक कुत्ता ने काटा और जो विस्तृत हमने चर्चा की है, काफी है समझने के लिए । काश ! हम समझते हैं कि वैसी परिस्थिति अगर आपके पी.एच.सी., अगर यहां पर जो हम समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जापान गए थे, दूसरे विदेश में गए थे, वहां पी.एच.सी. जो है, वह हमारा अपोलो और मेदान्ता से ज्यादा अच्छा है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों से अनवरत आपलोगों का प्रयास चल रहा है, निश्चित तौर पर आप अच्छे ढंग से चला भी रहे हैं लेकिन हम जो वृतांत सुना रहे हैं, उसको थोड़ा सोच के साथ ग्रहण करिए ताकि बिहार आपका है, बिहार हमलोग का है, बिहार में बहुत लोग बाहर से आते हैं तो नेपाल के लोग ही ज्यादा आते हैं और ज्यादा दरभंगा ही में आते हैं या मुजफ्फरपुर आते हैं । उससे ज्यादा पटना छन कर अगर आते हैं, चलिए, कोई बात नहीं है, हमारे राज्य में सिर्फ चिकित्सकों की ही खाली कमी नहीं है, पारा मेडिकल स्टाफ भी नहीं है । ए.एन.एम. की भी कमी है जिनकी नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग को दायित्व मिला लेकिन घोटालों के इस दौड़ में वह भी अछूता नहीं बचा और ए.एन.एम. की बहाली अधर में लटकी पड़ी हुई है । हॉं, सिर्फ महात्मा गांधी से प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्रीजी स्वच्छता के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं, पूरे देश में जागरूकता पैदा कर रहे हैं । मैं इसे सराहनीय मानता भी हूं और स्वास्थ्य विभाग में अपने प्रधानमंत्री की भावना को समझता हूं । आप किसी भी अस्पताल, कहीं भी चले जाएं, हमारे साथ बी.जे.पी. के भी साथी जा सकते हैं, जदयू के भी साथी जा सकते हैं, कहीं चलें, चयन आपलोग करें कि किस अस्पताल में जाना है, किस जिला स्तर के हॉस्पिटल में जाना है, किस पी.एच.सी. में जाना है,

किस ए.पी.एच.सी. में जाना है, निर्णय आप करें । चलने के लिए हमलोग तैयार हैं और वहां की परिस्थिति और भावना से जब आप अवगत होंगे तो लगेगा कि जो पंद्रह वर्षों से अनवरत आपका प्रयास चल रहा है, कहीं-न-कहीं आपको और सोचने पर विवश करेगा कि कैसे हम बिहार की सेवा करें और हम समझ सकते हैं । साथ ही, बीमार का इलाज, बीमारियां चाहे आपके माता हों, पिता हों या किसी का भी सेवा जब हमलोग करने जाते हैं, उनके लिए सोचते हैं, वहीं सेम परिस्थिति सबों के लिए झेलना पड़ता है । बीमार का इलाज कराने हेतु जाने वाले परिजन स्वयं बीमार हो जाते हैं । जब आप वहां जाते हैं जिसकी चर्चा हमने की, आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे बीमारियों को ले करके, हो सकता है आप खुद ही बीमार पड़ जाएं । आप स्वस्थ हैं लेकिन आपको लगेगा कि हम बीमार खुद भी पड़ रहे हैं । किसी भी अस्पताल में स्वच्छ पेयजल का अभाव है । पेयजल के लिए कहीं-कहीं नल है लेकिन उसके चारो तरफ जो गंदगी का अंबार है वह देखने लायक है, दरभंगा को छोड़कर । शौचालय की जो स्थिति है, बहुत खराब है । किसी शौचालय की सफाई नियमित रूप से नहीं होती है दरभंगा को छोड़कर । ओ.पी.डी. के बाहर से चिकित्सकों द्वारा देखे जाने वाले प्रतीक्षा करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं । दवाई मिलना है न ! लेकिन वहां जाकर आप देखें- न बैठने के लिए प्रॉपर पंखा है, न जगह है, न व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न कुर्सी है, न बेंच है, आखिर इतनी बड़ी धनराशि लेकर सरकार कर क्या रही है ? आखिर पैसे कहां जा रहे हैं ?

महोदय, मैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ आंकड़ों का जिक्र कर देना आवश्यक समझता हूं । नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पाया गया कि राज्य की 21 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का शारीरिक गठन और वजन सामान्य से नीचे है । पांच साल तक के 64 प्रतिशत् बच्चे खून की कमी से ग्रस्त हैं। 15 से लेकर 39 वर्ष के 60 प्रतिशत् महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त हैं । राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जो आपलोग ने ढिंढोरा पीटा और हमलोगों ने सुना, सदन इसके लिए गवाह है । उसके लिए यह दर्पण का काम करेगा कि ग्रामीण क्षेत्र की 12 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिशत् 4 प्रतिशत् महिलाओं का छाती और 5 प्रतिशत महिलाओं के दातों की जांच की गई । इतना ही नहीं, एच.आई.वी. एड्स की जागरूकता में बड़ी-बड़ी बातें सेमिनार करने वाली सरकार की यह स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों का मात्र 8 प्रतिशत् महिलाएं एच.आई.वी. एड्स के बारे में थोड़ा कुछ जानती है । मतलब अवेयरनेस की जरूरत है । जानकारी देने की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

आप डाक्टर हैं, मित्र हैं, छोड़िये । महोदय, जहां गर्भवती...

(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): टोका-टोकी मत करिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ: महोदय, जहां गर्भवती महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 54 है, वहीं राज्य में केवल 32 है जो अभी चर्चा हो रही थी, केवल 32 है ।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का 3 प्रतिशत् ऐसी है जिनकी गर्भावस्था के दौरान पूरी जांच नहीं हो पाई है । यही हाल है स्वास्थ्य का और आश्चर्य है कि ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का। फिर आगे चलेंगे । फिर आगे साथ रहेंगे, चिंता नहीं करिए । महोदय, अब हाल जाना जाए बच्चों का। राज्य के क्षेत्र में 44 प्रतिशत् बच्चे अंडरवेट हैं । महोदय, राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर जो 50 प्रतिशत् है, पांच वर्षों का मृत्यु दर यहां 60 प्रतिशत है । इसलिए महोदय, राज्य में जनसंख्या विस्फोट है । देश की सबसे अधिक आबादी के घनत्व का यह प्रदेश है । बार-बार मुख्यमंत्रीजी इस बात की चर्चा भी करते हैं । इस प्रदेश में जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय को लागू करने की जिम्मेवारी किसी दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं, स्वास्थ्य विभाग का ही है । ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में बंध्याकरण का प्रतिशत् केवल 19 प्रतिशत है...क्रमशः

टर्न : 23 / कृष्ण/ 06.03.2018

श्री समीर कुमार महासेठ (क्रमशः) महोदय, कैसे हम जनसंख्या पर नियंत्रण पायेंगे ? जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारी जमीन सिकुड़ रही है, हमारी गरीबी बढ़ रही है । उस पर नियंत्रण पानेवाला एक मात्र विभाग है स्वास्थ्य विभाग । लेकिन स्थिति भयावह है । महोदय, सरकार समय-समय पर अपनी पीठ थपथपाती रहती है । जब भी कोई सरकार बनती है तो शायद अपने सरकार के प्रति अगर ये सोच बना लें कि जो सरकार सही काम करती है, उसको हम जरूर कहेंगे कि वह अच्छी सरकार है, उसकी पीठ थपथपाई जाय । लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो पक्ष-विपक्ष एक हो करके सरकार उस दर्पण हिसाब से उसकी आंख खोलने का काम करें । तभी जा करके सशक्त विरोध हो पायेगा । सरकार अपनी ज्यादा पीठ थपथपाती नहीं रहे । मैं ज्यादा आंकड़ा नहीं प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि 2017-18 के बजट में शहरी सदर,अनुमंडल अस्पताल के दवा भण्डार मद में आवंटन केवल 39 करोड़ था ।

(व्यवधान)

उस समय 50 लाख रूपये का प्रावधान था संजय जी । 2017-18 में 39 करोड़ था, 2018-19 में उसको घटाकर मात्र 30 करोड ़कर दिया गया । 50 से 30 कर दिया गया ।

महोदय, अंधेपन की रोक-थाम के लिये 2017-18 में 15 करोड़ 19 लाख रूपये की व्यवस्था बजट में की गयी थी परन्तु राज्य में कहीं भी कोई कारगर व्यवस्था नहीं देखता हूं ।

महोदय, शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में तथा बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम में 2017-18 में उपबंध शून्य रहा । बुजुर्ग राष्ट्र के धरोहर होते हैं, स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार सजग रहती तो तो अपने तौर से भी इस मद में राशि उपबंध कर सकती थी ।

महोदय, ये तो छिट-पुट उदाहरण हैं । राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तौर से ध्वस्त है । महोदय, बार-बार आप एम0सी0आई0 की चर्चा करते रहे । एम0सी0आई0 के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण कॉलेज अस्पतालों पर एम0सी0आई का प्रतिबंध लगता है जिसके कारण पढ़ाई की अनुमति नहीं दी जाती है । भाई संजय सरावगी जी, दरभंगा के लिये एम0सी0आई0 के निर्देशों को बार-बार बताते रहे हैं लेकिन इसके बावजूद नेशनल आंकड़ों के हिसाब से जहां कैरेक्टर्स ऑफ एडल्टस एज 1549 है, वहां वुमेन्स लिटरेसी 70 प्रतिशत से लेकर रूलर में 46 प्रतिशत है । अगर विभिन्न क्षेत्रों में कहा जाय तो संजय जी आप खुद बतायेंगे कि हम कहां है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, एक बात की चर्चा करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी मधुबनी गये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मधुबनी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा । निश्चित तौर पर क्या कारण है मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मधुबनी में 5 किलोमीटर के रेडिअस में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं तो एनाउंसमेंट करते हैं कि मेडिकल कॉलेज झंझारपुंर में खुलेगा । तो क्या हम यह माने कि मधुबनी में दो मेडिकल कॉलेज खुलेंगे - एक झंझारपुर में खुलेगा और दूसरा मधुबनी के 5 किलोमीटर के रेडिअस में खुलेगा । अगर नहीं तो इस बात के लिये आप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके आप इसका निर्णय कर लें कि क्या करना है । मेरा मानना है कि आप जितने भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, आवश्कता नहीं है खोलने का । क्योंकि पहले का जो भी मेडिकल कॉलेज खुले हुयें हैं, पहले उसको चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता है, उसको ढंग से चलाने की आवश्यकता है । एम0सी0आई0 के ऐक्ट के हिसाब से उसको पूरा करने की आवश्यकता है । एक-एक पेशेंट को संतुष्टि देने की जो आवश्कता है, उसके परिवार को वह देने की आवश्यकता है । जिस दिन आप उसको आवश्यकता को पूरा कर लीजियेगा तब जाकर अन्यत्र 7, 9, 10 जितने भी मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यता है, आप खोलिये । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जेनरिक दवा के लिये कम से कम आप तुरंत आर्डर करें । हरेक अस्पताल में जेनरिक दवा कम से कम मूल्य पर गरीब जनता को मिल सके । इसको आप करने का निर्णय लें । आपके हॉस्पीटल के प्रांगण में दवा बेचने के लिये जो जगह दिया जाता है, उसमें वह बाहरी दवा बेचता है । क्यों ? जब जेनरिक दवा के लिये आप अस्पताल

के प्रांगण में जगह देते हैं तो वह बाहरी दवा क्यों बचेंगा ? वैसे लोगों को वहां जगह क्यों देंगे ?

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : एक मिनट में समाप्त करता हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मधुबनी जिला का एक पण्डौल और दूसरा रहिका प्रखंड में जितने स्वास्थ्य केन्द्र,उपस्वास्थ्य केन्द्र हैं, जब जो भवन आपके द्वारा बनाया गया है, वास्तव में वे भवन बने ही नहीं लेकिन उसे पूर्ण दिखाया जा रहा है । हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना चाहेंगे कि पण्डौल, रहिका और मधुबनी सदर अस्पताल पर आप ध्यान दें और एक कमिटी बना दें और कम से कम जनता की आवश्कताओं को पूरा करने का प्रयास करें ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम । आप अपनी बात शुरू कीर्जिये ।

श्री सत्यदेव राम - सभापति महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के मांग प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है । महोदय, हम सीवान जिले से आते हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी सीवान जिले से ही आते हैं । वित्तीय वर्ष 2015-16 में खासकर मेरे विधान सभा में दरौली आंदर प्रखंड और गुठनी प्रखंड में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति मिली और वह बना भी, लेकिन हस्तांतरित करने के पहले वह भवन धंस गया और हालत यह है कि हॉस्पीटल में तो एकाध मरीज मरते हैं लेकिन उन हॉस्पीटल में मरीज, मरीज के अभिभावक, डाक्टर, कंपाउंडर सब लोग मरेंगे । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि थोड़ा-सा अपने जिला के प्रति सहानुभूति रखते हुये इन दोनों प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य भवनों की जांच कराकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करें और उसका निर्माण करावें।

महोदय, उसी जिला में एक डाक्टर है वकिल सिंह चौहान । आज वह 16 वर्षों से एक ही प्रखंड में जमे हुये हैं । उनका स्थानान्तरण भी होता है, छुट्टी लेते हैं और फिर उसी ब्लॉक में ज्वाईन करते हैं । जनता का हमेशा इस पर विरोध होता है लेकिन सारे विरोध को दरकिनार करते हुये वे वहीं रहते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह किनके बल पर 16 वर्षों से स्थानान्तरण के बावजूद वहीं रहते हैं । इसलिये मैं उस संबंध में कहना चाहूंगा कि आप इसे दिखवा करके वैसे विवादित डाक्टर को तत्काल वहां से, जो 16 वर्षों से वहां हैं, किस नियम के तहत है, उनका स्थानान्तरण करने का काम करेंगे ।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि एक आशा कार्यकर्त्ता है । प्रसव से लेकर हर अभियान में महिलायें रात-दिन काम करती हैं सरकार भी महिला सशक्तिकरण की बात करती है । लेकिन वे महिलायें इस उम्मीद में 12 बजे रात में जब

फोन आता है तो वह जाती है लेकिन महोदय, उनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग को सुधारना है । वह आपकी निचली कड़ी है, आशा कार्यकर्त्ता मजबूत कड़ी है । उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उनका मानदेय कम से कम आज के मंहगाई के जामने में 18000/–रूपया करने का क ाम कीजिये, उनको स्थायी न करें लेकिन जीने के लिये उनका मानदेय 18 हजार रूपया जरूर करने का काम करें ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

दूसरी बात पंचायत स्तर पर आपने स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की अनुमति दी है । भवन के लिये जमीन भी परचेज किया जा चुका है । लेकिन आज तक आपका एक भी डाक्टर और कम्पाउंडर पंचायत स्तर के केन्द्रों पर नहीं जाते हैं । यहां तक की पी0एच0सी0 में भी वे नहीं रहते हैं । उनको जितनी सुविधाओं की जरूरत है, वह नहीं मिलती है और इसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है । गरीब लोग इसका खामियाजा भुगतते हैं । मेरे कॉस्टीच्युंसी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर है । अब छोटे–छोटे मामलों में भी उनको 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ।

टर्न–24/सत्येन्द्र/6–3–18

श्री सत्यदेव राम(क्रमशः): इसलिए हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टरों की बहाली हो, नियुक्ति हो और खासकर महिला डॉक्टरों की नियुक्ति की मैं मांग करता हूँ । पंचायत स्तर पर उन सेंटरों के निर्माण, उसके भवन के निर्माण की कार्रवाई आप करें, इसकी मांग मैं करता हूँ ।

अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिये । आप चारों तरफ देख रहे हैं, लाल बत्ती को देख नहीं रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, आपको देख रहे हैं तो लाल बत्ती क्या देखें, लाल बत्ती तो मेरा है ।

अध्यक्ष: आपका तो लाल झंडा है, बत्ती हमारा है ।

श्री सत्यदेव राम: लाल बत्ती भी, लाल झंडा भी है कुछ समय के लिए, आरा में सदर अस्पताल का आई0सी0यू0 बंद रहता है महोदय..

अध्यक्ष: एक मिनट में समाप्त कर दीजिये ।

श्री सत्यदेव राम: एक मिनट से और कम से खत्म करेंगे । वह कब खुलता है, जब भी0आई0पी0 लोग आते हैं तभी खुलता है और गरीब गुरबे की जरूरत पड़ती है तो आई0सी0यू0 नहीं खुलता है, उसको पटना की शरण लेनी पड़ती है इसलिए हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वे उस आई0सी0यू0 को परमानेंट खोलवाने का काम करेंगे और यह हम आपसे उम्मीद करते हैं । महोदय, दोण में एक रेफरल अस्पताल की स्वीकृति 1994 में ही मिली और उसका भवन भी बनकर तैयार है और वह काफी मजबूत भवन बना है, बने हुए उसको 20 वर्ष से ऊपर हो गया लेकिन महोदय हमने उसको जाकर के जांच किया और देखा तो वह काफी मजबूत है लेकिन वहां इलाज

नहीं हो रहा है । माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि उस रेफरल अस्पताल को तत्काल प्रभाव से चालू करवाकर के उस सुदूर इलाके के गरीब गुरबे लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाया जाय, इसकी जरूरत है । महोदय इसलिए आपने समय दिया इसके लिए मैं एक बात यही कहते हुए कि बातें स्वास्थ्य विभाग पर हुई लेकिन इसके अन्दर जो और विभाग है, उस विभाग पर सुनने वाले बड़े कम लोग हैं महोदय और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी नहीं है तो हमलोगों की बात कहां से दर्ज होगी ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं सुगमतापूर्वक समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है । आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाएं संचालित की जा रही है एवं राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है । विभागीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तृतीय अनुपूरक आगणन से उपबंध हेतु मांग संख्या-20 अन्तर्गत 25 विपत्र कोडों में कुल रू0 223,21,59,000/- मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । इनमें 23 विपत्र कोड स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से संबंधित है । इनके द्वारा कुल रू0 154,38,09,000/- मात्र की मांग उपस्थापित है । यह राशि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मियों के वेतनादि का भुगतान, संस्थान के भाड़े की गाड़ी का भुगतान, बकाये बिजली बिल का भुगतान, विभिन्न आवश्यक सामग्रियों के क्रय, संस्थान के किराये एवं महसूल कर का भुगतान, दवा का क्रय, संविदा/मानदेय पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान तथा छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/वजीफा हेतु आवश्यक है । शेष 02 विपत्र कोडों का संबंध वस्तुतः स्कीम मद से है । छपरा (सारण) तथा पूर्णियां में मेडिकल कॉलेज का निर्माण तथा केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले 09 ए0एन0एम0 संस्थानों के निर्माण हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशियां विमुक्त की जानी है । अतः इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित 02 विपत्र कोडों में रू0 68,82,60,000/- मात्र की आवश्यकता है । इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग के मांग संख्या-20 के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक के माध्यम से कुल रू0 223,21,59,000/- मात्र की राशि के उपबंध का प्रस्ताव सदन के पटल पर उपस्थापित है । स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार किया गया है तथा इसके अन्तर्गत रोगियों की जांच एवं दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था, विभिन्न मरीजों हेतु एम्बुलेंस की निःशुल्क व्यवस्था एवं आमजन हेतु निर्धारित राशि पर एम्बुलेंस की सहज व्यवस्था, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन इत्यादि किया जा रहा है । महोदय, विगत चार महीनों के अन्तर्गत बिहार के स्वास्थ्य

सेवाओं में 250 नये एम्बुलेंस की सेवा जोड़ी गयी है । विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के तहत् मरीजों एवं फ्रंट लाईन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है ताकि मरीजों की संख्या में वृद्धि हो और आमजन स्वस्थ रहे । फलतः संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम इत्यादि में दिन प्रतिदिन लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु अनुपात एवं शिशु मृत्यु दर के सूचकांक में गिरावट देखने को मिल रही है । पिछले वर्ष देश में सर्वाधिक गिरावट बिहार के अन्दर हुआ और जो शिशु मृत्यु दर है वह 38 पर पहुंच गया है । महोदय, नियमित टीकाकरण की प्रतिशतता में अभिवृद्धि हो रही है । अभी तक जो नियमित टीकाकरण राज्य के अन्दर होता था इस वर्ष हमलोगों ने इसका लक्ष्य 90 प्रतिशत से अधिक का रखा है और पूरे देश के अन्दर एक से चार राज्यों के अन्दर बिहार आये, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार एक से चार की श्रेणी में शामिल होगा टीकाकरण के मामले में । स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से विगत वर्षों में हमने कई प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मल रहा है । इसी का प्रतिफल है कि वर्ष 2004-06 में प्रतिवेदित शिशु मृत्यु दर जो 61 था वह आज घटकर वर्त्तमान में 38 हो गया है जिसकी चर्चा मैंने की अभी । बालिका शिशु मृत्यु दर, जो वर्ष 2015 में 50 था एस0आर0एस0 2016 के आंकड़ों के अनुसार घटकर 46 हो गया है । इसी प्रकार बालक शिशु मृत्यु दर जो वर्ष 2015 में 36 था एस0आर0एस0 2016 के आंकड़ों के अनुसार घटकर 31 हो गया है । नवजात शिशु मृत्यु दर जो वर्ष 2015 में 28 था, एस0आर0एस0 2016 के आंकड़ों के अनुसार घटकर वर्त्तमान में 27 हो गया है। पांच से कम उम्र के बच्चे का मृत्यु दर जो एस0आर0एस0 2015 के अनुसार 48 था, एस0आर0एस0 2016 के अनुसार घटकर वर्त्तमान में 43 हो गया है । महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ आंकड़े रखे थे मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने आंकड़े को थोड़ा ठीक कर लें । वर्त्तमान में राज्य में 40 विशेष नवजात देखभाल इकाई जिसे हम एस0एन0सी0यू0 कहते हैं, 40 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई, एन0बी0एस0यू0 एवं 533 नवजात देखभाल कक्ष एन0बी0सी0सी0 कार्यरत है जिसमें से बांका एवं पश्चिमी चम्पारण में 01-01 विशेष नवजात देखभाल इकाई एस0एन0सी0यू0 का अधिष्ठापन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ है । आगामी वित्तीय वर्ष में शिवहर एवं मुजफ्फरपुर में भी विशेष नवजात देखभाई इकाई एस0एन0सी0यू0 स्थापित कर लिया जायेगा । विशेष नवजात देखभाल इकाई एस0एन0सी0यू0 की सुविधा सदर अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालय के अतिरिक्त अनुमंडलीय अस्पतालों में भी दिये जाने का निर्णय लिया गया है । राज्य में बालिका शिशु मृत्यु दर बालक मृत्यु दर की अपेक्षा 15 प्वायंट अधिक है । बालिका मृत्यु दर को

कम करने के निमित्त बीमार नवजात बालिका को एस0एन0सी0यू0 में भर्त्ती करने के लिए आशा को उत्प्रेरित करने हेतु 500/–रू0 प्रोत्साहन राशि तथा माता को 200/–रू0 प्रतिदिन क्षतिपूर्त्ति राशि देने की योजना का सूत्रण किया जा चुका है ताकि यह जो बालिका मृत्यु दर है उसे गिरावट आये । नवजात बच्चों के स्वास्थ्य एवं देखभाल हेतु राज्य में कुल स्वीकृत 34 एस0एन0सी0यू0 में से 32 का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 02 एस0एन0सी0यू0 निर्माण के अंतिम चरण में है । 12 जिला अस्पतालों का निर्माण किया गया है तथा सभी....

श्री भोला यादवः अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप मंत्री जी अपनी बात जारी रखिये न ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः 12 जिला अस्पतालों का निर्माण किया गया है तथा सभी क्रियाशील है । सात नये अनुमंडलीय अस्पतालों के नवनिर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है । कुल 399 प्राथमिक ..

(इस बीच राजद एवं कांगेस के सदस्यगण सदन से बाहर चले गये)

सुन तो लीजिये भोला जी, अरे सुन तो लीजिये । कम से कम हम वाटर पार्क वाले मंत्री नहीं है भोला जी, वाटर पार्क वाले मंत्री नहीं है, जनता के बीच घुमने वाले मंत्री हैं। कुल 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 बेडेड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमित कर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है जिसमें 203 पूर्ण कर लिये गये हैं, 46 निर्माणाधीन है तथा शेष प्रक्रियाधीन है । (क्रमशः)

क्रमश :

टर्न–25/मधुप/06.03.2018

...क्रमशः ...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : वर्त्तमान में 23 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु निविदा निकाली जा चुकी है तथा 64 अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है ।

महोदय, चिकित्सा का का क्षेत्र काफी वृहत् है । चिकित्सा की आवश्यकता बच्चों के गर्भ में रहने से प्रारंभ होकर जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बनी रहती है । अतः बीमारी को दूर करने, गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने इत्यादि के उद्देश्य से विविध स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ।

उपलब्ध एवं उन्नत होते स्वास्थ्य सुविधाओं का ही यह परिणाम है कि बिहार का मातृ–मृत्यु अनुपात जो वर्ष 2004–06 में 312 था, एस0आर0एस0 2011–13 के आंकड़ों के अनुसार घटकर वर्त्तमान में 208 हो गया है ।

मातृ–मृत्य अनुपात को और कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला अस्पतालों एवं एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने के निमित्त विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ चिकित्सकों यथा 7 मेडिसीन, 12 मूर्छक, 23 प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं 16 शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में 29 मेडिसिन, 43 मूर्छक, 127 प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं 134 शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है ।

मातृ–मृत्य अनुपात को और कम करने के उद्देश्य से प्रसव पूर्व जाँच, प्रसूति महिलाओं का आवश्यकतानुसार सिजेरियन सेक्शन, ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज इकाई की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2018 तक कुल 12,47,103 गर्भवती महिलाओं का चार प्रसवपूर्व जाँच सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में किया गया है । इसी क्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह के 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क प्रसवपूर्व जाँच किया जा रहा है । साथ–ही, वैसे प्रथम रेफरल इकाई, जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, वहाँ वित्तीय वर्ष 2017–18 में निजी चिकित्सकों की सेवा लेकर C-Section करने के लिए जिलों को 10,000/– रूपये प्रति C-Section हेतु राशि उपलब्ध करायी गई है ।

मातृ–मृत्य अनुपात को और कम करने की दिशा में प्रथम चरण में सभी जिला अस्पताल के लेबर रूम को और सुदृढ़ एवं सुसज्जित करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि सभी लाभार्थी को आवश्यक सुविधाएँ सहज उपलब्ध करायी जा सके ।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 31 ब्लड स्टोरेज यूनिट को नया अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है । वर्त्तमान में कुल 45 ब्लड स्टोरेज यूनिट को क्रियाशील कर लिया गया है । शेष 30 ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना कर ली गई है, जिसे यथाशीघ्र क्रियान्वित कर लिया जायेगा । इस प्रकार बिहार में कुल 75 ब्लड स्टोरेज यूनिट शीघ्र क्रियाशील हो जायेगा । साथ–ही, इस 75 ब्लड स्टोरेज यूनिट के अतिरिक्त अन्य 40 ब्लड स्टोरेज यूनिट भी संस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

वर्त्तमान में राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय स्तर तक कुल 36 ब्लड बैंक संचालित हैं एवं 09 अतिरिक्त ब्लड बैंक को यथाशीघ्र क्रियाशील किये जाने की कार्रवाई की जा रही है ।

ममता की कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से ममता कार्यकर्त्ता को पूर्व में प्रति प्रसव मिलने वाले 100 रूपये मानदेय को बढ़ाकर 01 अप्रैल, 2016 से 300 रूपये किया गया है ।

राज्य में पूर्ण टीकाकरण का आच्छादन वर्ष 2005 CES(कॉवरेज इवैल्युएशन सर्वे) के अनुसार 18.6% था जो WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अनुसार वर्ष 2017 में बढ़कर 84% हो गया । इस आच्छादन को दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाकर 90% से अधिक किये जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं ।

पोलियो से दोहरी सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV का सूई) का शुभारम्भ किया गया है तथा नियमित टीकाकरण को और बेहतर करने एवं निमोनिया से बचाव तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के निमित्त राज्य के 17 जिलों में एक नया टीका PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) का दिनांक 19 जुलाई, 2017 से शुभारंभ कर टीकाकरण तालिका में शामिल किया गया है । माह जून, 2018 से राज्य के शेष 21 जिलों में भी PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) को नियमित टीकाकरण में सम्मिलित कर लिया जाएगा । इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियाँ की जा रही है ।

पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन बढ़ाने और शेष छूटे हुए बच्चों को प्रतिरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में तथा वर्ष 2017 में अप्रैल से जुलाई तक राज्य के 14 जिलों में 'मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम' का संचालन किया गया । इसी क्रम में पुनः नवम्बर, 2017 से फरवरी, 2018 तक चार चरणों में राज्य के 16 जिलों में 'सघन मिशन इन्द्रधनुष' कार्यक्रम चलाया गया । शेष जो हमारे 22 जिले बचेंगे, उन जिलों में भी मुख्यमंत्री विशेष सघन टीकाकरण अभियान कार्यक्रम हम अगले वित्तीय वर्ष में करने वाले हैं ।

प्रजनन दर में गिरावट लाने एवं उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने अर्थात् कम करने की दिशा में परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं । मिशन परिवार विकास पखवाड़ा, विश्व जनसंख्या दिवस, पुरूष नसबंदी दिवस, सास-बहु सम्मेलन, पुरूष भागीदारी दिवस इत्यादि का संचालन किया जा रहा है । दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को गोपालगंज जिला से गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा(MPA) एवं Centchroman (छाया)- साप्ताहिक गोली को परिवार नियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत "Basket of Choices" में शामिल कर लिया गया है एवं इसे स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक कार्यान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण (Post Partum Family Planning) अन्तर्गत सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं 38 जिलों के 537 स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसवोपरान्त कॉपर-टी की सुविधा प्रदान की जा रही है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के सभी 38 जिलों में माह दिसम्बर तक 1,19,681 लाभार्थियों को

प्रसवोपरान्त कॉपर-टी संस्थापित किया गया है एवं 2,39,136 परिवार नियोजन ऑपरेशन सम्पन्न किया गया है ।

सास-बहु सम्मेलन का आयोजन ए0एन0एम0 के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक पोषक क्षेत्र VHSND (ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण दिवस) के दिन किया जाना है । प्रत्येक सम्मेलन में कम से कम 10 सास-बहु की जोड़ी को शामिल किया जा रहा है ।

''मिशन परिवार विकास'' अन्तर्गत राज्य के 37 जिलों में महिला बंध्याकरण हेतु लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि 2000/- एवं पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि 3000/- कर दिया गया है । वहीं महिला बंध्याकरण हेतु उत्प्रेरक का उत्प्रेरण राशि 300/- एवं पुरूष नसबंदी हेतु उत्प्रेरक का उत्प्रेरण राशि 400/- प्रदान किया जा रहा है ।

सरकारी अस्पतालों में बाह्य कक्ष (OPD) में 33 प्रकार की एवं अंतर विभागीय कक्ष (IPD) में 112 प्रकार की दवाएँ देने का प्रावधान है, जिसके तहत् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक OPD में औसतन 29 प्रकार की एवं IPD में औसतन 90 प्रकार की दवाएँ तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में OPD में औसतन 57 प्रकार की एवं IPD में औसतन 102 प्रकार की दवाएँ उपलब्ध है । शेष प्रकार की दवाएँ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

सरकारी अस्पतालों के बाह्य रोगी कक्ष एवं अंर्तवासी रोगी कक्ष हेतु पूर्व से अधिसूचित आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) को संशोधित करते हुए नई सूची में कैंसर, किडनी, मधुमेह एवं जीवन रक्षक दवाओं को शामिल किया जा रहा है । इस प्रकार अब सरकारी अस्पतालों में लगभग 172 प्रकार की दवायें तथा 29 प्रकार के Medical Devices & Consumables रोगियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जा रहा है । राज्य में स्वास्थ्य उपकेन्द्र से लेकर चिकत्सा महाविद्यालय तक स्वास्थ्य संस्थानवार आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) तैयार की जा रही है ।

राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वृहत् प्राथमिक चिकित्सकीय सुविधा (Comprehensive Primary Health Care) उपलब्ध कराने हेतु Health and Wellness Centre (आरोग्य केन्द्र) के रूप में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को चिन्हित करने की लोकोपयोगी योजना बनायी गयी है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 200 Health & Wellness Centre प्रारंभ करने की योजना है । इसके तहत् उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक डायबिटिज, ब्लड प्रेशर, हाईपर टेंशन, कैंसर इत्यादि रोगों का स्क्रीनिंग किया जाना है, जो पहली बार प्रारंभ हो रहा है ।

वर्त्तमान में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर कार्यरत ए0एन0एम0 के अतिरिक्त एक जी0एन0एम0/आयुर्वेद चिकित्सक को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में

पदस्थापित करने हेतु छः महीने का ब्रिज पाठ्यक्रम IGNOU के माध्यम से प्रारंभ किया गया है । इसके तहत् सदर अस्पताल वैशाली एवं नालंदा में 06 जी0एन0एम0 एवं 46 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ है ।

स्वास्थ्य सुविधा जन-जन तक पहुँचाने के लिए विभिन्न स्तर के अस्पतालों का निर्माण कराने के साथ-साथ इन अस्पतालों के लिए चिकित्सक, परिचारिका, पारा मेडिकल एवं अन्य तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराना आवश्यक है । अतः इन कमियों को दूर करने के लिए सात निश्चय कार्यक्रम के तहत ''मिशन मोड'' पर 5 नये चिकित्सा महाविद्यालयों - मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय, महुआ(वैशाली) एवं आरा(भोजपुर) की स्थापना की जा रही है । केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत भी पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं छपरा(सारण) में नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है । इसके अतिरिक्त सात निश्चय कार्यक्रम के तहत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक जी0एन0एम0 ट्रेनिंग संस्थान एवं कम से कम एक पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में एक ए0एन0एम0 ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना किया जा रहा है एवं इन संस्थानों के भवन निर्माण की जिम्मेदारी BMSICL को दी गई है । राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल रू0 3401.01 करोड़ मात्र का व्यय आने की संभावना है । BMSICL द्वारा इन योजनाओं पर तीव्रता से कार्य करते हुए 44 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान, 19 जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान, 27 पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, 8 बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज की निविदा का निष्पादन किया जा चुका है एवं कुल 53 योजनाओं हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है । राज्य में 9 जिला अस्पतालों यथा अररिया, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी एवं वैशाली को Model Hospital के रूप में विकसित करने की योजना प्रक्रियाधीन है ।

...क्रमशः ...

टर्न-26/आजाद/06.03.2018

..... क्रमशः .....

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : आधारभूत संरचना, सुदृढ़ीकरण एवं आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं सहज उपलब्ध कराने के निमित्त दिनांक 10 अक्टूबर,2017 को राज्य में कुल 252 करोड़ की लागत से 63 योजनाओं का उद्घाटन एवं 614 करोड़ की लागत से 50 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न स्वास्थ्य उप केन्द्रों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई है । वैशाली में भगवानपुर, समस्तीपुर में मोरवा,

मुजफ्फरपुर में बोचहाँ, नालन्दा में इस्लामपुर, जहानाबाद में मखदुमपुर, पटना में पालीगंज, पटना में फतुहा एवं नालन्दा में इस्लामपुर ।

मुंगेर जिलान्तर्गत असरगंज प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैजलपुर के भवन निर्माण, समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चकसिकन्दर के भवन निर्माण, सिवान जिलान्तर्गत गोरियाकोठी प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जामो के जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटैया बाजार के भवन निर्माण, खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेघौना के भवन निर्माण, पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वीर के भवन निर्माण, गया जिलान्तर्गत गुरूआ प्रखंड स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र, भरौन्धा ग्राम में नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य, बांका जिलान्तर्गत रजौन प्रखंड स्थित मकरमडीह ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सरैया प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर महादेवा के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है ।

लखीसराय जिलान्तर्गत चानन प्रखंड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन के भवन निर्माण, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) जिलान्तर्गत बगहा–2 प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरा बाजार को रेफरल अस्पताल के रूप में उत्क्रमित कर तद्संबंधी भवन निर्माण, भोजपुर जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, शाहपुर एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, हसपुरा के पुराने भवन के स्थान पर तीस शैय्या वाले नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, नरकटियागंज के चहारदिवारी निर्माण कार्य, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया रेफरल अस्पताल के पुराने भवन के स्थान पर नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है ।

चिकित्सा संस्थानों को गुणवत्तायुक्त एवं सुदृढ़ करने की दिशा में प्रत्येक चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर वरीय पदाधिकारियों की निगरानी में नियंत्रण कक्ष गठित कर विभिन्न पालियों में चौबीसों घंटे सभी अस्पतालों का प्रतिदिन सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है एवं कर्त्तव्य पर अनुपस्थित पाये गये चिकित्सकों/कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है । इसी क्रम में 246 चिकित्सकों का एक दिन का वेतन काटे जाने के साथ–साथ असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर भी रोक लगायी गयी है ।

राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को उपकरणों से सुदृढ़ करने हेतु प्रथम चरण में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपकरणों का

ऑडिट कराने की योजना बनायी गयी है । राज्य के 534 प्रखंडों में न्यूनतम एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24X7 संचालन के लक्ष्य के विरूद्ध वर्तमान में 274 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 24X7 के मानक के अनुरूप संचालन किया जा रहा है और इसे बढ़ाकर 516 करने का प्रयास जारी है । इन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर छः शय्या की उपलब्धता, दो चिकित्सा पदाधिकारी, जिसमें एक एम0बी0बी0एस0 और एक आयुष तथा तीन पालियों में एक-एक एस0बी0ए0 प्रशिक्षित स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0 की प्रतिनियुक्ति, 24 घंटे बिजली, पानी, शौचालय एवं सामान्य प्रसव के लिए अन्य सारी सुविधा की उपलब्धता, निःशुल्क ओ0पी0डी0 की सुविधा, निःशुल्क दवा वितरण की सुविधा, निःशुल्क जाँच की सुविधा, प्रसवपूर्व सत्र के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल, सामान्य प्रसव की सुविधा, प्रसवोत्तर माता और नवजात की देखभाल, परिवार नियोजन तथा जटिल प्रसव हेतु रेफरल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जैसी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध है । राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत राज्य के 22 जिलों में 76 अति0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन करते हुए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ आमजन को उपलब्ध करायी जा रही है । माह जनवरी,2017 से दिसम्बर,2017 तक कुल 717595 मरीजों को ओ0पी0डी0 में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी है । गत वर्ष 2016 की तुलना में इस वर्ष ओ0पी0डी0 में लगभग 2.5 लाख मरीजों की वृद्धि प्रतिवेदित हुई है ।

अस्पतालों में साफ-सफाई की उन्नत व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक सेमी ऑटो एनालाईजर से पैथोलॉजी जाँच की सुविधा तथा जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में थ्री पार्ट ब्लड सेल काऊंटर से भी पैथोलॉजिकल जाँच की व्यवस्था की गई है । चिकित्सा संस्थानों में मरीजों को पहुँचने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए एम्बुलेन्स की सुविधा का सर्वव्यापीकरण किया जाना है । विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत मरीजों को निःशुल्क एवं कतिपय कार्यक्रमों अन्तर्गत निर्धारित दर पर टॉल फ्री नम्बर 102 पर रेफरल सेवाएँ भी आमजन को उपलब्ध करायी जा रही है । राज्य में पूर्व से संचालित 812 एम्बुलेन्स के अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में 250 नये एम्बुलेन्स को जिलों को उपलब्ध कराया गया है । अगले वित्तीय वर्ष में भी 150 और नये एम्बुलेन्स जून महीने तक लोगों की सेवा में उपलब्ध करा दिया जायेगा । साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के साथ एम0ओ0यू0 किया गया है एवं उनके द्वारा 40 एम्बुलेन्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

पूर्व से 49 शववाहन परिचालित है । इसके अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 03 अतिरिक्त शववाहन एवं अन्य पुराने पाँच मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में अतिरिक्त एक-एक तथा राज्य के 35 जिलों (अरवल, शिवहर एवं शेखपुरा

जिला को छोड़कर) में एक-एक अतिरिक्त शववाहन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

पूर्ण शराबबंदी कार्यक्रम अन्तर्गत सदर अस्पतालों एवं 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थापित पूर्णतः वातानुकूलित नशा मुक्ति केन्द्रों में एन0आई0एम0एच0ए0 एन0एस0, बंगलोर एवं एन0डी0डी0टी0सी0, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं परामर्शियों द्वारा सभी प्रकार के व्यसनों से मुक्ति हेतु उपचार की सुविधा उपलब्ध है । उपचार हेतु चिन्हित 28 प्रकार की दवाएँ निःशुल्क उपलब्ध हैं । रोगियों को इन नशा मुक्ति केन्द्रों में उपचार हेतु लाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध है । अर्न्तवासी रोगियों एवं उनके एक परिजन हेतु निःशुल्क पथ्य की व्यवस्था, रोगियों के आवासन हेतु वातानुकूलित वार्ड एवं उनके मनोरंजन हेतु अंत क्रीड़ा की सुविधा उपलब्ध है । इस कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 30.01.2018 तक के प्रतिवेदन के अनुसार नशा मुक्ति केन्द्रों में कुल 13577 लोगों का उपचार किया गया है, जिनमें से 2456 लोगों को इन केन्द्रों में भर्त्ती करा कर उपचार किया गया है ।

उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैलने वाली 6 वेक्टर जनित बीमारियाँ यथा कालाजार, मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी इंसेफलाईटिस/ए0ई0एस0 एवं फाइलेरिया चिन्ता का विषय है, जिसे दूर करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से बिहार में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

राज्य के 33 कालाजार प्रभावित जिलों के कुल 458 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से वर्ष 2011 में 212 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अति प्रभावित की श्रेणी में थे, जो अब घटकर मात्र 45 ही रह गयी है । वर्ष 2011 में जहां राज्य में 25222 मरीज प्रतिवेदित हुए थे, वहीं वर्ष 2017 में यह संख्या घटकर मात्र 4018 हो गई है । इस तरह विगत वर्षों में तुलनात्मक रूप से कालाजार प्रतिवेदित मरीजों की संख्या में 84 प्रतिशत की कमी आयी है । इसी तरह वर्ष 2011 में कालाजार से मृत्यु होने वाले मरीजों की संख्या जहां 76 थी, वह पिछले दो वर्षों से लगातार शून्य है ।

उपचारात्मक उपायों के अन्तर्गत माह जनवरी,2017 से राज्य के 21 जिलों के अत्यधिक प्रभावित 120 ग्रामों में कालाजार मित्रों द्वारा घर-घर कालाजार एवं पी0के0डी0एल0 रोगियों की खोज की गई । राज्य के 31 जिलों के सदर अस्पताल, 4 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं 53 चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कालाजार मरीजों का इलाज एकल खुराक एम्बिजोम से निःशुल्क किया जा रहा है ।

इसी प्रकार महोदय, मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया इन सारे चीजों की जॉच की व्यापक व्यवस्था की गई है एवं उनके उपचार की व्यवस्था की गई है ।

इसी प्रकार से राज्य में यक्ष्मा रोग के लिए यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम 736 केन्द्रों पर चलाये जा रहे हैं और यक्ष्मा पर नियंत्रण करने का निर्णय 2025 तक का है कि हमको पूर्ण रूप से नियंत्रित करना है तो लगातार स्वास्थ्य विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में लगी हुई है और हमें पूरा भरोसा है कि हम आगे आने वाले वर्षों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतर करने की जरूरत है, हम उसे अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे । स्वस्थ्य बिहार और समृद्ध बिहार बनायेंगे और हम इस दिशा में अग्रसर हैं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : कटौती वापसी का अनुरोध कर दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करता हूँ, जो सदन से बाहर चले गये हैं, लेकिन मेरी आवाज सुन रहे होंगे कहीं बैठ करके, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव, क्या अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अनुपस्थित)

माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

प्रश्न यह है कि :-

''इस शीर्षक की मांग 10रू0 से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि :-

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च,2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2017, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2017 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2017 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,23,21,59,000/- (दो अरब तेइस करोड़ एक्कीस लाख उनसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : अब शेष अनुदानों की मांगों का मुखबंद होगा ।

प्रश्न यह है कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2017, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2017 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2017 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

माँग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 2,20,85,41,000/- (दो अरब बीस करोड़ पचासी लाख एकतालिस हजार) रूपये,

माँग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 18,36,02,000/- (अठारह करोड़ छत्तीस लाख दो हजार) रूपये,

माँग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 1,31,16,45,000/- (एक अरब एकतीस करोड़ सोलह लाख पैंतालिस हजार) रूपये,

माँग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध 25,35,15,000/- (पचीस करोड़ पैंतीस लाख पन्द्रह हजार) रूपये,

माँग संख्या-07 निगरानी विभाग के संबंध 91,93,000/- (एकानवे लाख तिरानवे हजार) रूपये,

माँग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 11,46,39,000/- (ग्यारह करोड़ छियालिस लाख उनचालिस हजार) रूपये,

माँग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 1,62,16,000/- (एक करोड़ बासठ लाख सोलह हजार) रूपये,

माँग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 29,65,11,000/- (उनतीस करोड़ पैंसठ लाख ग्यारह हजार) रूपये,

माँग संख्या-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 91,02,000/- (एकानबे लाख दो हजार) रूपये,

माँग संख्या-19 पर्यावरण एवं वन विभाग के संबंध में 34,54,78,000/- (चौंतीस करोड़ चौवन लाख अटहत्तर हजार) रूपये,

माँग संख्या-21 शिक्षा विभाग के संबंध में 27,13,10,33,000/- (सत्ताइस अरब तेरह करोड़ दस लाख तैंतीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-22 गृह विभाग के संबंध में 63,43,52,000/- (तिरेसठ करोड़ तैंतालिस लाख बावन हजार) रूपये,

माँग संख्या-23 उद्योग विभाग के संबंध में 85,10,02,000/- (पचासी करोड़ दस लाख दो हजार) रूपये,

माँग संख्या-25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 34,00,00,000/- (चौंतीस करोड़) रूपये,

माँग संख्या-26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 4,34,99,000/- (चार करोड़ चौंतीस लाख निनानबे हजार) रूपये,

माँग संख्या-27 विधि विभाग के संबंध में 1,96,06,000/- (एक करोड़ छियानवे लाख छः हजार) रूपये,

माँग संख्या-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 8,00,00,000/- (आठ करोड़) रूपये,

माँग संख्या-31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 1,00,000/- (एक लाख) रूपये,

माँग संख्या-32 विधान मंडल के संबंध में 2,24,00,000/- (दो करोड़ चौबीस लाख) रूपये,

माँग संख्या-33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 36,50,000/- (छत्तीस लाख पचास हजार) रूपये,

माँग संख्या-35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 7,00,00,000/- (सात करोड़) रूपये,

माँग संख्या-37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 8,67,00,00,000/- (आठ अरब सड़सठ करोड़) रूपये,

माँग संख्या-39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 10,00,70,000/- (दस करोड़ सत्तर हजार) रूपये,

माँग संख्या-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 1,12,51,000/- (एक करोड़ बारह लाख एकावन हजार) रूपये,

माँग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 65,00,00,000/- (पैंसठ करोड़) रूपये,

माँग संख्या-43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 6,50,00,000/- (छः करोड़ पचास लाख) रूपये,

माँग संख्या-45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 7,00,000/- (सात लाख) रूपये,

माँग संख्या-46 पर्यटन विभाग के संबंध में 1,00,00,000/- (एक करोड़) रूपये,

माँग संख्या-47 परिवहन विभाग के संबंध में 5,18,62,000/- (पाँच करोड़ अठारह लाख बासठ हजार) रूपये,

माँग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 81,00,00,000/- (एकासी करोड़) रूपये,

माँग संख्या-49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 9,50,00,000/- (नौ करोड़ पचास लाख) रूपये

माँग संख्या-50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 98,08,27,000/- (अंठानवे करोड़ आठ लाख सताइस हजार) रूपये

माँग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 8,31,71,00,000/- (आठ अरब एकतीस करोड़ एकहत्तर लाख) रूपये,

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी-कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी-कार्य

बिहार विनियोग विधेयक,2018

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

''बिहार विनियोग विधेयक,2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

बिहार विनियोग विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूॅं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि:

बिहार विनियोग विधेयक, 2018 पर विचार हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

बिहार विनियोग विधेयक, 2018 पर विचार हो ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडश लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि–

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–28/शंभु/06.03.18

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विनियोग विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

बिहार विनियोग विधेयक, 2018 द्वारा कुल 5603.30 करोड़ रूपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है । विनियोजन राशि में 5593.81 करोड़

रूपये मतदेय एवं 9.50 लाख रूपये भारित थे । तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग विधेयक, 2018 का संचित विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सदन से अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक, 2018 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 6 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 20 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

सदस्यगण : भेज दिया जाय ।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 7 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....